Fourth Series, Vol.I, No. 3

Saturday, March 18, 1967
Phalguna 27, 1888 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(First Session)

4(7) 3
6 · 12 ... 82

(Vol. I contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Rs. 2. 00

CONTENTS

No. 3—Saturday, March 18, 1967/Phalguna 27, 1888 (Saka).

	COLUMNS
Members Sworn	79—80
President's Address—Laid on the Table	80—98
Obituary Reference	98—100
Re. Motions for Adjournment and No-Confidence Motion	100—20
Papers Laid on the Table	120—23
Demands for Supplementary Grants (General), 1966-67	123
Demands for Supplementary Grants (Goa, Daman and Diu), 1966-67	124
Demands for Supplementary Grants (Railways), 1966-67	124
President's Assent to Bills	124—25
Estimates Committee—	
Hundred and thirteenth Report	125—26
Synopsis of Proceedings of Plan Committees	126
Bills Introduced :	
(1) Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill	126—27
(2) Representation of the People (Amendment) Bill	127
(3) Land Acquisition (Amendment and Validation) Bill	128—29
Statements *Re.* Ordinances—	
(*i*) Representations of the People (Amendment) Ordinance	127
(*ii*) Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance	129
Statement Re. Termination of Emergency	
Shri Y.B. Chavan	129
Announcement Re. Panel of Chairmen	146
Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	130—46, 146—238
Shri A. B. Vajpayee	131—45
Shri Khadilkar	147—57
Shri Karni Singh	157—67
Shri Krishna Kumar Chatterjee	167—72
Shri P. K. Deo	172—75
Shri Shantilal Shah	175—83
Shri Chandra Jeet Yadav	183—93
Shri S. M. Banerjee	193—99
Shri Jagannath Prasad Pahadia	199—210
Shri Shiv Chandra Jha	210—11
Shri Bhola Nath Master	211—17
Shri D. N. Pataudia	218—22
Dr. Ram Manohar Lohia	222—31

2701 (Ai) LSD—1.

LOK SABHA

Saturday, March 18, 1967/Phalguna 27, 1888 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBERS SWORN

Mr. Speaker: Secretary may call the names of Members who have not yet been sworn....

Shri P. K. Deo (Kalahandi): On a point of order, Sir. Before you take up the List of Business, I would like to point out....

Mr. Speaker: This is oath taking of Members who have not done so.

Shrimati Girji Kumari (Shahdol)

Shri Bhajahari Mahato (Purulia)

Mr. Speaker: Secretary to lay on the Table a copy of the President's address to both Houses of Parliament assembled together on the 18th March, 1967.

Shri P. K. Deo: Sir, before you proceed to the next item, I would like to point out that today being the last working day of the week, the Minister for Parliamentary Affairs should have come out with his statement regarding the business for the next week. We are kept absolutely in the dark. We do not know what is going to take place next week. In today's List of Business, I do not find any reference regarding the business of the next week. We would like to know about that.

Shri K. Lakkappa (Tumkur): Sir, I have given notice of an adjournment motion in respect of Rajasthan....

Mr. Speaker: They will come later on.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): The list of business for the next week will be presented to the House. First we are going to take up the President's Address. The Vote of Thanks will be moved and adopted After that, the Vote on Account will be taken up.

12.13 hrs.

PRESIDENT'S ADDRESS

Secretary: I lay on the Table a copy of the President's address to both Houses of Parliament assembled together on the 18th March, 1967.

President's Address

संसद् सदस्यगण,

संसद् के दोनों सदनों के इस संयुक्त अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है। नवनिर्वाचित तथा पुनर्निर्वाचित सदस्यों को मैं अपनी बधाई देता हू और जो लोग हमारे बीच इस सभा मे अब नही हैं उनको अपनी शुभकामनाएं।

2. पहले ऐसा विचार था कि इस महीने तीसरी लोक सभा का अन्तिम अधिवेशन खासतौर पर लेखानुदान पास करने के लिए बुलाया जाय। लेकिन अधिकांश चुनाव-परिणाम घोषित होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों ने हमसे यह आग्रह किया कि इस मौके पर नई लोक सभा का ही अधिवेशन बलाया जाय जिसमें लेखानुदान पास किया जाय और दूसरी आवश्यक कार्रवाई हो। सरकार इस राय से सहमत

हुई और उनकी सलाह पर तीसरी मार्च को तीसरी लोकसभा भंग कर दी गई।

3. हमारे चौथे आम चुनाव ने फिर से हमारे लोकतंत्र की शक्ति और सजीवता का सबूत पेश किया है। पिछले सभी आम चुनावों से अधिक मतदाताओं ने इस बार के निर्वाचन में भाग लिया। मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई। चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हुआ, गोकि हिंसा और उपद्रव की कुछ दुःखद घटनाएं कहीं-कहीं हुई जिनकी सभी ओर से निन्दा की गई। आम चुनाव का काम जिस तरह पूरा हुआ उसके लिये मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। साथ साथ हमारी जनता भी बधाई की पात्र है, जिसने लोकतन्त्र और प्रतिनिधिक संस्थाओं के प्रति उत्साह, परिपक्वता और मर्यादा के साथ अपना विश्वास फिर से प्रकट किया।

4. स्वतंत्रता के बाद पहली बार केन्द्रीय सरकार से भिन्न राजनीतिक विचारधारा के दलों ने कई राज्यों में सरकार बनाई है। संघीय लोकतंत्रात्मक राज्य में यह कुछ अप्रत्याशित नहीं है। हमारे संविधान में संघ और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के नियमन के लिये उपबन्ध है। इसके अलावा पिछले कई वर्षों के दौरान संघ और राज्य तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सहयोग, सद्भाव और सामंजस्यपूर्ण संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिये कई संस्थाएं बन गई हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद्, जोनल काउन्सिलों और राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों के समय-समय पर होने वाले सम्मेलन इनके विशेष उदाहरण हैं।

5. संघ सरकार संविधान के उपबन्धों को अक्षरशः बिना किसी भेदभाव और सही माने में पालन करेगी तथा राष्ट्रीय समस्याओं को सहयोग से हल करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। हमें विश्वास है कि सभी राज्य इन संस्थाओं को कायम रखने में सहयोग देंगे तथा विचार-विमर्श द्वारा अपने और केन्द्र दोनों के हित में इनको अधिकाधिक उपयोगी बनायेंगे। देश की एकता और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, लोकतंत्रीय संस्थाओं को कायम रखना, आर्थिक विकास और जन-कल्याण हमारा परम उद्देश्य है और इस दिशा में संघ एवं राज्य को एक साथ मिलकर प्रयत्न करना है।

6. हमारी सरकार ने अभी अभी कार्यभार संभाला है। मतदाताओं की इच्छा के अनुकूल नीति और कार्यक्रम तैयार करने और आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करने में थोड़ा समय लगेगा। आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने चार प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं :—

उन्होंने संकल्प किया है कि 1971 के अन्त तक खाद्य के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहें ;

यह भी संकल्प किया है कि बुनियादी जरूरत की चीजों के मूल्य में अभिवृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने और कम से कम समय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाय ;

तीसरा संकल्प यह है कि आर्थिक विकास की गति को पर्याप्त तीव्र करें ताकि 1976 तक विदेशी सहायता लेने की आवश्यकता न रहे ;

और यह भी संकल्प किया है कि जन्म-दर प्रति हजार चालीस से घटकर यथाशीघ्र पच्चीस हो जाय, इसके लिए परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाय।

ये काम इतने बड़े और महत्वपूर्ण हैं कि सारी जनता और दलों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के बिना पूरे नहीं हो सकते। इन्हें प्राप्त करना सरकार का प्रधान उद्देश्य होगा।

7. खाद्य समस्या का सामना करने के लिए संकटकालीन स्थिति की तरह जो कदम उठाये गये हैं, उन्हें और जोरदार बनाया जायेगा। देश में अपनी पैदावार अथवा आयात से प्राप्त जो भी अनाज सुलभ है, हमें यह देखना है कि उनका वितरण समान रूप से हो। खाद्य के मामले में और कौन से काम करने हैं इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार जानने तथा उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पहले ही सम्पर्क किया है।

8 साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी। आगामी प्रत्येक वर्ष में हमारे खाद्य आयात की मात्रा कम होती जानी चाहिये। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार काफी रासायनिक खाद और अच्छे बीज सुलभ कराने और किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान देगी। लघु सिंचाई और कुआ को अधिक उपयोगी बनाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। सिंचाई की जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं और जिनके निर्माण का काम काफी आगे बढ़ चुका है उन को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किया जायेगे तथा सिंचाई के लिए देश में जो साधन सुलभ हैं उन के समुचित और सर्वाधिक उपयोग की व्यवस्था की जायेगी।

9. बारिश की कमी के कारण खेतों की पैदावार कम हुई और खासकर इसी वजह से पिछले दो वर्षों में कीमतें बढ़ती गईं। समय पर बारिश न होने की वजह से औद्योगिक उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा और औद्योगिक उत्पादन में कमी का एक कारण यह भी था कि विदेशी मुद्रा की कमी होने से आवश्यक कच्चा माल विदेश से मंगाया नहीं जा सका। केन्द्र द्वारा घाटे का बजट और राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) के कारण स्फीति दबाव अधिक बढ़ा। इस स्थिति का सामना करने के लिए कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के हर सम्भव उपाय किये जाने चाहियें। पिछले सालों में हमारी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो साधन और क्षमता पैदा की गई है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना है। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये। किफायतसारी और कुशलता में कोई विरोध नहीं है और सरकारी खर्च के हर क्षेत्र और हर दिशा में जितनी भी कटौती हो सकती हो की जानी चाहिये।

10 हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है हमारी अर्थ व्यवस्था को आत्म-निर्भर और अधिक विकास के योग्य बनाना। इस लक्ष्य को 1976 तक प्राप्त कर लेने के लिये चौथी योजना में उन उद्योग धन्धों पर विशेष ध्यान दिया जायगा जिन से निकट भविष्य में हमारा तेजी के साथ विकास हो, विशेषत ऐसे उद्योग धन्धे जो खेती और निर्यात में सहायक सिद्ध हों। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अधिक कार्यकुशलता पर सर्वाधिक जोर देना होगा। पहिली तीन योजनाओं में उद्योग धंधों के ऊपर काफी सरकारी पूंजी लगाई गई है और इस ख्याल से यह बहुत आवश्यक है कि इन उद्योग धंधों से ज्यादा मुनाफा हमें मिले ताकि विकास का काम आगे बढ़े। चौथी योजना की रूप-रेखा का मसौदा कुछ महीने पहले प्रकाशित किया गया था। सूखे के कारण जो असर देश पर पड़ा, कीमतों की जो प्रवृत्ति अभी है, देश और देश के बाहर से क्या अतिरिक्त साधन जुटाये जा सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख कर उस मसौदे का पुनरीक्षण किया जा रहा है और जल्दी ही राष्ट्रीय

विकास परिषद् के इस योजना के संबंध में विचार विमर्श करने के बाद संसद् के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

11. हमारी आबादी पचास करोड़ से आगे बढ़ गई है। यह एक खतरे की सूचक है और यदि हम इस ओर से लेपरवाह रहे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। राज्यों के साथ मिल कर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सभी स्तरों पर सुदृढ़ बनाया जायेगा।

12. आर्थिक कठिनाइयां तो एक कारण है, लेकिन इन के अलावा भी खासकर नौजवानों के बीच व्याप्त असतोष के कुछ और भी कारण हैं। आजादी के बाद जो एक नई पीढ़ी पैदा हुई है उस के मन में कुछ नये विचार और नई आकांक्षायें है। हमें उन की ओर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षा आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन के सम्बन्ध में राज्यों के विचार मांगे गये हैं और उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हमारी शिक्षा-पद्धति को पुनर्गठित करना जरूरी है। विश्वविद्यालय स्तर पर एक राष्ट्रीय सेवा की योजना के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

13 हमारी सभी योजनाओं और प्रायोजनाओं की सफलता हमारे प्रशासन की कुशलता और सत्य निष्ठा पर निर्भर करती है। काम में कुशलता लाने के लिए प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किये जायेंगे। योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। अभी जो नियंत्रण लागू किये गये है उन का पुनरीक्षण किया जायेगा और उन में से जो अनावश्यक होंगे उन्हें हटा दिया जायेगा तथा नियंत्रण को अधिक कुशल और उपयोगी बनाने के लिए उनको फिर से समंजित किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने वाली हैं।

14. सार्वजनिक जीवन और सरकारी कर्मचारियों के आचरण में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला हैं। इस विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है। सरकार आयोग की इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करती है कि ऊंचे राजनीतिक अथवा प्रशासनिक पदों के भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करने के लिए समुचित संस्था के गठन की आवश्यकता है। सरकार शीघ्र ही इस विषय में अपने प्रस्तावों को तय कर संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उन्होंने आयोग की उन सिफारिशों को जिनका राज्य सरकारों से सम्बन्ध है, उन्हें भेज दिया है।

15 श्रम के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। ग्रामीण श्रमिकों सहित सभी प्रकार के श्रमिकों के आजादी के बाद के काम और रहन-सहन के हालात का पुनरीक्षण कर यह आयोग समुचित सिफारिश करेगा। संघ की राजभाषा के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों को सांविधिक स्वीकृति देने के लिए शीघ्र ही संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। जो घोषणा पहिले की जा चुकी है उस को ध्यान में रखते हुए गोवध पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जायगी जैसा कि घोषित किया जा चुका है असम के नेताओं से हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए असम राज्य के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी। राज्य सरकारों से परामर्श कर वित्तीय वर्ष को बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

16. आज के संसार में कोई भी देश अलग नहीं रह सकता। भारत को विश्व-कुटुम्ब में अपना समुचित स्थान लेना है। सुरक्षा परिषद में हमारी सदस्यता से हम पर

कुछतर उत्तरदायित्व आ गया है, जिसे निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे।

17. भारत की विदेश नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। भारत ने जिस शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को प्रवर्तित करने के लिए जितना भी कार्य किया है, उसे अब दोनो गुटो के नेताओ ने स्वीकार कर लिया है। अमरीका और रूस दोनो देशों के साथ हमारे विशेष मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति सफल प्रमाणित हुई है। सरकार इस नीति को सुदृढ बनाने का हर सम्भव प्रयत्न करेगी और उसके भावात्मक सिद्धान्तो पर सकल्प के साथ चलती रहेगी।

18 आज मानवता के सामने दो सकट विद्यमान है। एक है निर्धन राष्ट्रो और धनी राष्ट्रो के बीच बढ़ती हुई खाई। दूसरा है कुछ देशो द्वारा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का अस्वीकार।

19 सरकार की विदेश नीति के दो उद्देश्य होगे। हमारे राष्ट्रीय हितो—आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा सम्बन्धी हितो—को आगे बढाना और अतर्राष्ट्रीय सहयोग का सवर्धन। इस उद्देश्य की प्राप्ति मे, हम ससार के अधिकाश देशो के साथ अधिकाधिक मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने और उन्हे कायम रखने मे सफल हुए है। भारत के अन्य एशियाई देशो के साथ सम्बन्ध सुदृढ करने का सरकार का विशेष प्रयत्न रहेगा।

20 यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मित्र देश बर्मा की सरकार के साथ हमारी सरकार, हमारी परम्परागत सीमा का औपचारिक सीमाकन सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर करने मे सफल हुई है।

21. सरकार वियतनाम सम्बन्धी अपनी नीति पर दृढ़ है, जिसका अनेक बार स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

22 पाकिस्तान सरकार और वहा के लोगों की मित्रता और सहयोग प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार हृदय से इच्छुक है। सामान्य हित रखने वाले हमारे इन दोनो देशो को जिस कटुता और सघर्ष ने कभी-कभी विलग कर दिया है उससे हमे सबसे अधिक दुख पहुचा है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सद्भावना, मित्रता और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हमारी सरकार भरसक प्रयत्न करेगी।

23 हम चीन के साथ भी शाति से रहना चाहते हैं। परन्तु चीन सरकार की आक्रामक कार्रवाई और गतिविधि और साथ ही उसके द्वारा शातिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना की अस्वीकृति—ये बडी कठिनाइया चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सुधारने मे बराबर बाधक बनी हुई हैं।

24 ससार के जिन मित्र राष्ट्रो, अतर्राष्ट्रीय सस्थाओ तथा अभिकरणो ने हमारे विकास कार्यक्रमो मे तथा हमारे खाद्यान्न सकट को दूर करने मे हमे अमूल्य सहायता प्रदान की है, उनके हम आभारी हैं।

25 विकासशील देश भी अपनी अर्थ-व्यवस्थाओ को, आपसी सहयोग द्वारा सुदृढ कर सकते हैं। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, सयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर और हमारे प्रधान मत्री—इन तीन गुटनिरपेक्ष देशो के नेताओ के त्रिपक्षीय सम्मेलन ने इस दिशा मे कार्य करने का आधार स्थापित कर दिया है।

26 हाल ही मे हमे एक और राष्ट्र के अध्यक्ष, अफगानिस्तान के महामान्य सम्राट, के स्वागत करने का अवसर मिला जिनके साथ हमारी बहुत ही मित्रतापूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई।

27 ससद् सदस्य, आज हमारे सम्मुख जो प्रश्न हैं उनमे से कुछ का मैंने सक्षेप में उल्लेख किया है। इन विषयो मे तथा अन्य

विषयों में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की पूरी जानकारी प्राप्त करने का आपको यथासम्भव अवसर मिलेगा। आपका वर्तमान सत्र छोटा ही होगा, जो कुछ अनिवार्य वित्तीय और बजट सम्बन्धी कार्यवाही तक सीमित रहेगा। आगे की कार्यवाही पर विचार करने के लिए आप फिर से शीघ्र ही मिलेंगे।

28. वर्तमान सत्र में निम्नलिखित अध्यादेशों का स्थान लेने के लिए विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे :—

(1) खनिज उत्पादन (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 1966,

(2) अत्यावश्यक वस्तुयें (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1966,

(3) भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्य) अध्यादेश, 1967, और

(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1967।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) स्थिरता विधेयक भी प्रस्तुत किया जायेगा।

29. 1967–68 के वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

30. यह हमारे लिए दुख का विषय है कि राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा। हमारी हार्दिक आशा है कि इस व्यवस्था को अधिक समय तक बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा। और शीघ्र ही उत्तरदायी सरकार फिर से स्थापित करना सम्भव होगा। 1967–68 के वित्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण भी आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

31. संसद सदस्य, मेरी शुभकामना कि आप अपने प्रयास में सफल हों।

[Members of Parliament,

It gives me great pleasure to welcome you to this joint session of the two Houses of Parliament. I offer my congratulations to the newly elected and re-elected Members and my good wishes to those no longer with us.

2 Earlier, it was intended that the third Lok Sabha should have a final session this month mainly to pass a Vote on Account. Shortly after most of the election results were announced, many Honourable Members from different political parties approached us with the request that it should be the new Lok Sabha which should meet at this juncture to pass the Vote on Account and to transact other essential business. The Government agreed with this view and, on their advice, the third Lok Sabha was dissolved on the 3rd of March.

3. Our fourth General Elections have once again demonstrated the vigour and vitality of our democracy. There was a larger turn-out of voters than on any previous occasion, as well as a substantial increase in the number of women who cast their votes. Despite a few unfortunate incidents of violence and disturbance which have been universally condemned, the elections were orderly and peaceful. The Chief Election Commissioner and his staff deserve our congratulations. So do the people, for the enthusiasm, maturity and dignity with which they have reaffirmed their faith in democracy and representative institutions.

4. For the first time since Independence, Governments of political complexions different from that of the Government at the Centre have been formed in several States. In a federal democratic polity, this is to be expected. Our Constitution has pro-

visions defining and regulating the relationship between the Union and the States and their mutual obligations. Further, over the years, we have developed certain institutions for promoting co-operation, understanding and harmonious relations between the Union and the States, and between one State and another. The National Development Council, the Zonal Councils and periodic conferences of Governors and Chief Ministers are the more conspicuous examples of this nature.

5. The Union Government will respect the constitutional provisions in letter and in spirit without any discrimination and endeavour to strengthen the arrangements for a co-operative approach to our national problems. We are sure that all States will extend their co-operation in preserving these institutions and in making their deliberations increasingly fruitful and beneficial both to the Union and to themselves. Strengthening the unity of the country, safeguarding its security, preserving democratic institutions, and promoting economic development and the well-being and happiness of all our people are the common objectives towards which the Union and the States must strive together.

6. Our Government have just taken office. While they will take a little time to place before you all the policies and programmes which they will pursue in accordance with the mandate of the electorate, they have already decided upon four major objectives in the economic sphere.

(1) They have resolved to end our dependence on food assistance from abroad by the end of 1971.

(2) They have resolved to do all that is possible to ensure that the rising trend in prices of the basic necessities of life is halted and conditions of stability achieved in the shortest possible time.

(3) They have resolved to attain and sustain an adequate rate of economic growth so as to eliminate the need for external economic assistance by 1976.

(4) And they have resolved to pursue the national programme of family planning with the objective of reducing the birth rate from forty per thousand to twenty-five per thousand as expeditiously as possible.

These tasks are of such magnitude that they can be accomplished only with the active support, participation and involvement of the people and the co-operation of all parties. To secure these will be one of Government's primary objectives.

7. The food situation will be dealt with on an emergency basis. The measures already set in motion to fight the drought will be strengthened. We have to ensure that the available foodgrains in the country, whether indigenous or imported, are distributed equitably Government are already in touch with State Governments seeking their views and their co-operation in regard to the further steps that have to be taken on the food front.

8 Simultaneously, Government intend, in collaboration with the States, to make every effort to augment agricultural production. Our food import requirements must be reduced in each successive year. Towards this end, Government will pay special attention to the adequate availability of fertilizers and improved seeds and to the credit needs of the farmer Greater emphasis will be placed on minor irrigation and energisation of wells. Efforts will be made to expedite the completion of major irrigation projects that are in an advanced stage of construction and to ensure the fullest utilization of the irrigation potential already created.

9. The upsurge in prices, particularly during the last two years, was primarily the result of the shortfall in

agricultural production due to the failure of the monsoons. Industrial production too was affected by the failure of the monsoons and the shortage of foreign exchange to import necessary raw materials. Deficit financing at the Centre and overdrafts by the State Governments on the Reserve Bank further aggravated the inflationary pressures. To deal with the situation, everything possible must be done to increase production in both agriculture and industry. The considerable potential and capacity in various sectors of the economy built during the past years must be more fully utilised. Simultaneously, a stricter financial discipline must be maintained. Economy is not inconsistent with efficiency and we must seek genuine economy in every field and in every sector of public expenditure.

10. Our Five-Year Plans have had the objective of making the economy self-reliant and capable of further development. To achieve this target by 1976, special attention will be paid in the Fourth Plan period to those industries which will contribute most to rapid development in the immediate future, particularly industries which will be helpful to our agriculture and exports. The greatest emphasis will have to be laid on higher efficiency in both the public and the private sectors. Substantial investments have been made in industry by the public sector in the first three Plans and it is important that these are now made to yield greater profits to sustain further development. The Draft Outline of the Fourth Plan was published some months ago. It is being reviewed in the light of adverse effects of the drought, the latest price trends, and the prospects of mobilising additional resources, internal and external, and it is proposed to take an early opportunity to discuss the Plan fully in the National Development Council and thereafter in Parliament.

11. Our population has crossed the five hundred million mark. This is a danger signal which we can ignore only at our peril. Family Planning programmes will be strengthened at all levels with the co-operation of the States.

12. Although economic difficulties are at the root of much of the prevailing discontent, other factors too have contributed to a sense of frustration, particularly among the young. The new generations which has grown up since Independence has new aspirations and new ideas. We must respond to them. The educational system needs re-shaping in the light of the recommendations of the Education Commission, on which we are awaiting the comments of the State Governments. A new scheme of national service at the University level is under active consideration.

13. The success of all our Plans and projects depends upon the efficiency and integrity of the administration. To ensure efficiency in performance, changes will be made in the administrative set-up. The Planning Commission will be re-organized. The working of controls will also be reviewed; those found unnecessary will be withdrawn and others re-adjusted as may be required to make them more purposeful and efficient. The Administrative Reforms Commission is expected to submit its recommendations on the re-organisation of the Central Government fairly soon.

14. Integrity and impartiality in public life, and in the conduct of the public servants, are the foundations of true democracy. The Administrative Reforms Commission has made an interim report bearing on this subject. Government agree, in principle, with the Commission's approach on the need for adequate and satisfactory institutional arrangements to deal with problems of corruption in high public office, whether political or administrative. They expect to finalize their proposals and place them before Parliament at an early date. They have already referred to the State Governments the recommendations of the Commission which concern them.

15. A National Commission on Labour has been set up under the chairmanship of Sri Gajendragadkar. The Commission will review and make appropriate recommendations on the whole field of the working and living conditions of labour of all categories, including rural labour, since Independence. Legislation to give statutory recognition to the assurances given in regard to the official language of the Union will be shortly introduced in Parliament. A high-level committee will be set up to examine the question of a ban on cow slaughter in terms of the announcement already made. A committee will also be set up, as announced, to examine further the proposal for the re-organisation of the State of Assam in the light of the discussions held with the leaders of Assam. The question of changing the financial year will be considered in consultation with the State Governments.

16. In a shrinking world, no country can remain isolated. India has a role to play in the counsels of the world. Our membership of the Security Council casts on us an onerous responsibility which we shall do our best to discharge.

17 The foreign policy of India has stood the test of time. The concept of peaceful co-existence, which India had done so much to sponser, is now accepted by the leaders of the two groups. With both the United States and the Soviet Union we have the friendliest of relations. Our policy of non-alignment stands vindicated. Government will do everything possible to strengthen non-alignment and pursue the positive aspects of this policy with vigour and determination.

18. There are two dangers which confront humanity today. One is the widening gulf between the poor nations and the rich nations. The other is the rejection of the principle of peaceful co-existence by some countries.

19. Government's foreign policy will serve the twin objectives of furthering our national interests—economic, political and strategic—and of promoting international co-operation. Towards this end, we have succeeded in building up and maintaining the friendliest of relations with most countries of the world. It will be Government's special endeavour to strengthen India's relations with our Asian neighbours.

20. It is a matter of deep gratification that our Government have been able to sign an Agreement with the Government of Burma about the formal delineation and demarcation of our traditional boundary with that friendly country.

21 Government adhere to their policy regarding Vietnam which has been enunciated on several occasions.

22 Government most sincerely desire the friendship and co-operation of the Government and people of Pakistan Nothing has distressed us more then, the bitterness and conflict which have sometimes divided our two countries which have many common interests Government will make every effort to achieve a relationship of the fullest understanding, goodwill and amity with Pakistan.

23. With China too we would like to live in peace. But the aggressive acts and postures of the People's Republic of China coupled with their rejection of the concept of peaceful co-existence, continue to be the major obstacles to an improvement of our relations with China.

24. We are grateful to friendly nations of the world, as well as to inernational institutions and agencies, who have given us valuable assistance in our development programmes as well as in meeting our food crisis

25. Developing countries can also strengthen their economies through mutual co-operation. The Tripartite Meeting between the leaders of three non-aligned countries, President Tito of Yugoslavia, President Nasser of the United Arab Republic and our Prime Minister, has laid the foundations of such an approach.

26. Another Head of State whom we had the pleasure of welcoming amidst us recently was His Majesty the King of Afghanistan, with whom we have had very friendly and cordial talks.

27. Members of Parliament, I have briefly touched upon some of the issues that confront us today. You will have an opportunity to get a fuller picture of the Government's policies and programmes in these and other matters in due course. Your present session will be a short one, confined to the transaction of certain essential financial and budgetary business. You will be meeting again shortly to consider further business.

28. Bills will be introduced in the current session to replace:—

(1) The Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Amendment Ordinance, 1966;

(2) The Essential Commodities (Second Amendment) Ordinance, 1966;

(3) The Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance, 1967; and

(4) The Representation of the Peop e (Amendment) Ordinance, 1967.

The Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill will also be introduced.

29. A statement of the estimated receipts and expenditu e o. the Government of India for the financial year 1967-68 will be laid before you

30. It is a matter of distress to us that President's rule had to be introduced in Rajasthan. It is our earnest hope that it will not be necessary to continue this arrangement for long and that it will be found possible early to restore responsible government.

A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of Rajasthan for the financial year 1967-68 will also be laid before you.

I wish you success in your endeavours.

12.13½ hrs.

OBITUARY REFERENCES

Mr. Speaker: I have to inform the House of the sad demise of eight of our friends, namely Shri Sadashiv Govind Barve, Dr. Gopichand Bhargava, Dr. Lanka Sundaram, Shri Radhelal Vyas, Shri Algu Rai Shastri, Shri Sadath Ali Khan, Shrimati V. Vimla Devi and Shri Apurva Kumar Chanda.

Shri Sadashiv Govind Barve was elected to this House from the Bombay North East Constituency of Maharashtra. He passed away at New Delhi on the 6th March, 1967 at the age of 52.

Dr. Gopichand Bhargava was a Member of the Constituent Assembly of India during the year 1946. He passed away at Chandigarh on the 26th December, 1966 at the age of 78.

Dr. Lanka Sundaram was a Member of the First Lok Sabha during the years 1952—57. He passed away at New Delhi on the 8th January, 1967 at the age of 63

Shri Radhelal Vyas was a Member of the Provisional Parliament, First Lok Sabha, Second Lok Sabha and Third Lok Sabha during the years 1960—67. He passed away at Indore on the 13th January, 1967, at the age of 59.

Shri Algu Rai Shastri was a Member of the Constituent Assembly of India, Provisional Parliament and First Lok Sabha during the years 1946—57. He passed away at Lucknow on the 12th February, 1967, at the age of 67.

Shri Sadath Ali Khan was a Member of the First Lok Sabha and second Lok Sabha during the years 1962—61. He passed away at New Delhi on the 23rd February, 1967, at the age of 51.

Shrimati V. Vimla Devi was a Member of the Third Lok Sabha during the years 1962—66. She passed away at Eluru on the 1st March, 1967, at the age of 43.

Shri Apurva Kumar Chanda was a Member of the Central Legislative Assembly of India during the years 1937—39. He passed away at New Delhi on the 14th March, 1967 at the age of 74.

We deeply mourn the loss of these friends and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved families

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi):

Mr. Speaker, Sir, I rise to pay homage to the eight distinguished Parliamentarians who have passed away during this brief inter-session period. You have yourself named them

Dr. Gopichand Bhargava was a veteran freedom fighter He was a disciple in Lala Lajpat Rai and worked epecially in Harijan and Khadi movements Shri Algu Rai Shastri was also closely connected with the freedom movement and his interest lay in working for backward agricultural communities. Both of them functioned in many other fields as well

Dr. Lanka Sundaram and Shri Sadath Ali Khan were able Parliamentarians. Dr. Lanka Sundaram was a noted economist and writer. Shri Sadath Ali Khan was a writer, a journalist and a peot. Both of them made a mark in diplomacy as well.

Shri Radhelal Vyas was with us in the Third Lok Sabha, as indeed was Shrimati V. Vimla Devi. She was energetic and able and you yourself will remember how she often enlivened the proceedings of the House.

In the olden days, Shri Radhelal Vyas was specially interested in Constitutional reform in the Princely States. He was a member of many important committees of the House.

Shri Sadashiv Govind Barve was a Member of the Planning Commission. He was with us till very lately. We were hoping for much greater service to this House from him and his association with us in many fields of activity. He was an economist and an able administrator.

Shri Apurva Kumar Chanda was greately admired as a teacher who moulded the minds and tastes of two generations in Bengal.

We mourn the loss of these distinguished Parliamentarians I should like to express our sentiments of deepest grief and sympathy and we would request you, Sir, to convey these sentiments on our behalf to the bereaved families.

Shri M. R. Masani (Rajkot): May I, on behalf of those who occupy these benches, associate myself with what you, Sir, and the Leader of the House have said? Apart from being members of this House and colleagues of ours at one stage or another, several of them were personal friends of many of us and we join you, Sir, and the whole House in mourning their loss.

Mr Speaker: The House may stand in silence for a short while.

(The Members stood in silence for a short while).

12.20 hrs.

RE MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND NO-CONFIDENCE MOTION

Shri P. K. Deo (Kalahandi): We had submitted and we had given notice of serveral motions for adjournment. We thought that this would be the most appropriate time to censure the Government by tabling a motion for adjournment on the Rajasthan issue.

This Rajasthan question has been agitating the mind of everybody. It is a matter of grave concern to everybody in this country and in this House. The way the Central Gov-

[Shri P. K. Deo]

ernment have acted. the first act that the Central Government did was to impose President's rule in Rajasthan.

Mr. Speaker: He need not go into the merits of it. I think he wants to discuss the Rajasthan question. Is that not so? But I am told that there has been a convention that normally on the day of President's Address the House would not take up any adjournment motion etc. That has been so on the past occasions. I think we could take it up on the 20th.

Shri P. K. Deo: But things have changed, and things have been moving so fast.. We do not like to precipitate a wrong thing, but we do not want this thing to continue. It has been a matter of grave concern. Government have acted in a very parochial way. The report that the State Governor has submitted is without giving a chance to the Opposition to from a government there, and the Central Government have acted on the report of the State Governor; their first act was to sabotage democracy and the democratic institutions so healthily built up in this country.

So, I think that there could not be a more appropriate occasion to censure Government by tabling an adjournment motion so as to highlight this thing in the debate. I hope you will give permission so that the House could be adjourned and we could take up this discussion at about three o'clock.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : कार्य सूची के बारे में मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आप ने जिस परम्परा की बात की उस पर अगर हम चलेंगे, और आज कोई स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेगें तो इस के क्या नतीजे होगें, इस ओर मैं जरा आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आज जिस परम्परा की बात चल रही है वह जो हमारे नियम हैं और अध्यक्ष द्वारा जो निर्देश जारी किये गये हैं, उन के बिल्कुल खिलाफ जाती है। मैं आप का ध्यान नियम 31 (1) की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में कार्य सूची के बारे में कहा गया है :

"31(1) A list of business for the day shall be prepared by the Secretary, and a copy thereof shall be made available for the use of every member.

(2) Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any sitting without the permission of the Speaker.".

यह नियम हमारी कार्य सूची के सम्बन्ध में है। अब कार्य सूची मे हम लोग जो कागजात वगैरह सदन के टेबल पर रखते हैं उस के पहले कुछ विषय आ जाते है जिस की सूची आप के द्वारा जो निर्देश जारी किये गये हैं उन मे दी गई है। मैं आप के द्वारा जारी किये गये निर्देश न० 2 की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

निर्देश न० 2 इस प्रकार है :

"(a) *Business before the House*

2 Unless the Speaker otherwise directs the relative precedence of the classes of business before the House specified below shall be in the following order, namely:—

(i) Oath or affirmation...

वह हो गया।

(ii) Obituary reference....

वह भी हो गया।

(iii) Questions..

आज कोई प्रश्न की सूची है ही नही।

'(iv) Calling-attention-notice;

इसके आगे लिखा है :

"(v) Leave to move motions for adjournment of the business of the House....".

आगे अविश्वास के प्रस्ताव का उल्लेख भी इस में हैं। जहां तक मुझे जानकारी है कई स्थगन प्रस्ताव आप के पास पहुंचे है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बारे मे। 13 तारीख को दस बजे के पहले कुछ प्रस्ताव मैं ने दिये। इसी प्रकार एक अविश्वास प्रस्ताव जन संघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भी दिया गया है। मेरे और हमारे दल के जो उपनेता हैं श्री रवि राय, उन के नाम से भी एक अविश्वास प्रस्ताव पहुंचा है।

एक माननीय सदस्य . कैसे मालूम हुआ ?

श्री मधु लिमये : मैं ने और श्री रवि राय ने मिल कर दिया है तो क्या मालूम नही होगा ? अजीब आदमी है।

मैं अर्ज कर रहा था कि आप अगर आज इस परम्परा पर जाते हैं और नियमो को तोड देते है तो क्या नतीजा होगा ? केवल यह निर्देश नं० 2 नही टूटेगा बल्कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जिस अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी गई है, जिस का हम सभी लोग विरोधी दल के, मेरा ख्याल है, समर्थन करने जा रहे हैं, कम से कम मेरा दल तो जरूर करने जा रहा है, वह गैरकानूनी हो जायेगा। कैसे, यह मैं आप को बतलाना हूं।

अब आप ऐडजर्नमेंट सम्बन्धी नियम 57 देखिये। वह इस प्रकार है.

"Notice of an adjournment motion shall be given before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made to each of the following....".

13 तारीख से ले कर अब तक जो स्थगन प्रस्ताव दिये गये हैं उन पर विचार करने के लिये यह पहली बैठक है। अगर इस बैठक मे वह नहीं आयेंगे तो मेरी समझ में नही आता है कि उन को बाद में कैसे लिया जायेगा।

हमें अविश्वास प्रस्ताव को भी पहले खत्म करना होगा। आप 19. खये। वह इस प्रकार है :

"A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made subject to the following restrictions, namely:—

"(a) leave to make the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon .."

कार्य सूची लेने के पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेना चाहिये।

अब आगे आप (बी) देखिये।

(बी) इस प्रकार है :

"(b) the member asking for leave shall before the commencement of the sitting for that day, give to the Secretary a written notice of the motion which he proposes to move".

आज की बैठक के पूर्व जितने प्रस्ताव आये हैं, उनके आने के तत्काल बाद जो बैठक होगी, यानी यह आज की बैठक, उसमे उनका ले लेना लाजिमी है। आप 20 तारीख को कैसे इनके प्रस्ताव को लेगे ? इसलिये आप से मेरी प्रार्थना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिये जो दिन आप को मुकर्रर करना हो आप करे। लेकिन ध्यान आकर्षण, स्थगन और अविश्वास इन तीनो प्रस्तावो को आप आज ले लीजिये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I fully appreciate what you have said, that we have developed a convention that on the day when the President addresses Parliament and the Address is later laid on the Table of the House, these adjournment motions and call attention notices are not normally allowed. But since we have made many changes—I have seen yesterday also we did not stick to convention—and since these two matters, specially the

[Shri S. M. Banerjee]

Rajasthan affairs, where there has been a rape of democracy—the Governor should have resigned by this time, but he has not and there has been a rape of democracy—and since the Government in my State of Uttar Pradesh is born out of corruption and political bribery.....

Mr. Speaker: Without going into details, he may make his point.

Shri S. M. Banerjee: These matters are so important that I would request you in all humility—and the rules do not forbid such a course; there is not a single rule under which this can be disallowed—that these adjournment motions, no-confidence motions and even call attention notices be allowed today. We have to take a decision on these today.

Dr. Karni Singh (Bikaner): The question of President's rule being imposed on Rajasthan is a matter of urgent public importance. Some of us, Members of the Opposition, particularly I as a Member from Rajasthan, have tabled adjourment motions on the subject. We feel that the situation in the State is such that it warrants that this House takes the matter into consideration at once. As you know, a very grave injustice has been done to the people of Rajasthan, in spite of the fact that the Opposition there claims to have a majority and a physical inspection was given by the Opposition Members, the Government has badly advisod the President to continue that President's rule I feel that the matter is of such importance that we cannot postpone it any more I would submit very respectfully that the adjournment motion be admitted today.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): My submission is this, that it is not right to say that today we are not transacting any business. If, after the President's Address is delivered, we are not transacting any business, we may not press this point, but fortunately for us we find on the Order Paper all sorts of business—Papers to be laid followed by a long series of items, Supplementary Demands for Grants, President's Assent to Bills, Report of the Estimates Committee, Introduction of Bills etc. As normally as on any other day the proceedings of the House are going on. Therefore, to say that today we are not transacting any business is wrong, and I submit that since we are transacting business, it is all the more necessary to put this no-confidence motion on the agenda, and we should dispose of it before we go to the next item of laying papers on the Table.

Shri Hem Barua (Mangaldai): I have submitted an adjournment motion on the imposition of President's rule in Rajasthan.

To say that no business is going to be transacted today after President's Address is not very correct in the sense that the List of Business contains a lot of items submitted by the Government, Treasury Benches That shows that the normal routine is carried out in the House. And in that context, may I submit that this adjournment motion be taken into consideration because of this particular aspect of things? In Rajasthan a peculiar situation has developed, and it pains me to say that leonine violence has been let loose by the Government on the people there because the people wanted to assert their democratic rights Therefore, I hope and trust that you, in your wisdom, will allow this to be discussed in the House.

Shri K. Lakkappa (Tumkur): Conceding that there is a convention that on the day of President's address no business is transacted, here is a case where an adjournment motion has been tabled by the hon. Member to discuss the crisis arising because of the Governor of Rajasthan not respecting the Constitution. The President, the Speaker and every Member of this House, of course, have to show due respect to the Constitution, but the Governor has not respect the Constitution, and there is a constitutional

crisis. Therefore, under the circumstances, the motion may be allowed, and you may kindly allow the House to discuss this.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta North East): I wish to submit to you that I have a recollection that on a similar occasion in the past we did have adjournment motions and their admissibility discussed in the House, even though there was not on that occasion such a fairly substantial list of items as in today's List. Therefore, I feel that even purely technically speaking, there is nothing to prevent you giving your ruling in regard to the admissibility of the adjournment motion, and I wish to add that since it is common knowledge that in Rajasthan something has happened which has gone against the grain of parliamentary democracy or any kind of decent political life altogether, and since there is all over the country very grave feelings roused in regard to this matter, and in Rajasthan itself an almost impossible situation has been created, it is up to us as Members of Parliament as our first duty to take up a discussion of this matter, and that is why the proceedings of today require to be interrupted, in order to have a discussion.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): We have no objection to this.

Mr. Speaker: That is what I thought I have received a motion of no-confidence given by Mr. Vajpayee and Mr. Limaye, and in the letter he wrote some that on the 20th he would like to take it up.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): On a point of personal explanation.

Mr. Speaker: I was saying I have no objection, and the Treasury Benches also have no objection, and they wou'd like to take it up as quickly as possible. Therefore, taking up the question of adjournment motion is not necessary, when we are having a no-confidence motion on the same issue. It is not necessary that we should take up the no-confidence motion immediately, but I am in the hands of the House. I would like to hear Members on that issue. In view of the fact that we are going to take up the no-confidence motion, I thought the adjournment motions might be taken up later, not that they are going to be thrown out.

Shri P. K. Deo: In this connection, I submit that the no-confidence motion would be a general motion because the motion could not be anything beyond "The House has no-confidence in the Council of Ministers'....

Mr. Speaker: It is particularly on the Rajasthan issue.

Shri P K. Deo: The motion would be a general motion. In debating the adjournment motion we would like to highlight the situation which has recently developed in Rajasthan and we would like to confine our various observations to that issue. In the no-confidence motion, Members have scope to speak on any subject. Since we would like to restrict our observations to this item only, the adjournment motion should get precedence over the no-confidence motion.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अभी आपने जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसको अपनी स्वीकृति दी है और जो स्थगन के प्रस्ताव हैं उन्हें भी आपने एक तरह से स्वीकृति दी है । अब प्रश्न रह जाता है कि कौन सी चीज पहले ली जाए । जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा है जो स्थगन प्रस्ताव है वह जरूरी है और उसे पहले लेना चाहिये ।

मैं तीसरी एक चीज कहना चाहता हूं । ध्यानाकर्षण के जो प्रस्ताव हैं उनको तो आप को तत्काल ही ले लेना चाहिये । स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास का प्रस्ताव तो आएगा ही और मैं चाहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाए लेकिन ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव को तो अभी ले लेना चाहिये । मैं अनुरोध करता हूं कि उनकी आप अभी इजाजत दें ।

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली सदर) : मैंने भी एक नो-कान्फिडेंस मोशन आपके पास

[श्री कंवरलाल गुप्त]

भेजा है जिसमें एक ही कारण मैंने दिया है कि राष्ट्रपति राज राजस्थान में लागू किया गया है । केवल इसी कारण के लिए मैंने नो-कान्फिडेंस मोशन भेजा है । मैं आपके साथ सहमत हूं कि जो केवल एक कारण से नो-कान्फिडेंस मोशन आपके पास आया है, उसमें दूसरी बातों की चर्चा नहीं हो सकती है । इसलिए एडजर्नमेंट मोशन को छोड़ करके पहले आपको नो-कान्फिडेंस मोशन लेना चाहिये ।

Shri Dattatraya Kunte (Kolaba): Sir, I am grateful to the Chair for having agreed to take up the no-confidence motion.

Having agreed to take it up for discussion, it becomes necessary that the adjournment motion should get priority because it relates to an urgent matter of public importance not a question of general confidence or otherwise in the Treasury Benches. The motion of no-confidence can cover wider fields. If you consider that this is a matter of urgent public importance, I do not see why you should not agree to have this motion discussed first.

Mr. Speaker: I would request Mr. Vajpayee to move his no-confidence motion now. Before he does so, I may inform the House that I have received two notices of motions of no-confidence in the Council of Ministers under Rule 198. The first notice is by Shri Vajpayee. The motion as slightly edited is as follows:

> "That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers."

The reasons given are: imposition of the President's rule in Rajasthan and suspension of State legislature. May I request those Members who are in favour of leave being granted to this motion to rise in their places?

Shri S. M. Banerjee: What is the second one? (*Interruption*).

Mr. Speaker: This is the first one. If it is not accepted, let us see.

श्री मधु लिमये : हम पहले प्रस्ताव का समर्थन तो करेंगे ही, लेकिन आप दूसरा प्रस्ताव भी पढ़ दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो सकता है ? अगर आवश्यकता होगी, तो दूसरा प्रस्ताव बाद में लिया जा सकता है ।

May I request those Members who are in favour of leave being granted to this motion, to rise in their places?—Since it is more than 50, leave is granted.

Shri P. K. Deo: What is the fate of the Adjournment Motion?

Mr. Speaker: May I request the Prime Minister to indicate the time when it could be taken up?

Shrimati Indira Gandhi: We can start immediately, as far as we are concerned, and it may be concluded today.

Mr. Speaker: The Prime Minister, the Treasury Benches, they are prepared to take up this motion immediately, now, after the papers are laid on the Table. If the Mover also is agreeable, it can be taken up immediately after the papers are laid on the Table.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रधान मन्त्री ने कहा है कि वह अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार हैं । लेकिन अभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो बात चल रही थी, उसके सम्बन्ध में आपने कोई निर्णय नहीं दिया है । मेरा अनुरोध है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव को अलग से लिया जाये, क्योंकि उसका एक निश्चित विषय है और उसका अविश्वास प्रस्ताव से बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है । अविश्वास प्रस्ताव बहुत व्यापक होते हैं और उनमें सब विषय आ जाते हैं, जबकि स्थगन प्रस्ताव किसी एक खास मुद्दे के बारे में होते हैं । इसलिए आप उसके लिए अलग से समय निर्धारित करें ।

Shri S. M. Banerjee: I have gone through this no-confidence motion tabled by my hon. friend Shri Vajpayee. It is very specific. It is only about the rape of democracy in Rajasthan (*Interruption*). My Adjournment Motion, or the Adjournment Motion of many other Members and the Calling Attention Notices relate to many other issues. I request that since this no-confidence motion does not cover all those items, the Adjournment Motions and the Calling Attention Notices which relate to a serious situation in Uttar Pradesh and other things should be kept in abeyance. If your ruling now is that all those things, all those discussions may not take place in this issue—this no-confidence motion is specific—then you should see that those things should be kept in abeyance.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): I want to understand one thing After all these points have been raised, I do not think the motion of no-confidence binds us to one thing or limits our discussion only to a particular thing mentioned in regard to the motion. That is not needed according to the rules: but for convenience it is always mentioned. So, I do not think you will rule out any discussion of any other topic which the Members want to raise during the course of the no-confidence motion. It is all right that the Prime Minister has come forward to take up this motion immediately, but I would like to know how much time are you going to devote for this motion: two days or three days.

An hon. Member: One day. (*Interruption*).

Mr. Speaker: One day is enough. After all, you have another opportunity of discussing it during the debate on the President's Address.

Shri Surendranath Dwivedy: That is another matter; I do not think one day will be sufficient.

Shri Nambiar: It will not be sufficient.

Some hon. Members: Two days.

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, अभी आप ने नो-कान्फ़िडेंस मोशन पर बहस की इजाज़त दे दी है। इस वक्त मुल्क के सामने एक बहुत ही अहम मसला है—उत्तर प्रदेश का मसला—और वह आप की फ़ौरी तवज्जह चाहता है, लेकिन वह मसला इस नो-कान्फ़िडेंस मोशन में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में कानून को तोड़ कर मिनिस्ट्री बनाई गई है, जिस के नतीजे में चीज़ों की प्राइसिज खास तौर से गल्ले की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और लोगों की जानें ख़तरे में पड़ गई है। वह मसला फ़ौरी तौर पर हाउस के सामने आना चाहिए। इस लिए मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ़ पुरानी परम्पराओं की ही पाबन्दी न करें, बल्कि वक्त और ज़रूरत के मुताबिक उन परम्पराओं को डेवेलप करते हुए इस बारे में एडजर्नमेंट मोशन को एलाऊ करें, ताकि यू० पी० के लाखों इन्सानों की ज़िन्दगी का मसला इस हाउस के सामने रखा जा सके।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : इस समय सदन मे जो चर्चा हो रही है, वह प्रधानतः श्री वाजपयी के नो-कान्फ़िडेंस मोशन और कुछ एडजर्नमेंट मोशन के बारे में है। दोनों मोशन्ज करीब करीब एक ही हैं। नो-कान्फिडेंस मोशन और एडजर्नमेंट मोशन दोनों राजस्थान की समस्या पर आधारित हैं।

एक माननीय सदस्य : दोनों में बहुत फ़र्क है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : दोनों एक ही समस्या पर आधारित हैं। इस लिए एक ही विषय पर दो मर्तबा बहस कराने से सदन का समय व्यर्थ जायेगा। माननीय सदस्य नो-कान्फ़िडेंस मोशन के दौरान यू० पी० आदि अन्य बातों की चर्चा भी कर सकते हैं। वह मोशन खास तौर से राजस्थान के बारे में ही है। इस लिए मैं समझता हूं कि इस समय नो-

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

कान्फ़िडेंस मोशन के अलावा किसी दूसरी मोशन पर बहस को गुंजायश नहीं है।

श्री क० ना० तिवारी : (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, आप के प्रेडेसेसर के सामने भी नो कान्फ़िडेंस मोशन और एडजर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में इस तरह के सवाल आते रहे हैं। मुझे याद है कि उन्होंने रूलिंग दिया था कि जब नो-कान्फिडेंस मोशन एडमिट हो जाता है, तो उस में सब बातें डिस्कस हो जाती हैं और उस समय एडजर्नमेंट मोशन के रूप में उन्हीं बातों को दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। इस लिए मेरा ख़याल है कि इस समय हाउस में केवल नो-कान्फिडेंस मोशन को ही लिया जाना चाहिए।

Shri P. Ramamurti (Madurai): Now that you have allowed this no-confidence motion to be taken up immediately, although the mover confines himself to the specific question of Rajasthan it does not preclude other members who may participate in the debate from raising any other question. Therefore, to say that this no-confidence motion will have to be finished within the course of this day is certainly something which will be doing injustice to us. We will not be able to bring forward many other issues on the basis of which we want to express our want of confidence I would, therefore, request you to rule that the time-limit is extended, that this debate will not be over by today, but we will discuss it on the 20th also fully.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, नो-कान्फ़िडेंस मोशन के मुक़ाबले में एडजर्नमेंट मोशन एक माइनर चीज है और नो-कान्फिडेंस मोशन के लिये जाने के बाद और कोई चीज नहीं ली जाती है। जब लीडर ने नो-कान्फ़िडेंस मोशन पर अभी डिस्कशन करना एक्सेप्ट कर लिया है, तो किसी अन्य मोशन को ले कर हाउस का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे मित्र ने अभी उत्तर प्रदेश का ज़िक किया। मैं समझता हूं कि वहां पर एक फ़र्म गवर्नमेंट है।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान की स्थिति पर विचार करने के लिए एक दिन का समय दिया है। पेपर्स को पढ़ने से मालूम होता है कि वहां पर तीस आदमी मरे हैं। अगर एक आदमी के लिए, जिस की जान गई है, एक घंटे का समय भी दिया जाये, तो इस मोशन के लिए तीस घंटे से कम का समय नहीं होना चाहिए, यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री अब्दुल गनी (गुड़गांव) : स्पीकर साहब, जब राजस्थान एसेम्बली में अपोजीशन की अक्सरियत को दुनिया ने देख लिया है, तो मुझे खुशी होगी कि अगर जम्हूरियत के सब से बड़े अलमबरदार की बेटी, श्रीमती इंदिरा गांधी, दिल्ली से अपनी ग़लती का एहसास करें। (Interruption). आनरेबल मैम्बर्ज कुछ भी कहें, ग़लती तो ग़लती ही रहेगी। (Interruption). मैं अर्ज कर रहा था कि.... (Interruption). ये गांधीजी के चेले हैं, जो दूसरे को अपनी बात नहीं कहने देते हैं! इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ..... (व्यवधान) .... अगर यह इस तरह ही शोर करते रहेंगे तो इनकी निन्दा नहीं होगी गान्धी जी की होगी कि उन के चेले ऐसे निकम्मे हैं, ऐसे नालायक हैं, ऐसे बेसब्रे हैं कि वह सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि एक अपोजीशन का मेम्बर क्या कहता है। इन को शर्म आनी चाहिए।

मैं इन को हरा कर आया हूं। लेफ्ट और राइट को हराकर आया हूं। मैं यहां आया हूं तो मैं यह अर्ज कर रहा था...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आनरेबिल मेम्बर अब बैठें।

श्री अब्दुल गनी : मिस्टर स्पीकर, सर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इन्दिरा गांधी जी आप के काम को आसान कर सकती है, वह यह कह दे कि राजस्थान मे मिनिस्ट्री बनेगी तो यह झगड़ा खत्म होता है। ऐडजर्नमेंट मोशन खत्म होता है। कोई ऐडजर्नमेंट मोशन की बात नहीं रहती है। मुझे उम्मीद है कि वह निहायत दिलेरी के साथ अपने पिता की बात को कायम रखेंगी।

श्री जार्ज फर्नांडिज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोडा परेशान हूं, जो यहां पर आप का फैसला हुआ और जो बहस चली, मैं तो पहली बार लोक सभा में आया हूं.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था, बीच में यह लोग रोकने की कोशिश किए इसलिए उन की तरफ देखना पड़ा जो एक पुस्तक हैंड बुक फार मेम्बर्स हमे दी गई है उस के पृष्ठ 34 पर लिखा है :

"The following procedure will be observed in the disposal of notices of adjournment motions:—

(1) Where the Speaker is satisfied *prima facie* that the matter proposed to be discussed is in order under the rules, he will give his consent to the moving of the motion and at the appropriate time call upon the member concerned....."

अध्यक्ष महोदय, इस में तो साफ लिखा है कि अगर इस मामले मे आप के मन मे बात जंची कि जो नोटिस आपके सामने है ऐडजर्नमेंट मोशन का वह महत्वपूर्ण मामला है तो उस पर आप बहस करने की इजाजत देंगे। लेकिन मैं जरा परेशान हूं, जो बहस चली उस से ऐसा लगता है कि आप के मन में कुछ दुविधा है। अध्यक्ष महोदय, जब आपने वोट आफ नो-कान्फिडेंस, अविश्वास के प्रस्ताव की इजाजत दी तो वह देते वक्त आपने उस की कुछ चर्चा भी की और उस में मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान के मसले को आप बहुत महत्व देते हैं। उस को महत्व देते हैं इसलिए अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस की इजाजत आप ने दे दी। तो अगर आप उस को महत्व का मानते हैं और मुझे तो ऐसा ही दिखाई देता है सदन मे कि सभी लोग उसे महत्व दे रहे हैं तो इन नियमो के अनुसार जिन का उल्लेख मधु लिमये जी ने किया और जो इस हैंडबुक की बात मैंने पेश की है और जो आप प्रस्ताव को बहस के लिए लेने वाले हैं इन सब बातो को देखते हुए आपका यह फर्ज हो जाता है कि ऐडजर्नमेंट मोशन को तत्काल बहस के लिए रखने की इजाजत दे।

Shri Khadilkar (Khed): Mr. Speaker, Sir, it is not only what is written in the Handbook of Procedure that we adopt here, but the conventions and past rulings form part of the procedure of this House. Unfortunately, today you have shown indulgence.....

An hon. Member: Fortunately.

Shri Khadilkar: My hon friends, Shri Masani and Shri Hiren Mukerjee would bear me out that on no occasion after the President's Address.....

Mr. Speaker: We have already taken a decision about that.

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): He is challenging your ruling.

Shri Khadilkar: That is why I am referring to the past rulings, because on this point there is already a ruling given by the former Speaker that when the President's Address is to be debated upon, if the points raised in the Adjournment Motion or Motion of No-Confidence were to be covered in the discussion on the President's Address, Members were never allowed to move them. But another important matter is, so far as Motion of No-Confidence is concerned, it has a wide field to cover. It can cover

[Shri Khadilkar]

any issue. Then, in such a situation, once you have admitted it, there is no scope for another adjournment motion, or any other motion, because it has a wider amplitude to cover.

Shri Krishna Kumar Chatterjee (Howrah): I am deeply amazed, being a new member, to listen to the controversy that has ensued. Our Prime Minister has conceded the opposition demand that the No-Confidence motion should be taken up immediately. After that, the question of bringing in an adjournment motion first, does not arise. It is the difference between Tweedledum and Tweedledee. In the discussion of the no-confidence motion, certainly Rajasthan and Uttar Pradesh will come in very large proportion; comments will be made about Rajasthan and Uttar Pradesh. Nobody is debarred from making comments on other points also. Therefore, I think this controversy should stop. We shall immediately take up the question of No-Confidence, leaving aside the question of adjournment. We on this side have already conceded that the No-Confidence motion should be debated on immediately.

Shri N. C. Chatterjee: Sir, now you have given your ruling, we must abide by it. The language of the motion is "that the House expresses its lack of confidence in the Council of Ministers". It is very widely put and there is no limi ation. Therefore, we can indulge in all sorts of arguments and contentions to justify the motion. It is not done in an irresponsible manner. It is a very important subject, because we maintain that it is a fraud on the Constitution of India, a severe blow to democracy, which must be ended immediately. I only plead with you and with the House that one day is absolutely inadequate for dealing with this important subject. I am pleading that you should allot at least two days so that the whole thing may be debated.

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): Two questions have been raised here. Whether the time for discussion should be one day or more, that is for you to decide, in consultation with the Leader. Regarding the question whether apart from the No-Confidence motion, the adjournment motion should also be discussed, the matter is perhaps covered by a rule which says that no member shall anticipate the discussion on a matter which has been previously appointed for consideration. The rule fur her says "in determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time". The motion was read out, and the ground given was the Rajasthan matter.

An hon. Member: But not UP on which there is a separate motion.

Shri Govinda Menon: It was contended here that other matters also may be discussed during the discussion. That being so, it will be a wastage of time and a breach of the rule laid down, to have another motion, in anticipation of the motion which has been taken up for discussion. Again, the question is, the No-Confidence motion having been admitted, whether the business of the House should not be broken and the adjournment motion taken up. On that I find the view of the House, in the last Lok Sabha, was that once a No-Confidence motion is admitted, no other business should be taken up and the No-Confidence motion should have precedence. On that matter friends in this House fought very vigorously last time and, finally, the Prime Minister conceded it. That being so, I should think that it would be wrong to have any other matter taken up for discussion before the No-Confidence motion is disposed of.

Mr. Speaker: Instead of spending any further time on this discussion, why not we take up the No-Confidence motion? About the time to be allotted for it, let us continue the discussion and, if necessary, we can find some time for it on the next working day also.

13 hrs.

Shri Surendranath Dwivedy: From your ruling it is not clear whether the adjournment motions . . .

Mr. Speaker: I have not given any ruling.

Shri Surendranath Dwivedy: But you have said that this will get precedence and immediately discussion would start. But what happens to the notices of adjournment motion that have been given?

Mr. Speaker: Adjournment motions and calling-attention notices, all that we will consider and see how many of them cover the same Rajasthan issue and how many different issues. We will examine them separately, unconnected with this. No ruling is given now.

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने यह मान लिया है कि यह डिस्कशन दो दिन चलेगा ?

श्री मधु लिमये : ध्यान दिलाने के प्रस्तावों का क्या होगा, उनका न अविश्वास प्रस्ताव से और न स्थगन प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : उसको 20 ता० को लेंगे, आज तो नो-कान्फीडेन्स मोशन को इमिडियेटली लेंगे।

Shri Nambiar: Unless we know the time fixed for this, we will not be in a position to aportion the time that each Member or group will get. Those who get the opportunity to speak earlier will absorb all this time. Without fixing the time it will not be possible to regulate the discussion even.

Mr. Speaker: I have said that on Monday also this will be continued. It is clear, it will be for two days.

13.02 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ORDINANCES UNDER THE PROVISIONS OF ARTICLE 123(2) (A) OF THE CONSTITUTION

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances, under provisions of article 123(2)(a) of the Constitution:—

(1) The Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Amendment Ordinance, 1966 (No. 12 of 1966) promulgated by the President on the 15th December, 1966. [*Placed in Library. See No.* LT.—2/67].

(2) The Essential Commodities (Second Amendment) Ordinance, 1966 (No. 13 of 1966) promulgated by the President on the 23rd December, 1966. [*Placed in Library. See No.* LT-3/67].

(3) The Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance; 1967 (No. 1 of 1967) promulgated by the President on the 20th January, 1967 [*Placed in Library. See No.* LT-4/67].

(4) The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1967 (No. 2 of 1967) promulgated by the President on the 28th February, 1967. [*Placed in Library. See* No. LT-5/67].

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT AND RE. PRESIDENT'S RULE IN KERALA

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951:—

(i) G.S.R. 1779 published in Gazette of India dated the 26th November, 1966, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(ii) G.S.R. 1832 published in Gazette of India dated the 3rd December, 1966, making certain amendments to Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.

(iii) The All India Services (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1878 in Gazette of of India dated the 10th December, 1966.

(iv) G.S.R. 1822 published in Gazette of India dated the 10th December, 1966, containing corrigendum to G.S.R. 1270 published in the Gazette of India dated the 20th August, 1966.

(v) The All India Services (Provident Fund) 2nd Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1913, in Gazette of India dated the 17th December, 1966.

(vi) The All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) (2nd Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1915 in Gazette of India dated the 17th December, 1966.

(vii) The All India Services Computation of Pensions (Amendment) Regulation, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1916 in Gazette of India dated the 17th December, 1966.

(viii) G.S.R. 1956 published in Gazette of India dated the 24th December, 1966, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(ix) G.S.R. 1957 published in Gazette of India dated the 24th December, 1966, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(x) The All India Services (Compensatory Allowance) Amendment Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 1958 in Gazette of India dated the 24th December, 1966.

(xi) G.S.R. 1990 published in Gazette of India dated the 31st December, 1966, making certain amendments to schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(xii) G.S.R. 1992 published in Gazette of India dated the 31st December, 1966, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(xiii) G.S.R. 1993 published in Gazette of India dated the 31st December, 1966, making certain amendments to Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.

(xiv) The All India Services (Travelling Allowance) (Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. G.S.R. 66 in Gazette of India dated the 21st January, 1967.

(xv) G.S.R. 69 published in Gazette of India dated the 21st January, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(xvi) G.S.R. 70 published in Gazette of India dated the 21st January, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(xvii) G.S.R. 136 published in Gazette of India dated the 4th February, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(xviii) G.S.R. 137 published in Gazette of India dated the 4th February, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954. [*Placed in Library. See No.* LT-6/67].

(2) A copy of Proclamation issued by the President on the 6th March, 1967, revoking the Proclamation issued by the Vice-President, discharging the functions of the President, on the 24th March 1965, in relation to the State of Kerala, published in Notification No. G.S.R. 298 in Gazette of India dated the 6th March 1967, under clause (3) of article 356 of the Constitution [*Placed in Library. See* No. LT-7/67].

12.05 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1966-67

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai): I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 1966-67.

12.05½ hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GOA, DAMAN AND DIU), 1966-67

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Shri Morarji Desai): I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of Union Territory of Goa, Daman and Diu for 1966-67.

12.05½ hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1966-67

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (Railways) for 1966-67.

12.05½ hrs.

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I lay on the Table following ten Bills passed by the Houses of Parliament during the Sixteenth Session of Third Lok Sabha and assented to by the President:

(1) The Kerala Appropriation (No. 3) Bill, 1966.

(2) The Kerala Appropriation (No. 4) Bill, 1966.

(3) The Kerala Appropriation (No. 5) Bill, 1966.

(4) The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1966.

(5) The Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1966.

(6) The Appropriation (No. 4) Bill, 1966.

(7) The Appropriation (No. 5) Bill, 1966.

(8) The Produce Cess (Amendment) Bill, 1966.

(9) The Indian Tariff (Second Amendment) Bill, 1966.

(10) The Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Bill, 1966.

[Secretary]

Sir, I lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary of Rajya Sabha, of the following fourteen Bills passed by the Houses of Parliament during the Sixteenth Session of Third Lok Sabha and assented to by the President:

(1) The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Bill, 1966.

(2) The Companies (Amendment) Bill, 1966.

(3) The Delhi Municipal Corporation (Validation of Electricity Tax) Bill, 1966.

(4) The Metal Corporation of India (Acquisition of Uundertaking) Bill, 1966.

(5) The Companies (Second Amendment) Bill, 1966.

(6) The Constitution (Nineteenth Amendment) Bill, 1966.

(7) The Goa, Daman and Diu (Opinion Poll) Bill, 1966.

(8) The Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 1966.

(9) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1966.

(10) The Preventive Detention (Continuance) Bill, 1966.

(11) The Banaras Hindu University (Amendment) Bill, 1966.

(12) The Jawaharlal Nehru University Bill, 1966.

(13) The Constitution (Twentieth Amendment) Bill, 1966.

(14) The Seeds Bill, 1966.

12.06 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

HUNDRED AND THIRTEENTH REPORT

Secretary: The Chairman, Estimates Committee (1966-67) presented to the Speaker on the 2nd March, 1967, the Hundred and Thirteenth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Forty-Eighth Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on the erstwhile Ministry of International Trade in terms of Clause (1) of Speaker's Direction No. 71A.

In terms of clause (6) of Speaker's Direction No. 71A, I lay a copy of the Report on the Table of the House.

12.06½ hrs.

SYNOPSES OF PROCEEDINGS OF PLAN COMMITTEES

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the Synopses of Proceedings of the following Committees of Third Lok Sabha on the Draft Fourth Five Year Plan:—

(1) Committee 'A' (Policy, Resources and Allocations);

(2) Committee 'C' (Agriculture and Rural Economy);

(3) Committee 'D' (Social Services); and

(4) Committee 'E' (Education and Manpower Planning).

12.06½ hrs.

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL*

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to continue the Armed Forces (Special Powers) Regulation, 1958, for a further period.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to continue the Armed Forces (Special Powers) Regulations, 1958, for a further period."

The motion was adopted.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 18th March, 1967.

Shri M. C. Chagla: Sir, I introduce the Bill.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I want to know the special reasons for the Minister of External Affairs introducing this Bill. Why has the Defence Minister not done it? Are we still continuing with the practice that Nagaland and other things come under the External Affairs Minister? He should explain that.

Shri K. Manoharan (Madras North): Sir, can we not take up the No-Confidence Motion on Monday?

Mr. Speaker: No.

13.07½ hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL*

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

Shri Govinda Menon: Sir, I introduce the Bill.

13.08 hrs.

STATEMENT *RE.* ORDINANCE

(i) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ORDINANCE

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1967, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

13.08½ hrs.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL*

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894, and to validate certain acquisitions of land under the said Act.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, this Bill has been circulated to us. This is based on a judgment of the Supreme Court. I would have liked that along with this Bill that judgement of the Supreme Court should have been circulated to us to understand the whole thing. I would only request the hon. Minister to circulate the copy of the Supreme Court judgement which has necessitated this Bill for the validation of certain land acquisitions.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi): It is a very relevant point. The copy of the Supreme Court judgement should be circulated.

Mr. Speaker: What is the view of the Minister?

Shri Annasahib Shinde: The Supreme Court judgement is a public document. It is available to hon. Members.

Mr. Speaker: A few copies may be kept here also.

Shri Nambiar: Shri Shukla has presented a long list of notifications....

Mr. Speaker: We cannot go back now.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 18th March, 1967.

[Mr. Speaker]

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894, and to validate certain acquisitions of land under the said Act."

The motion was adopted.

Shri Annasahib Shinde: I introduce the Bill.

13.10 hrs.

STATEMENT RE. ORDINANCE —contd.

(ii) Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): I lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance, 1967, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

13.10½ hrs.

STATEMENT RE. TERMINATION OF EMERGENCY

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): Mr. Speaker, Sir, I beg to make the following statement.

The Proclamation of Emergency which was made in the wake of Chinese aggression has been reviewed. In actual practice, Government have already restricted the exercise of Emergency powers to certain areas only. It is their intention to seek necessary constitutional authority to terminate with effect from 1st July, 1967 the state of emergency in all parts of the country except where abnormal conditions still persist.

13. 11 hrs.

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

Mr. Speaker: We shall now take up the No-Confidence Motion.

Shri Vajpayee.

Shri A. K. Gopalan (Kasergod): Are we having the discussion just now?

Mr. Speaker: All of us agreed.

Shri A. K. Gopalan: May I make a submission? It is true, as the Law Minister said, that when the No-Confidence Motion is moved, it must be taken up first before any other subject is taken up. But as far as today's order paper is concerned, the work is over and there is no other business left. We can take it up on Monday.

Mr. Speaker: All of us agreed, including the Prime Minister, that it could be taken up today. Let us take it up today and it will also be discussed on Monday.

Shri A. K. Gopalan: I suggest that the No-Confidence Motion may be moved today; the mover is there and he can speak. As far as others are concerned, they may speak on Monday. We know it only now; we did not know it before. You may give an opportunity to the mover of the No-Confidence Motion. He can move it and then it can be taken up on Monday.

Dr. Karni Singh (Bikaner): I wish to make a submission that since this No-Confidence Motion is primarily fixed on the President's rule in Rajasthan, the Members of the Opposition from Rajasthan who have given adjournment motions should be given time earlier.

Shri Hem Barua (Mangaldai): The convention is that after the normal routine business is transacted in the House, the House is adjourned.

Mr. Speaker: All of us agreed that it could be taken up now.

An hon'ble Member: We can have it on Monday and Tuesday.

Some hon. Members: No.

Mr. Speaker: It will be discussed on Monday also. Shri Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास के अभाव को प्रकट करता है।

महोदय, यह प्रस्ताव मैं खेद के साथ उपस्थित कर रहा हूं। कुछ ही दिन पहले यह मंत्रिमंडल गठित हुआ है। आज राष्ट्रपति महोदय ने मंत्रिमंडल की नीतियों पर प्रकाश डाला है। स्पष्ट है कि इस अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मंत्रिमंडल की अन्य नीतियों के स्पष्ट होने से पहले ही दे दी गई थी और इसीलिए प्रस्ताव के साथ जो मैं ने कारण दिये हैं उनमें केवल राजस्थान की स्थिति का संकेत किया है। नये मंत्रिमंडल ने और उसके सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद जो पहला काम किया वह था राजस्थान में संविधान पर आघात करना। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। विधान सभा को स्थगित कर दिया गया। आम चुनाव के द्वारा राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार का शासन चाहती थी उसे उस शासन से वंचित कर दिया गया। राजस्थान में जो कुछ हुआ है वह लोकतन्त्र की हत्या है। चुनाव के द्वारा जनता ने जो मत दिया है उस की खुली अवहेलना है। वस्तुतः यह बड़ी दुखदायी बात है कि जब देश के अन्य प्रदेशों में ठीक ढंग से मंत्रिमंडल बने हैं तो केवल राजस्थान और उसके साथ उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल के निर्माण में न तो संविधान के अक्षर की न उसकी भावना का खयाल किया गया है और न चुनाव के परिणामों द्वारा जनता ने जो अपना निर्णय दिया है उसका समादर किया गया।

राजस्थान में जो कुछ हुआ उसकी देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। राजनीतिक दलों को छोड़ कर जिन व्यक्तियों का राजनीति के साथ सम्बन्ध नहीं है, जो स्वतन्त्रचेता हैं, आवश्यकता पड़ने पर जो विरोधियों की भी आलोचना करते हैं, उन्होंने भी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन घोषित करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय की कटु निन्दा की है। समाचारपत्रों ने एक स्वर से इस कदम को अलोकतान्त्रिक और अवैधानिक ठहराया। प्रश्न यह है कि आम चुनावों के तुरन्त बाद जब जनता ने कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ कर शान्तिपूर्ण तरीके से मतदान में उत्साह से भाग लेकर लोकतन्त्र में अपनी गहरी आस्था प्रकट की है तो राजस्थान में इस प्रकार का दुखदायी दृश्य क्यों उपस्थित हुआ? गड़बड़ वहां से शुरू हुई जब राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया कि विधान सभा में जो सबसे बड़ा दल है उसे वे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण देंगे। प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल बनाने के लिए किसी दल को निमंत्रण देते समय राज्यपाल चुनाव के निर्णय को ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे। यह भी प्रश्न है कि निमन्त्रण देते समय केवल राजनीतिक दलों की संख्या देखी जायेगी। या जो निर्दलीय रूप से स्वतन्त्र हुए हैं उन सदस्यों की भी गणना की जायगी। राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को राज्यपाल द्वारा निमंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस को केवल तीस फीसदी मत मिले हैं जबकि कांग्रेस के विरुद्ध 70 फीसदी जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में परास्त कर दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेश्वर प्रसाद (छपरा): उनका नम्बर कितना है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उस पर भी आ रहा हूं। क्या केवल सीटें गिनी जायेंगी ? क्या चुनाव के द्वारा जनता ने जो राय प्रकट की है, जो राय प्रकट हुई है उसे दृष्टि से बिलकुल ओझल कर दिया जायेगा ? यदि सीटों का ही विचार करना है तब भी क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में जितने गैर-कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित हुए थे उन्होंने अपने को एक दल के रूप में संगठित किया ? उन्होंने अपना एक नेता चुना। उन्होंने एक न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किया। राजस्थान के राज्यपाल के लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वह जनमत का समादर करते और जो नया दल गठित हुआ था उस के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाते। एक दिन उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि वे किसे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमन्त्रण दे रहे हैं इसकी जनता को सूचना देंगे। लेकिन जब पत्रकार गये तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है क्योंकि कल जो विरोधी दल के नेता आये थे उनमें से एक नेता जाते जाते मुझे ऐसी बात कह गये जिस बात का कि मैं आदी नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल से विरोधी दल की ओर से क्या बात कही गई ? केवल इतना कहा गया कि हम आशा करते हैं आप निष्पक्षता से निर्णय करेंगे। कल भी हमने आप से कहा कि आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, हम आप से आशा करते हैं कि आप निष्पक्ष दृष्टि से कार्य करेंगे। इसमें बुरा मानने की कौनसी बात थी? लेकिन शायद राज्यपाल के दिल में चोर था जिसके कि कारण वह अपना संतुलन खो बैठे और दूसरे दिन उन्होंने जो निर्णय दिया वह संसदीय इतिहास में और कम से कम भारत के संसदीय इतिहास में बड़ा विचित्र माना जायेगा।

राज्यपाल ने कहा कि कांग्रेस दल की और गैर-कांग्रेस दलों की शक्ति का विचार करते समय जो निर्दलीय सदस्य चुने गये हैं मैं उनकी गिनती करने की आवश्यकता नहीं समझता। जब तक निर्दलीय सदस्य चुनाव लड़ते हैं, जब तक निर्दलीय सदस्यों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जब तक वे विजयी होकर विधान सभाओं में और संसद् में आ सकते हैं, तब तक कोई उनके अस्तित्व से इंकार नहीं कर सकता। क्या यह सच नहीं कि 1962 में इसी राजस्थान में निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से ही कांग्रेस सत्तारूढ़ हो सकी थी? जो नियम 1962 में लागू किया गया वह 1967 में लागू करने के लिए राज्यपाल तैयार नहीं हैं।

सन् 1962 में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस का बहुमत बनता था, सन् 1967 में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस अल्पमत में होती है, इसलिए राज्यपाल महोदय ने संविधान की अवहेलना कर के एक विचित्र निर्णय दिया, जिसकी परिणति इसमें हुई कि कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया। राजस्थान में इसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। जनता में रोष जागना भी आवश्यक था। जब संविधान की अवहेलना की जायेगी और जनमत को ठुकराया जायेगा, तथा जब राज्यपाल ऐसा आचरण करेंगे जिसमें से पक्षपात की गन्ध आती होगी, तो लोगों को शान्तिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट करने से नहीं रोका जा सकता। भारत गणराज्य है, हम एक लोकतन्त्र हैं, हम शान्तिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का अधिकार जनता से छीन नहीं सकते।

मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर में दफा 144 लगाने की क्या जरूरत थी..... (व्यवधान) मुझे कांग्रेसी सदस्यों के अज्ञान पर बड़ा दुःख होता है, और यही कारण है कि इस अज्ञान का लाभ उठा कर मंत्रिमंडल ने ऐसा कदम उठाया है जिसके कारण मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है। राजस्थान में हमारे कांग्रेस के सदस्यों को जनता को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। स्पष्टतः दफा 144 लगा कर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की चेष्टा की

गई । विरोधी दलों के नेताओं को जेल में बन्द करके जनता के नेतृत्वविहीन किया गया, और इससे जयपुर में असन्तोष ने और भी उग्र रूप लिया ।

जयपुर में 7 मार्च को गोली चली । मुझे सन्तोष है कि केन्द्रीय सरकार ने उस गोली-कांड की हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में सहमति द है। क्या गोली चलाना जरूरी था । कमीशन इसकी जांच करेगा, लेकिन तथ्यों को सदन के सामने रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं । आकाशवाणी से घोषणा कर दी गई कि जयपुर में दफा 144 हटाई जा रही है, लेकिन सड़कों पर तायनात जो पुलिस थी उसको खबर नहीं थी । रेडियो पर दफा 144 हटाने की घोषणा सुन कर भीड़ सड़कों पर इकट्ठी होने लगी ।

Shri P. Venkatasubbaiah (Nandyal) On a point of order. Now that the Government have instituted a judicial inquiry into the police firing, can the hon. Member raise that matter during the course of his speech here?

Mr. Speaker: Not specifically, but in a general way he has been referring to it.

Shri A. B. Vajpayee: It is only a fact-finding Commission; nothing is sub-judice.

An hon. Member: Is it a point of order or point of disorder?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह समझ कर कि दफा 144 वापस ले ली गई है, लोग सड़कों पर निकले, और पुलिस ने उनको तितर बितर करने के लिए बलप्रयोग किया, जिसकी परिणति गोलीकांड में हुई। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि 7 मार्च के बाद जयपुर में पूरी शान्ति रही। जयपुर को छोड़ कर सारे राजस्थान में आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंग से चला ।

विरोधी दलों पर आरोप यह लगाया गया है कि वे सरकार बनाने का निर्णय विधान सभा के भीतर न ले कर सड़कों पर लेना चाहते थे। मैं इस आरोप का दृढ़तापूर्वक खंडन करता हूं । विरोधी दल केवल जयपुर में ही सक्रिय नहीं हैं, सारे राजस्थान में प्रभाव रखते हैं । सारे राजस्थान में शान्ति रही क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि विरोधी दल मामले को सड़कों पर ले जाने के हामी नहीं थे ? यदि राजस्थान सरकार और पुलिस संयम स काम लेती तो जयपुर में गोली चलाने की नौबत नहीं आती ।

बस्तर में हुए गोलीकांड का इस सदन में समर्थन किया गया था । पांडे कमीशन की रिपोर्ट आ गई है । उस पर और प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है । 7 नवम्बर को दिल्ली में जो गोली चली उसका भी पूर्व सदन में समर्थन हुआ था । गृह मंत्री बतलायें कि दिल्ली पुलिस ने उस गोली कांड के बारे में जो जांच की है उसका निर्णय क्या है । जयपुर में 7 मार्च और दिल्ली में 7 नवम्बर को शासन की विफलता जनता की भावनाओं को कुचलने की उसकी तत्परता ही दिखाती हैं ।

कांग्रेस के नेता श्री सुखाड़िया ने जब देखा कि बहुमत उन के साथ नहीं है और उन्होंने राज्यपाल को इस आशय की सूचना दी कि मैं मंत्रिमंडल नहीं बना सकता, तब राज्यपाल का कर्तव्य था कि संयुक्त दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाते । उनको क्यों नहीं बुलाया गया । इसके लिए जवाब दिया गया कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पैदा हो गई । 7 मार्च के बाद राजस्थान में क्या हुआ ? कौनसी नई परिस्थिति पैदा हुई ? श्री सुखाड़िया 7 मार्च के बाद मंत्रिमंडल बनाने के लिए तैयार थे, तब तो उन्होंने कानून और व्यवस्था का हवाला नहीं दिया । तब वह समझते थे कि लोभ से, लालच से, भय से आतंक से, उचित और अनुचित तरीके अपना कर, वह गैर-कांग्रेसी

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सदस्यों को अपनी ओर तोड़ लेंगे और मंत्रि-मंडल बनाने में सफल हो जायेंगे। जब उन की आशाओं पर पानी फिर गया तो उन्होंने कानून और व्यवस्था का हवाला दे कर मंत्रि-मंडल बनाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। राज्यपाल महोदय के लिए रास्ता खुला हुआ था। वे गैर-कांग्रेसी दलों को बुला कर मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुला सकते थे। लेकिन यदि राज्यपाल ऐसा करते तो आज की परिस्थिति पैदा न होती। उन्होंने विरोधी दलों को सरकार बनाने का मौका देने के बजाय केन्द्र को लिख दिया कि राजस्थान में परिस्थिति ऐसी है जिसमें संविधान काम नहीं कर सकता और राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिए।

मैं चाहूंगा कि राजस्थान के राज्यपाल की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये। केरल के मामले में इस प्रकार की परम्परा अपनाई जा चुकी है। कहा जाता है कि राज्यपाल ने सिफारिश की थी कि विधान सभा भंग कर दी जाये। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। विधान सभा को भंग नहीं किया गया, केवल मूर्छित किया गया है। राजस्थान की विधान सभा बेहोश कर दी गई है। पता नहीं कौन हनुमान संजीवनी ले कर आयेंगे और उस मूर्छित विधान सभा को होश में लायेंगे। शायद संजीवनी गृह मंत्रालय की किसी आलमारी में बन्द है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : आपको मदद लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यशवन्त राव आज उस आलमारी को रक्षा कर रहे हैं खेद का विषय है कि राज्यपाल ने पक्षपातपूर्ण आचरण किया। केन्द्रीय सरकार ने उस पक्षपात के साथ अपने को जोड़ा। केन्द्रीय सरकार के लिए मार्ग खुला हुआ था। राज्यपाल को सलाह दी जा सकती थी कि वह अपनी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करें, बदलती हुई परिस्थिति, शान्तिपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए जो सिफारिश की उस पर फिर से सोचें। लेकिन केन्द्र ने भी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि जहां भारत के सभी अन्य प्रदेशों में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें काम कर रही हैं वहां केन्द्र के गृह मंत्री ने राजस्थान का भाग्यसूत्र अपने हाथ में ले लिया है।

मुझे आश्चर्य है कि गृह मंत्री महोदय ने कहा कि विधान सभा इसलिए नहीं बुलाई जा सकी क्योंकि विरोधी दलों ने विधान सभा के सामने एक प्रचंड प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री० शेर सिंह) : तैयारी की थी, घोषणा नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको उन की तैयारी का पता लग गया और उसके आधार पर आपने संविधान की हत्या कर दी। क्या प्रदर्शन की घोषणामात्र से विधान सभा स्थगित कर दी जायेगी, जनता को लोकतंत्रीय अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा? लोकतन्त्र में प्रदर्शन चलेंगे, प्रदर्शन चलने चाहिए और अगर प्रदर्शन के आधार पर सरकारें न बनने वाली हों तब तो फिर कांग्रेस के हमारे मित्र किसी प्रदेश में गैर-कांग्रेसी सरकार को चलने नहीं देंगे।

प्रश्न राजस्थान का ही नहीं है। केन्द्रीय सरकार और गैर-कांग्रेसी सरकारों का प्रश्न भी इसके साथ जुड़ गया है। कल मैंने कहा था कि कांग्रेस का सत्ता पर से एकाधिकार समाप्त हो गया है। अनेक प्रदेशों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने हैं। क्या केन्द्रीय सरकार उनको चलने देगी?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जरूर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राजस्थान एक इंगित है, एक इशारा है जो केन्द्रीय सरकार की नीयत के बारे में शक पैदा करता है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतने प्रदेशों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बन सकी हैं और चल रही हैं तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को ही क्यों अलग किया गया ?

आप अन्तर देखिये । गैर-कांग्रेसी सरकारें जहां बनी हैं या जब वहां इन सरकारों के बनने की घोषणा हुई है, तो जनता ने दीये जलाये लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल के लिए बुलाया गया तो वहां चितायें जलीं । जब गैर-कांग्रेसी दलों ने सत्ता के सूत्र सम्भाले तो माताओं और बहनों ने उनके माथे पर तिलक की रोलियां लगाईं और जब राजस्थान में जनता द्वारा तिरस्कृत कांग्रेस दल के नेता को मंत्रीमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो माताओं और बहनों के माथे की रोलियां पुंछ गईं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : धिक्कार ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गैर-कांग्रेसी मंत्रीमंडल बनने से जनता प्रसन्न होती है और कांग्रेस को जब मंत्रीमंडल बनाने के लिए बुलाया जाता है तो जनता रुष्ट होती है । क्या यह परिवर्तन केवल विरोधी दलों ने कर दिया है ? अगर आप ऐसा समझते हैं तो अभी आप दीवार पर लिखे हुए को पूरी तरह से पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं ।

राजस्थान में जो कुछ हुआ है उसने चौथे चुनाव के बाद लोकतन्त्र की प्रक्रिया को जो बल मिला था उसको आघात पहुंचाया है । उसने लोकतन्त्र के ढांचे के लिए खतरा पैदा कर दिया है और उसके लिए यह मंत्रीमंडल निन्दा का अधिकारी है ।

भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के सामने विधान सभा के सदस्यों को लाया गया हो और गिनती करके दिखाई गई हो कि बहुमत किसके साथ है ।

An hon. Member: They were under duress.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रख कर ऐसी बात नहीं कह सकता । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जैसा कि गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें संख्या से कोई सम्बन्ध नहीं है संख्या किधर ज्यादा है किधर कम है, इनको वह चिन्ता नहीं करते हैं . . . .

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने कभी नहीं कहा । संख्या के बारे में आप कह रहे थे मैंने नहीं कहा था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब विरोधी दल के सदस्य राष्ट्रपति जी के सामने आए और हमने कहा देख लीजिए 93 सदस्य हैं तो आपने कहा था कि 93 हैं या कितने हैं, इससे हमारा मतलब नहीं है और आपने राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू किया है कि वहां शान्ति और व्यवस्था का सवाल है . . . .

श्री यशवन्त राव चह्वाण : सही बात है ।

Since you were quoting me, I only wanted to make my position clear. I said, who has got what number of people is a matter for the Governor to consider. It is not for the Government of India to consider I was merely making a reference to the constitutional aspect of it. I was not expressing any view on the merits of the matter.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छी बात है कि गृह मंत्री जी ने यह मुद्दा कह दिया कि बहुमत किसके साथ है और किसके साथ नहीं है, इसका निर्णय राज्यपाल करेंगे । लेकिन अगर राज्यपाल निर्णय करने में गलती कर दें तो उसकी अपील कहां है . . . .

श्री यशवन्त राव चह्वाण : सदन के पास ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सदन की बैठक नहीं होने दी गई ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : शान्ति पैदा करे तब हो ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं । मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता हू । राजस्थान मे जो कुछ हुआ है वह किसी अन्य प्रदेश मे भी हो सकता है । जिस तरह से राज्यपाल नियुक्त किये गये हैं, मैं उसमे जाना नही चाहता हू । लेकिन राज्यपाल गलती कर सकता है । तब क्या केन्द्रीय सरकार का काम है आख मूद कर राज्यपाल के निर्णय को पुष्ट करना । यदि ऐसी बात है तो फिर जनता के सामने रास्ता कौन सा रहेगा ?

मैंने सविधान देखा है और मैं चाहूगा कि सविधान इस दिशा मे सुधारा जाए । हम राष्ट्रपति पर अभियोग लगा सकते है, राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल को इम्पीच करने की कोई व्यवस्था नही है ।

एक माननीय सदस्य . वह डिसमिस होंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी आखिर जनता के लिए कौनसा रास्ता है । विधान सभा भग कर दी जाएगी । केन्द्र राज्यपाल की सलाह पर लोकतन्त्रिक प्रक्रियाओ को समाप्त कर देगा लेकिन यह सदन किसी राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नही लगा सकता है । इस दिशा मे सविधान मे सशोधन करना जरूरी है ।

मैं इस बात से भी सहमत नही हू कि राज्यपाल की जो भी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रपति के सामने जो सिफारिश रखी राष्ट्रपति महोदय के पास उस सिफारिश को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था । सविधान की धाराओ की मेरी यह व्याख्या नही है । मैंने विधि विशेषज्ञो को भी इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करने के लिए कहा और अनेक विधि विशेषज्ञ ऐसे हैं जो इस मत के हैं कि इन मामलों में राष्ट्रपति को केवल केन्द्रीय सरकार की नीति पर चलने की आवश्यकता नही है, वह स्व-विवेक से भी काम ले सकते हैं, अपने डिस्क्रीसन से भी काम ले सकते हैं । मुझे खेद है कि राष्ट्रपति महोदय ने राजस्थान के मामले मे स्व-विवेक से काम नही लिया और यदि स्व-विवेक से काम लिया —मेरी जानकारी नही, लेकिन अगर लिया— तो उन से ऐसा निर्णय हुआ जिस निर्णय से सविधान की मर्यादाओ की रक्षा नहीं हुई ।

अभी समय है राजस्थान मे लोकतन्त्र के चक्र को पीछे घुमाने की जो कार्यवाही की गई है उसे रोका जा सकता है । क्या राजस्थान मे शान्ति नही है ? क्या केन्द्रीय सरकार वहा मरघट की शाति चाहती है ? इस देश मे मरघट की शाति पैदा नही होने दी जायेगी । अगर सविधान की हत्या की जायेगी, अगर केन्द्रीय सरकार लोकतत्र का गला घोटने पर उतारू है, तो शान्तिपूर्ण तरीको मे अपनी पूरी निष्ठा रखते हुए भी हम इस अन्याय के खिलाफ लडेंगे । हम नही चाहते कि यह मामला सडको पर तय हो । लेकिन आम आदमी से इतना ही काफी नही है । आम आदमी को यह कहना भी जरूरी है कि उसे सडको पर निकलने की नौबत ही नही आने दी जायेगी ।

अगर राजस्थान मे विरोधी दलों को सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाता, तो क्या बिगड जाता ? कहा जाता है कि अगर विरोधी दल चाहते तो वे विधान सभा मे शक्ति-परीक्षा कर सकते थे । तो क्या श्री सुखाडिया विधान सभा में शक्ति-परीक्षा नही कर सकते थे । जो बात विरोधी दलो पर लागू होती है, क्या वह श्री सुखाड़िया पर लागू नहीं होती

है ? जो बात हम पर लागू होती है ? क्या वह कांग्रेस पर लागू नहीं होती है ? लेकिन श्री सुखाड़िया को समय दिया गया लोगों को तोड़ने और अपनी ओर फोड़ने का ।

निर्दलीय सदस्यों के बारे में निर्णय देने के लिये राज्यपाल को बारह दिन लगे । अगर "सिंगल लार्जेस्ट पार्टी" के नाते कांग्रेस को बुलाना था, तो चुनाव-परिणाम के तुरन्त बाद बुला सकते थे । राज्यपाल बारह दिन क्या करते रहे ? क्या "इंडिपैंडेंट्स नाट टु बि काउंटिड" इस नतीजे पर पहुंचने के लिये उन्हें बारह दिन लगे थे ? या वह भविष्य की चिन्ता कर रहे थे, तारो की तरफ देख रहे थे, ज्योतिषियों से विचार विनिमय कर रहे थे ? जो कुछ राजस्थान मे हुआ, वह अच्छा नही हुआ । उसे ठीक किया जाना चाहिए ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम भी नहीं समझते कि अच्छा हुआ । हम भी नाराज हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप गलत काम भी करते है और नाराज भी है । जो कुछ किया, आपने किया । अभी भी उसे बदलने का मौका है । राजस्थान मे शांति है । क्या गृह मंत्री स्वयं जाकर देखेंगे कि राजस्थान मे क्या स्थिति है ? लेकिन यह शान्ति ज्यादा दिन रहेगी, ऐसा समझ कर वह न चले । शायद वह इसी के भरोसे बैठे हैं । (*Interruptions*).

राजस्थान की विधान सभा का बहुमत दिल्ली आया था, राष्ट्रपति के सामने उपस्थित हुआ था । वहा पर बहुमत किसके साथ है, यह प्रकट हो गया है । जो एक बहाना लिया गया था बहुमत की सरकार को न बनने देने का और अल्पमत की सरकार को थोपने का, वह बहाना, यानी शान्ति और व्यवस्था का बहाना भी अब नही है । हो सकता है कि राज्यपाल महोदय न मानते हों । लेकिन केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में स्वतंत्र रीति से मत निश्चित करना होगा और अगर राज्यपाल महोदय संविधान के अन्तर्गत निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार नही हैं, तो उन्हें राजस्थान से हटाना होगा ।

नये राज्यपालो की नियुक्ति करते समय केन्द्रीय सरकार इस बात को ध्यान मे रखे कि 1967 के चुनावो के बाद राज्यो की परिस्थिति बदल गई है । कई राज्यो में गैर-कांग्रेसी मंत्री-मंडल काम कर रहे है । कांग्रेस के दलीय स्वार्थों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त नही किये जाने चाहिए । अगर किये गये, तो प्रधान मंत्री के इन आश्वासनों की कोई कीमत नही होगी कि हम राज्यो के साथ सम्बन्ध अच्छे रखना चाहते है । केवल घोषणा काफी नही है, आचरण होना चाहिए और राजस्थान मे जो आचरण हुआ है, उस से सभी गैर-कांग्रेसी दलो और मंत्री-मंडलों में एक संदेह पैदा हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हू । उत्तर प्रदेश में भी अगर राज्यपाल जनमत का समादर करते और विरोधी दलों के संयुक्त दल को मंत्री-मंडल बनाने के लिए निमंत्रण देते, तो उत्तर प्रदेश में संविधान की मर्यादा का पालन होता । लेकिन वहा भी कांग्रेस को मौका दिया गया । *Interruptions*). 425 सदस्यो के सदन मे 199 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है ? (*Interruptions*).

एक माननीय सदस्य : इस बारे में दो मापदंड नहीं हो सकते ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दो मापदण्ड तो आप अपना रहे हैं । राजस्थान मे राज्यपाल ने इंडिपैंडेंट्स को नही जोड़ा और उत्तर प्रदेश मे इंडिपैंडेंट्स जोड़े जा रहे हैं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : हरियाणा को देख लीजिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि मन्त्री-मंडल का यह कर्म उसे निन्दा का अधिकारी बनाता है। आम चुनावों के बाद देश की जो परिस्थिति है, समस्याओं की जो जटिलता है, गम्भीरता है, उसे हल करने के लिए सभी दलों का सहयोग जरूरी है । एक दृष्टि से यह अच्छी बात हुई है कि ग़ैर-कांग्रेसी दल जगह जगह सत्तारूढ हुए हैं । ऐसा लगता है कि जनता ने सभी दलों को एक-साथ कसौटी पर कसने का फ़ैसला कर लिया है । लेकिन अगर इस परिस्थिति का लाभ उठाया जाये, तो देश की समस्याओं को हल करने के लिए ऐसा वातावरण बन सकता है, जो अब तक नहीं था । राजस्थान में राष्ट्रपति-शासन लागू करके केन्द्रीय सरकार ने सारे वातावरण को विकृत कर दिया है ।

इस लिए यह केन्द्रीय सरकार हटनी चाहिए, सदन को इस सरकार को बाहर फेंक देना चाहिए, ठुकरा देना चाहिए । इसी लिए मैं ने यह अविश्वास-प्रस्ताव पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस को स्वीकार करेगा ।

Mr. Speaker: Motion moved:

"That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers."

The motion is now open for discussion. I think we will have to fix up some time limit for speeches. I would say the leaders of the parties may take about 20 minutes each but o hers should confine themselves to ten minutes so that we will be able to give opportunity to many.

Shri M. R. Masani (Rajkot): 10 to 15 minutes should be the time for others.

Mr. Speaker: If we attempt to limit within ten minutes it will go to 12 to 13 minutes.

Shri K. Manoharan (Madras North): 25 to 30 minutes may be allowed to leaders of parties.

Dr. Karni Singh: Sir, Members of Parliament from the affected States should be given five minutes more.

Mr. Speaker: Let us proceed. Let us see the point they are making. We would certainly like to hear them. The whole House would be pleased to hear them. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister will be happy to hear them if any new points are to be covered.

13.48 hrs.

ANNOUNCEMENT RE. PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker: Now, before we proceed, since we do not have a Deputy-Speaker elected yet, I would like to announce the names of the following friends who will constitute the Panel of Chairmen:

Shri D. S. Raju

Shri P K. Deo

Shri K. Manoharan

This is the Panel of Chairmen. We will elect the Depu y-Speaker a little later. Now I would request Shri Manoharan to speak.

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है कि चूंकि इस हाउस में गवर्नमेंट और अपोजीशन के मेंबर्ज मतलीस है इस लिए एक मेंबर उधर से और एक इधर से बुलाया जाये ।

13.49 hrs.

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

Mr. Speaker: I have here a list containing names from all sides. If

Shri Manoharan is not here or he is not ready, I would request Shri Khadilkar to speak.

Shri Khadilkar (Khed): Mr. Speaker, Sir, "No-confidence Motion" in this House, as Shri Masani has rightly pointed out, has become farcical, and he dissociated himself—and also his group—from the present motion. I am very glad. It is a welcome move on his part.

An hon. Member: He is dreaming.

Shri Khadilkar: It has become a hardy annual. We have witnessed it on several occasions. Therefore, Sir, on this occasion we must take this motion very seriously. Shri Masani perhaps realises it, perhaps the Right Communists do, but others do not. At the present juncture, after the general elections, let them bear one thing in mind. In this House we have got the mandate with a majority. Whatever the number sitting in opposition, they are splinters and even if they join, with all the verbosity, with all the eloquence, they cannot possibly destroy a fact which has emerged after the last elections. Let them bear this in mind. Therefore, those who want to run the governments at the State level, within the framework of he Constitution, according to the procedures laid down, I expect they would act more responsibly while opposing a government which has come back to power with a renewed mandate, a solid mandate, not a fractional majority by different parties with different ideologies and different programmes coming together and having some sort of marriage of convenience when hey are ranged against the Congress. Let them bear this in mind. Therefore, if you take into consideration the last election results, I think wiser counsel should have prevailed and they should have said "you have come with a renewed mandate; we will watch what you do, how you function; we will judge your functioning from issue to issue and whether we agree or disagree, we will have our own say".

13.52 hrs.

[SHRI D. S. RAJU *in the Chair*].

Unfortunately, the Rajasthan issue has been highlighted. But, while highlighting that issue, the hon. Member has not cared to go deep into the Constitution, particularly article 356. I would like to remind him that when the emergency powers were used after the last elections in Kerala, I had raised my voice against the use of emergency powers in that particular situation because it was not justified. Why did I say that? Because, after the elections the representatives with a fresh mandate must be given an opportunity to find out whether they are in a position to form a government or not. So, I then pleaded that the House need not be dissolved but should be kept in suspense. Since then, the emergency powers were used in the case of Punjab, for the sake of division, and now in Rajasthan. So, we have got to take into consideration whether those powers are being used arbitrarily for a party advantage, or as laid down in article 356, when there is sufficient justification and there is no possibility of a Government with the backing of a clear cut majority. I am no just talking with the oratorial flourish like my hon. friend, Shri Vajpayee, but I may tell him that oratorial flourish will cut no ice in this House.

On this occasion, when you have no clear-cut majority, if you do not yield but threaten the government by saying that you will take he battle to the streets, as you did in your speech, I am afraid, we will have to take a very serious view of the situation, because we are entrusted with the responsibility of running the Union Government, like you have come in power, with the co-operation of other parties, in some States, except Madras where one opposition party has secured the majority. Therefore, I will suggest one thing.

Shri K. Manoharan: Madras is going to be the harbinger.

Shri Khadilkar: I have said that. I have made an exception. You have secured a majority.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): There is no chance of the expansion of the Cabinet any more.

Shri Khadilkar: I am more honourable. Even if I am not on the Treasury Benches I have my say. When I have not agreed on certain issues, I have given expression to my thoughts without inhibition because in our party, I must say it, when the question of interpretation of the Constitution is concerned, we have full freedom and I have exercised it.

Therefore I would like to remind Shri Vajpayee, let us try to recollect what happened in Rajasthan. That would be better. There was an agitation. There was no clearcut majority of any party. In a routine manner the Assembly was convened to meet on the 20th. As the Opposition parties tried to mount an agitation and threatened with movements, peaceful or violent, whatever be their character, the Governor decided to advance the date to the 14th, according to their desire, to meet their wishes. Did he not act taking into consideration the prevailing feeling and the atmosphere outside? Was he acting on somebody's advice from somewhere else? He did act on his own. What does it show? It proves his *bona fides*. You will have to admit that it proves his *bona fides*. Therefore, all the attempts made during the intervening period by the so-called Opposition groups, parties and independents, with maharajas and maharanis on their side....

Shri P. K. Deo: You have plenty of them on your side.

Shri Khadilkar: ....and moneybags to enlist a few more members, did not succeed.

Shri P. Ramamurti (Madurai): You have got a Maharaja in the Cabinet.

Shri Khadilkar: When they found that they had no chance of enlisting majority support, they thought that the best course would be to take the battle to the streets of Jaipur and compel the Government under provocation, not under normal circumstances but under provocation, to use force. If Opposition parties are going to adopt this attitude, they ought to remember that it is a double-edged weapon. I do not want to give any threat.

An hon. Member: You have used it in Bihar.

Shri Khadilkar: They should remember that in some States, either as a group or as a party, or as a combination or a coalition, they are running the Government. While taking to such methods they should bear in mind that they cannot act in this manner and then expect the Opposition there to act in a responsible manner, functioning within the framework of the Constitution in their respective States. Where they have not got a clearcut mandate and horse-trading is going on to enlist members......

Shri Jyotirmoy Basu (Diamond Harbour): From which side?

Shri Khadilkar: From the Opposition side. What has happened in UP? I do not know the antecedents, but there is a clearcut majority of four members on our side. I heard yesterday, and it was really painful reading that one of the members of the Congress side was shot at and killed. If you are going to take to this method to reduce the majority, I am afraid, you are not at all......

An hon. Member: You want time.

Shri Khadilkar: No, I am not wanting to take time, but I would like certainly to beg of the Government to watch very carefully. Fortunately, a Left Communist Chief Minister, of Kerala, has admitted in his statement and so far as the Central Government is concerned, from their statement it appears that they are going to extend full co-operation.

Shri Jyotirmoy Basu: Lip service.

Shri Khadilkar: Is it lip service? I know, he is very sincere.

Shri Jyotirmoy Basu: I am referring to the Central Government.

Shri Khadilkar: Therefore, at this juncture, when we are mainly concentrating on the Jaipur incidents and what happened in Rajasthan, we should not be carried away by emotion or flourish of the language. Was there any substance? As I said, propriety demanded, though after the last General Elections the Opposition is trying to intensify the climate of defeat in the country so far as the ruling party is concerned, that they ought to have borne in mind the facts of political life and the fact is that once the mandate is given and the Government is formed, there is no room for immediate No-Confidence motion. Constitutional propriety does not pepmit that.

14 hrs.

Shri A. B. Vajpayee: Don't talk of constitutional propriety. You have flouted the Constitution. It does not lie well in the mouth of the hon. Member to talk of constitutional propriety. Let him not teach constitutional propriety to Opposition Members.

Shri Khadilkar: Have a little patience. You cannot run the Government in this impatient manner. You are supposed to run the Government.

Shri Dhireshwar Kalita (Gauhati): What happened in Haryana?

Shri Suraj Bhan (Ambala): There the Congress majority is reduced. (*Interruption*).

Shri Khadilkar: The Constitution says:

> "If the President on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution the President may by Proclamation....."

The only point of discussion or debate regarding Rajasthan affair could be made on the basis of this article. You cannot argue the case because there was firing. Who compelled the Government to resort to firing?

Shri A. B. Vajpayee: They only argue on that basis.

Shri Khadilkar: Just now you said that if these things happen, you will have to start agitations outside. You cannot have one foot in the seat of power and another foot in the camp outside from where you can operate in an unconstitutional manner. No public opinion in this country.... (*Interruption*).

श्री रामसेवक यादव : (बाराबंकी) केरल में क्या हुआ था, आप भूल जाते हैं। क्या किया था केरल में ?

Shri Khadilkar: On this occasion, I am referring to Rajasthan. I plead with the Opposition and when the groups belonging to Opposition are in power in some of the States, the natural expectation was that they will behave with greater sense of responsibility and they will try to see whether in terms of the Constitution any breach has been committed.

I would like Shri Vajpayee—just now I have no reference with me—to refer to what happened in the Constituent Assembly when these provisions were finally approved. It is the final responsibility of the Central Government to see that, if there is a failure of administrative machinery in a State, we assume responsibility. Here, at the same time, while assuming responsibility, the Government has stated very clearly that it is for a short duration. The President in his Address today has expressed a desire that that duration will not be too long because we do not want to take upon ourselves the responsibility of running a State Government when only recently the elections have taken

[Shri Khadilkar]

place. But, unfortunately, the result of the elections has not given any party a clear-cut majority.

Then, the question of Governor was brought in and he said about his impeachment and all that. I would like to say that there are Governors in West Bengal, Madras, Orissa, Bihar, Kerala and Punjab where the Opposition is ruling. Is there any report anywhere that the Governor is not acting according to the advice of the elected representatives and the new Ministries? (*Interruption*). You cannot single out one Governor and say, as he tried to argue just now, that he did not act as he should have acted. He exercised objectivity in assessing the situation.

Shri P. Ramamurti: If 'A' has acted properly, that does not mean that 'B' can act properly. What is this logic?

Shri Khadilkar: Mr. Ramamurti, when I quoted all these Governors, they have acted on the advice of the newly formed State Governments. Here, unfortunately, the situation was such where no Government could be formed. You must realise that.

Shri K. Manoharan: At the time of elections, I read paper reports that Dr. Sampurnanand, Governor of Rajasthan, had clearly stated that the Congress Government alone can provide stability and continuity in the country. Thereby, he has proved himself to be a Congressman rather than a Governor.

Shri Khadilkar: What he said is correct. I am confident about it. (*Interruption.*)

Shri A. B. Vajpayee: Is no impropriety involved now?

Shri Khadilkar: He has made a reference to the Convocation address. In a convocation gathering, he is free to express his opinion. What is wrong there?

Shri K. Manoharan: Governor is supposed to be above party politics.

Shri Khadilkar: Yes; he is above party politics. He was speaking at the convocation.

Shri K. Manoharan: That is still worse. (*Interruption*).

Shri Khadilkar: I maintain what he said is correct. The observers who have seen the results of the elections have also reached the same conclusion.

Shri K. Manoharan: What business has he got to give the lead to the people?

Shri Khadilkar: It was his opinion. He is free to express his personal opinion. It was not an election meeting; it was a convocation address.

Shri K. Manoharan: This is a very feeble defence. As long as he is Governor, he has no personal opinion at all.

Shri Khadilkar: It was a convocation address.

Shri K. Manoharan: That is still worse because he was facing students.

Shri Khadilkar: They must know what are the facts of political life.

An hon. Member: That was misuse of his official position. (*Interruptions*)

Shri Khadilkar: Sir, I cannot carry on like this. Let me have my say.

He questioned the propriety of the Governor saying that we can provide stability and progressive Government in this country. These remarks are justified even now. As I said earlier, there were prophets of doom predicting that not only the Congress but democracy itself was disintegrating. They have been belied by the results of the elections because very wisely the Congress Party has been entrusted with a clear-cut mandate to run the Centre and supervise, within the framework of the Constitution, according to the laid down principles and procedures of the Constitution, the

functioning of the State Government. So, he is proved prophetic so far as his remarks are concerned that the Congress alone can provide stability. So, the Governor took all aspects into consideration and reported to the President that all efforts had failed. Even advancing the date by about six days has not satisfied the Opposition. They are bent upon creating disturbances. They organise demonstrations and *morchas*. The matters which are to be debated, discussed and deliberated and resolved peacefully in the four corners of the chamber of the Assembly have been taken up in the streets. In such a situation what other course he had but to report to the Centre that there is failure of administration. That was his obligation. It is on this basis that the Central Government has acted and for the duration of two months the Assembly has been kept in suspension. Is there any Consitutional impropriety involved in this? I would like to know this. There are many Constitutional pandits on this side and I expect that some of them at least.... (*Interruptions*).

Shri Dhireshwar Kalita: On a point of order

Shri Khadilkar:....will have to say keeping in view the Articles of the Constitution.... (*Interruptions*)

Shri Dhireshwar Kalita: On a point of order.

Mr. Chairman: What is the point of order?

Shri Dhireshwar Kalita: I have learnt many lessons on Indian Constitution, but I want to know only this much. When in Rajasthan a clear majority emerged and representatives of the Opposition came here and presented themselves to the President, how can this gentleman speak about Constitutional propriety? I want to know this from him.

Mr. Chairman: I do not see any point of order in this.

Shri Khadilkar: What I was saying in conclusion was this. As I said in the beginning, the move to come forward with a no-confidence motion immediately after the election with a clear-cut mandate was foolish, to say the least, and, therefore, one party called it farcical and did not associate itself with it, but the others have jumped into the wagon... (*Interruptions*).

Shri A. B. Vajpayee: Did the hon. Member see that that party stood up in support of my motion?

Shri Khadilkar: That is allright. There are marriages of conveniences and alliances. They have given up the political morality. The Opposition has already given up the political morality. (*Interruptions*). So, I do not want to go into their alliances.

श्री रामसेवक यादव : मुस्लिम लीग और गणतंत्र परिषद् के साथ गठबंधन कर चुके हो। क्या बात करते हैं?

Shri Khadilkar: What I suggest is this. He has made only one point. So far as Jaipur incidents are concerned, they are under investigation by a high judicial authority and I do not want to go into the details about it. So far as the Governor's report and the proclamation of Emergency is concerned, I am convinced that within the framework of the Constitution, according to the provisions as I have read out just now, the Governor was justified in reporting failure and the Central Government was more than justified at the present juncture it was their responsibility it was their obligation under the Constitution to act on the advice of the Governor ...

Some hon. Members: No no,.

Shri Khadilkar: 'No' or 'Yes' will not make it.

One more point. Mr. Vajpayee referred to the incidents of November 7th in the last session he made a pointed reference to that. He ought to feel ashamed.

An hon. Member: Why?

Shri Khadilkar: I say this because the authorities were assured of a peaceful demonstration and some sort of a strategy was behind all this to create a situation on the eve of the elections; they wanted to generate an atmosphere of violence and disorder in the country. So, those who were responsible for organizing that demonstration, were responsible....

Shri Atal Behari Vajpayee: Where is the report?

Shri Khadilkar: ....were responsible for what happened on that day and they must feel ashamed of this, if they believe in democracy and want to function within the framework of the Constitution.

Dr. Karni Singh: During the last 15 years that I have had the honour to represent the people of my constituency in this august House, I have always maintained a position of complete neutrality and independence, but this time when democracy has been murdered, when the feelings of the people have been completely floutd and ignored, it makes the blood of any citizen who believes in freedom and democracy boil and I feel that it is the responsibility of all of us, whether we belong to the Congress Party or to the Opposition, to voice our feelings on the President's rule having been imposed in Rajasthan fearlessly. I had only hoped that the Government would have sense enough to revoke the President's proclamation before the President made his Address today. As you know 93 members of the Opposition in the Legislative Assembly were brought to Delhi and a physical inspection was given to the President of India.

An hon. Member: It is wrong.

Dr. Karni Singh: He has to prove it wrong.

These 93 members were brought here and the President saw them and later group photographs were taken, and if anybody still wishes to challenge that, he is welcome to do that.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): You can even bring them before the House and show them.

Dr. Karni Singh: For the Government to stand on a false sense of prestige and for the Governor to make a statement to say that the President's rule should continue, is something which, I think, lacks in diplomacy and administrative skill. (*Interruptions*).

As you know, there have been balanced election results in Rajasthan in 1952 and 1962 and this is not the first time that the Opposition and the Congress Party have returned almost an equal number of members, but this time there was no doubt that the Opposition did have an edge and should have been called to form a Government. However, whatever may be the facts in this case, once the Governor took the decision to call the Congress Party to form the Government, he should have gone all the way through and let the Congress Party from the Government first; it could have been toppled over. But because of certain excuses that the Government gave in Rajasthan—that the law and order situation had broken down—the Governor recommended to the President through the Government of India that the President's rule be imposed. This is something that the people of Rajasthan feel most indignant about and if I can quote Mr Chatterjee, "it is a slur on democracy; it is a fraud on the Constitution".

A great deal has ben said about the firings that took place in Rajasthan and we heard members from Congress benches say that these were engineered by the Opposition.

It appears that the Congress members have forgotten that when the feelings of the masses running into lakhs and lakhs are aroused, it is something that cannot be engineered by any individuals or members of the Opposition parties. When feelings run high as they did in Rajasthan—and such feelings are known to run

high in many other parts of the country—it is for the Government to read the writing on the wall and understand as to what is the correct step to take. In my opinion, imposing President's rule was a completely retrograde step.

I was told, although I have not visited the site myself, that firings took place in which even children were killed.

An hon. Member: Shame, shame.

Dr. Karni Singh: After that; college students and children between the ages of 11 and 13 were put in jail, preventing them from appearing in their examinations. I cannot understand how a Welfare State and a Government which claims to be a Welfare Government can do hings like that and especially where children are involved. I can understand disciplinary action being taken against adults, but I do not think that anybody can forgive a Government which puts little children in jail and fires on little boys.

Coming to the question of horse-trading, I understand that whenever there is a parity in any legislature, political parties will make an attempt to win over members of the Opposition Party or *vice versa* but in the case of Rajasthan, we know from the previous two occasions in 1952 and 1962, that the Government of Rajasthan or the Leaders of the Congress Party are known for their success in horse-trading. In fact, it was perfectly expected immediately after the results were annonuced that the Chief Minister of Rajasthan would try to win over the independent members from the Opposition benches and that is exactly what happened. I can also understand as an independent that the Opposition members did likewise too. But that is not the point. The point is which Party had the majority and the Party that had the majority should have been called first. We heard the Governor say that he was going to ignore the independent members, although the members had given in writing their consent to join the Samyuktha Dal. As an independent myself, I questioned the right of the Governor to take a stand against the independents like that to ignore them; if the 50 members of the Opposition parties here who have been returned as independents are as free to join any political party or remain independents as they like, and for any authority to question that decision or theirs, I feel, is completely unjustified. Mrs. Gandhi had spoken from the house tops soon after the elections eulogising the great stand that the Congress party took to see that the elections were held fair all over the country, and we praise her for that. But immediately after the general elections, why should Rajasthan have been singled out as the State wehere democracy was to be stifled? I think Government would have been wise to see that democracy and democratic principles were established in Rajasthan too.

Talking about flirings, if every time a firing takes place President's rule has to be imposed, then I would like to know from the Home Minister whether whever firings take place in the Congress-run States, Government will also impose President's rule immediately. Any Government worth its name should be in a position to take care of demostrations and rowdy elements. But what happened in Rajasthan was an upsurge gainst a wrong being done against the people, against somethig which was completely undemocratic.

We often hear remarks being made that Government might have taken these steps to prevent a feudalistic government coming into power. I cannot honestly understad what they mean by feudalism. The former princely States were finished off twenty years ago. Everybody is equal now. This is a free country. It must be remembered that that former Rulers of the Indian States are not citizens of Pakistan or China but they are very much the citizens of this country.

[Dr. Karni Singh]

Each one of them is trying to do his duty to the best of his ability. But may I remind the Congress Benches that the very fact that Mrs Gandhi has been elected leader of the Congress Parliamentary Party twice is also a perpetuation of a type of feudalistic hereditary system because she is also the daughter of the late Prime Minister Jawaharlal Nehru? I shall admit that I was elected four times to Parliament because my father and grandfather had worked for the people sincerely. Heridity is something that we could do nothing about. She was also elected because her father was a great man. If she had not been the daughter of Jawaharlal Nehru, I am sure Shri Morarji Desai would have been the Prime Minister today.

Shri Nambiar: And Shri Moraji Desai might well be followed by his son.

Dr. Karni Singh: Quite true, and with an equal chance Shri Nambiar's son too. If he works well, his son will benefit, and if he works badly he will be thrown out.

I would like to make one request to the Central Government now. I say as an Independent that whenever allegations were made against the Congress Party in Rajasthan about corruption, I had always felt that not all these allegations could be true. Shri Mohanlal Sukhadia is a friend of mine, and the leader of the Opposition there is my father in-law I am neutral in this matter. But now when we see that the Rajasthan Government and the Congress Party are so keen to stick to power it makes us wonder sometimes whether they really have any skeletons to hide, and if that be the case, then for the sake of public knowledge it is important that the Central Government should institute an inquiry into these allegations. I agree that we should not go in for a system of witch-hunting Every time a political party is thrown out of power, we do not want to see that the outgoing Chief Minister or his co leagues have an inquiry instituted against them purely as a process of victimisation. But I do think that in Rajasthan, for the sake of the feelings of the people, and for the sake of the country as a whole and for the sake of preserving democratic principles, an inquiry should be instituted into the corruption charges against the Congress Government.

One of the most depressing things about the whole President's rule question has been the imposition of the President's rule in Rajasthan a bare few hours before the tussle for supremacy was to take place in the Assembly. If President's rule was to be imposed it could easily have been done a few days earlier also. The entire country and the two crores of people of Rajasthan were anxiously waiting to see which party in fact had the majority. But at nine o'clock at night, a bare few hours before the tussle was to take place, Government took a decision to impose President's rule. This in my opinion shows the weakness of the Congress Party, the weakness of the Government of India and a definite desire on their part to hide something, God alone knows what it is.

Now, I would like to say one thing, that a stage has come when a parliamentary delegation consisting of all parties from this House and the Congress Party too should go to Rajasthan and make an on the-spot inquiry, and I am sure that they will be in a position to report to Parliament as to what exactly the circumstances there are, what the conditions there are, and whether President's rule should be continued.

I shall also make another request to the Leader of the Congress Party in Parliament, namely that when the Proclamation by the President comes before Parliament, the whip should not be allowed. If the Congress Party is not whipped to vote, I am quite

sure that Proclamation will never be carried through this Parliament. I sincerely hope that Shrimati Indira Gandhi and Shri Morarji Desai, both of whom stand for freedom and democracy, will see that the Members of the Congress Party are given total freedom of vote on this measure.

Shri Nambiar: They know they will be defeated and, therefore, they will not allow that.

Dr. Karni Singh: Enough has been said about President's rule in Rajasthan and there will be other Members who may wish to say something more on this question.

I shall now digress and speak on another subject and that is the result of the elections. For the first time in the four elections that have been fought since freedom, the people can now feel that their representatives are in fact their representatives; they can feel that in fact whatever their wishes are can be carried through in the legislatures and in the supreme Parliament of India. I think the greatest thing could have happened to preserve democracy in our country to provide a safety valve, was to have some non-Congress Ministries in the States It is possible that some Congress Members who have been my friends may feel unhappy about a situation like that, but I feel that the Congress Party, by vacating office, will get a longer lease of life. The Opposition Parties who have come to power will in my opinion be facing some of the most difficult problems that there are, problems like hunger, poverty, unemployment, rising prices etc., all of which have dogged the Congress Party all these years and which will confront the Opposition parties likewise.

If we want to face these gigantic problems, to give the people of our country a fuller life and a happier life we shall have to tackle these problems on two fronts which the President has observed very rightly this morning, namely by increasing food production in particular and production on all fronts in general, and by decreasing the number of people being born every day and every hour. I have been, for the last ten years, fighting for population control and family planning, in this House, and I am glad that from the President's lips today we heard that the population had reached the peak figure of about 50 crores, that our increase was about 35 000 per day, and that we were adding on an Australia every year. In a situation like this, what Government propose to do to bring down the increase in population from 45 per thousand to 25 per thousand is a step in the right direction.

Shri Krishna Kumar Chatterjee (Howrah): He is expressing confidence in Government.

Dr. Karni Singh: I sincerely hope that Government will achieve the targets because if they do not....

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): Are we discussing the President's Address now? We are not discussing it today?

Dr. Karni Singh: I am not discussing it, but I can make a reference to the President's Address. Can I not?

Shri Krishna Kumar Chatterjee: He is expressing confidence in the Government.

Dr. Karni Singh: Whatever the President says has also a bearing on the no-confidence motion, because everything that we are doing today....

Shri Nambiar: We can discuss it.

Dr. Karni Singh: Of course, I can.

The Prime Minster also observed in her broadcast two days ago that if India were not to take up family planning seriously we would be submerged I am glad that at least the younger generation in the Congress Benches have begun to realise the problems that are goig to confront them. I feel sorry that the men in

[Dr. Karni Singh]

their sixties and seventies may not be around to see the population explosion take place. But my generation is in for the high jump, and unless we do something positive now, we are guaranteed that poverty will remain as long as we live.

About a year and a half ago a no-confidence moiton was moved against the Shastri Ministry. I remember very vividly having spoken on that occasion when I criticised the Congress for their misdeeds and the Opposition for theirs, which according to me was their lack of incentive to unite into a powerful Opposition. I am very happy to see today some of the parties like the Swatantra, Jan Sangh, the DMK and the two communist blocs and the SSP who have come here in bigger numbers I offer them my congratulations. I feel that this is the only way by which we can serve the country, by creating a very powerful Opposition and a very powerful ruling party. India has ultimately to produce a powerful two-party system. Now the Opposition parties have taken the first step. The people have approved of them. The next step is that the rightist parties should merge into a new party and the leftist parties should from themselves into another new party.

Shri Nambiar: And ultimately the rightists to be liquidated.

Dr. Karni Singh: May be. That is for the people to decide.

An hon. Member: They will become independents (*Interruption*).

Dr. Karni Singh: Shri Khadilkar made a reference in his speech—I was not here when he spoke; but I was told that he did so—to the ex-rulers and said that the Opposition had all the ex-rulers, Maharajas and Maharanis and what not. It has never been my practice to speak for or against on this subject because I consider myself a representative of the masses. But in fairness to those people who happen to belong to a parentage of former rulers, which is obviously not due to their own fault because they could not pick their parentage, it is unfair for the Congress party to say that the Opposition has all the Maharajas and Maharanis. If I am right, the Congress party has most of them.

I am particularly glad today to see that the Prime Minister has utilised the services of some of the finest amongst the former rulers like Dr. Karan Singh who from his tender age in his early twenties worked as Governor of one of the most difficult States in the country. He acquitted himself well and he has been rewarded today and made a Cabinet Minister.

The fact is that whether a person is a Maharaja or a Maharani or an individual of any other ranking in society, we are all Indians. The services of every individual should be utilised according to his worth, and prejudices should be shunned. I have no doubt that no great nation can ever be built on prejudices.

Coming to the future of the Congress party in this House, the people have shown by their verdict that they cannot tolerate a steam-roller democracy. The Opposition has been returned in very powerful numbers I have a feeling that in the next election that will come in the next five years, the Opposition will be returned in bigger numbers, perhaps enough to form a Government There is also the possibility that before the five years are out, the Opposition may form the Government here too That can happen if members of the Congress party who feel strongly that the Government is not carrying on correctly by bringing in measures like President's rule in Rajasthan, which are completely undemocratic, act up to their convictions. I have a feeling that many of these young men who have freedom of speech, who believe in freedom, may walk across to the Opposition and then the Opposition may be in a position to form the Government. If such a situation happens,

I feel it will be like a shot in the arm; it will give the country fresh thinking and fresh blood because change is the essence of democacy.

I do not wish to take too much of the time of my brother Members here. I support the no-confidence motion moved by Shri Vajpayee with all my heart and I sincerely hope that we will be in a position to carry it through in this House.

Shri Krishna Kumar Chatterjee rose—

श्री मगीभाई जे० पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, मैं आप से एक जानकारी चाहता हूं । जिन के नाम लिस्ट मे नही हैं और वे बोलना चाहते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी ?

मैं बोलना चाहता हूं और इधर मेरे पास जो बैठे हुए उनका नाम लिस्ट मे है—

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इधर आकर बोल सकते हैं ।

श्री मगीभाई जे० पटेल : अभी तो आपकी हार हुई है । इसी वास्ते आप इधर बैठे हैं । आप हो इधर आ जाये ।

Shri Krishna Kumar Chatterjee (Howrah): I rise to oppose the Motion moved by Shri Vajpayee against the Ministry. Before doing so, I was trying to listen very carefully to the arguments put forward by him. I shall presently concentrate on the arguments advanced by him and demolish them altogether and bring out my case that there is no reason or warrant for the no-confidence motion at all

Facts speak more than anything else. What happened in Rajasthan? Let us scan the facts. In Rajasthan, the Governor was within his rights when he acted as he did. Members of the Opposition must agree that they also must swear by the Constitution. The Governor acted within the precincts of that Constitution. He had a discretionary right and he exercised it according to the constitutional processes laid down. He asked the largest legislature party to form the Ministry there. Shri Sukhadia, the leader of that party, accepted that offer and assured the Governor that the Ministry would be brought into existence and would take oath on such and such date. But we find that after that mob fury was generated. Those people who claim today that they had the necessary majority on that day and the Governor was not within his right to refuse that chance to them, could not have the patience to demonstrate that majority of theirs beyond doubt. Instead they generated mob fury and the result was that law and order was brought to pieces and the Governor had to take recourse to measures to restore peace. There was no other alternative left to the Governor.

Can the Mover deny that if the other side really had a majority, they should have waited and proved it in the Assembly that was due to meet and thereby demonstrated that Shri Sukhadia's claim was not justified? But it was evident that political action was involved. How can we stifle our conscience and wisdom?

Shri Nambiar: Was the other party called by the Governor?

Shri Krishna Kumar Chatterjee: We on this side keep an open mind on these matters. In Assam, we have got our soft feelings for the Opposition. You know in West Bengal we have quite a large number of Members, constituting the largest single party. We were called by the Governor, but we did not accept the chance. We allowed the Opposition to form the Government there.

Prof. Samar Guha (Contai): His party was not called by the Governor to form the Government; it is a misstatement he is making

Shri Krishna Kumar Chatterjee: In this country, we want the democratic process to function. (*Interruptions*). We on this side feel pleased that the Opposition groups have combined in some States to form the Government. We are prepared to ask the Central Government to give them all co-operation and opportunities to function But the situation in Rajasthan is entirely different. In that State, the Governor was within his right to call upon the largest party to form the Government, and he did so. In doing so, he was not offending any provision of the Constitution. I am prepared to challenge the Opposition to oppose me on this point. Once the President appoints a Governor, the Governor has got every right to exercise his wisdom in his own way. Are we to dictate to him the code of conduct he should follow? That is the question. I put it through you to the Opposition that if we did so, democracy would have to yield to pressure tactics; I am not prepared to use strong language and say 'blackmail'—I refrain from using that word because if I did so it would offend this augst House and the Members of the Opposition But adoption of such tactics gives rise to the fear among us that probably democracy may be endangered in the whole of India Why? While moving this no confidence motion Shri Vajpayee has offered a threat to this House, and that threat is this, that if things continue like this, there may be a day when the Central Ministry will have to face the same law and order question.

Shri A. B. Vajpayee: On a point of personal explanation. I did not hold out any threat.

Shri Krishna Kumar Chatterjee: If he did not do so, I am prepared to withdraw what I said, but somehow or other I felt there was some kind of threat. But we had witnessed tragic scenes and tragic incidents in the cow slaughter movement Therefore, we should be very cautious At this stage in this country peace has to be held the supreme duty of any Government functioning today. If any Government fails to bring peace to this country, that Government has no right to exist even for a second. That is why I welcome this move on the part of the President. By a proclamation he has allowed time to pass, so that peace may be restored there, and if the Opposition can even then muster majority, they will be allowed to function there as the Government. That is absolutely clear And from the President's Address today, it is evident that he also feels that if the Opposition can command a majority there, nothing should stand in the way to obstruct the process of their Government there.

One thing has to be remembered. The over of the no confidence motion was referring to certain newspaper reports We know how newspapers are run today and how propaganda is made. Certain newspapers are in the habit of running on certain political lines. We do not welcome it, but somehow or other this is a feature which has developed in this country, and we deeply regret this. A newspaper must be a free vehicle of opinion, so that the people can form free opinions in the country, so that democracy may develop on proper lines, but, unfortunately the paper he has quoted, *Samachar Patra* is certainly a paper which gives out certain versions which are not in conformity with freedom of thought. Therefore, we shall not give much credence to whatever *Samachar Patra* has been publicising all these days.

It is also true that in Rajasthan, when it was found by the Opposition Members that Mr Sukhadia might succeed in not only forming the Government, but running the Government as well, that some other people might join that party, an attempt was made to frustrate this by distrubing the peace of that State Rajasthan is a State where we really hope that there will be peace and prosperity because they were deprived of opportunities in the pre-independence days. Naturally we welcome the development of Raj-

asthan in a proper way, so that there may be not only prosperity and tranquillity but development as well, but that chance has not been given by the Opposition tactics. Therefore, the Governor's action was proper when he tried to maintained not only peace there, but wanted to give some time to the Opposition also to think, and to the people also to think that if peace is disturbed in this way no development is possible.

It is for a short while. Why this impatience on the part of the Members of the Opposition? If they have a majority, nobody can deprive, not even a very arbitrary Governor can deprive the Opposition Members of the right of having their own Government in that State.

It would be entirely wrong to say that the firing was not justified I am not in favour of firing, we must think on human lines, that has always been my view not only in the legislatures but also outside We do not like firing to take place, but when a situation is created where not only peace is disturbed but private security is also disturbed, something has to be done. In that tragic necessity, sometimes firing creates such a situation that human lives are lost. We deeply regret it, we are sorry for this Of course, there will be inquiry commission to go into the matter, and I therefore refrain from making observations on that, but it appears that a situation was created where firing had to be resorted to

When did it happen? Remember this, that section 144 was there On the advice of our Home Minister, Chavanji, section 144 was lifted At that psychological moment when section 144 was lifted, firing had to be resorted to because of the disturbed conditions that took place. Such a situation was there that human lives were at stake, and the lifting of section 144 was taken advantage of by the Opposition parties, and probably they generated this mob fury, and in quelling the disturbance firing had to be resorted to. Therefore, it would not be proper for the Opposition friends to suggest that firing was resorted to arbitrarily. It had to resorted to under certain tragic circumstances.

With these few words, I will again repeat that so far as the Rajpal's action in Rajasthan was concerned, it was absolutely constitutional and was in the best interests of the people there and in the best interests of the State. So, this no confidence motion before the House should be thrown out We shall certainly try to support all principles that will help the democratic development in this country on national lines. I request the House to reject the no confidence motion that is before the House.

Shri P K Deo: As a responsible party in the Opposition we should not have taken this extreme step of supporting a motion of no confidence against the Government which is hardly seven days old. We should have given time to the Government to acquit itself, but it is the compulsion of events in Rajasthan and it is the compulsion of conscience that has prompted us to support this move of censure against this Government. It is a no confidence motion and though in this motion there should be a full dress debate of the various lapses and misdeeds of this Government, I would like to pinpoint my observations on the developments that have taken place in Rajasthan and the step that has been taken by this Government to perpetuate the party in power which was thrown out at the polls and rejected as completely unworthy of holding office in that State.

Within a few hours of assuming office, the first act of the Central Government was the imposition of President's rule in Rajasthan. I would accuse the Government of committing a Hamalayan blunder. It has acted on the advice of the Governor who was a partisan, and whose recent conduct has been widely condemned by every

[Shri P. K. Deo]

paper and by every reasonable critic in this country. The 14th of March will go down in the history of democracy in this country as the blackest day. The Government advised the President to impose President's rule which actually means Governor's rule, the rule of the discredited Governor in that State, and this Governor's rule came just a day before the Assembly was about to meet. The Assembly should have been given the chance to prove the strength of the various parties, but the Assembly was denied the right of expressing its views, and just a day before the Assembly was to meet. President's rule was imposed on the people. When the Assembly was expected to pass judgment on the Governor's previous action asking Mr. Sukhadia to form the Government. They were denied their democratic right and God knows when they will be allowed to meet again The Governor's action has been universally condemned. The plea put forward was the danger to the law and order situation. I submit that this is the creation of the Central Government. It was a challenge thrown to the democratic rights of the people of Rajasthan; it was a challenge thrown to the popular will. So, there was a popular upsurge. You cannot say that they invited this trouble. The firing was deliberate. Now, there would be a judicial enquiry and the cat will be out of the bag and the entire country will be convinced and shown who was at the wrong. We know the tactics of the Congress party especially in my State since 1957. In 1957, there was a similar situation there and due to political horse trading some M.L.A s underwent a political metamorphosis for the fishes and loaves. It is well known and I do not want to repeat it here. The Congress party has tried all along to exploit the ignorance and poverty of our people and of our poor MLAs taking advantage of its position and power. They want to perpetuate themselves in office even though they were rejected by the majority in that State. We know that the demonstrations against the Government action were peaceful and it was due to the professional provacateurs a situation resulting in firing had been created. Now, the plea is put forward that there was likelihood of endangering the law and order situation and so the Central Government had to take this extreme step. By some queer coincidence the action of the Governor synchronises with the utterance of the President of the Congress Party, Mr. Kamraj that the largest party in the Assembly should be given a chance to form the Government. That was not the case previously. They adopt different standards for different States. In West Bengal and in Bihar even though the Congress was the largest single party, it was not asked to form the Government It is only when the Orissa Government declared that a commission of enquiry would be instituted to go into the conduct of the previous ministers like Biju and Biren and other corrupt people and expose their misdeeds, only then a fear complx was crated in the minds of the Congress people and a different standard was adopted to perpetuate corrupt Congress ministries in power. Another plea put forward was that independents are not to be counted; they completely ignored the affiliation of the independents. When it served their purpose in U P. the independents were counted to make the Congress a majority party. But in Rajasthan they were to be completely ignored. This is completely devoid of any foundation in law or morality or common sense. They cited the instance of Madras But at that time, though the Congress was not the majority party in Madras, the other opposition parties were not united and were not prepared to shoulder the responsibility of Government. But in this case the opposition parties were united and they had a physical majority in the House. We know that the third largest party was invited to form a Government in Kerala and Mr. Thanu Pillai who was the leader of the PSP, the third largest single party then in Kerala,

was invited to form the Government because it suited the Congress men there. In this case a different standard is being adopted. In 1965 our left communist friends came with a large majority in Kerala but they were denied the opportunity to form a Government there. May I quite from *Kate's Constitutional Law*, page 147? He says: "The King is bound to invite the leader of the majority"; Jemnings in his *Cabinet Government*, page 27 says "The leader of the majority means the person who was the backing of the numerical majority in the House." These qualifications were fulfilled by Shri Laxman Singh, Maharawal of Dungarpur who was the leader of the opposition in Rajasthan. There was a deep rooted conspiracy to sabotage the very foundation of democracy in this country I submit that the Governor should be removed from his office under article 156 of the Constitution the President should withdraw his pleasure. There should be consistency in precept and practice. Day in and day out, the Prime Minister has been saying that democratic values are to be respected but we see how these precepts are like piecrusts are broken every day. The President's rule should be revoked and the Opposition should be called to form a Government as they still command a majority in the House.

Shri Shantilal Shah (Bombay, North West): Sir, I rise to oppose this motion of the confidence especially with reference to the action of the President in issuing the Proclamation under article 356 of the Constitution. The article states that if the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. he may by proclamation assume to himself all or any of the functions of the Government.. Now, two things are necessary. Firstly, the President has to act on receipt of a report from the Governor. One does not know what that report is. But one may reasonably assume that the Governor has made a report and that the President has pursued it and considered it. The next stage then is that he has to be satisfied that a situation has arisen in which the Government cannot be carried on that satisfaction must be the subjective satisfaction of the President. And the only material on which the President can satisfy himself is the report of the Governor. Now we may assume that the President has satisfied himself. Nobody in the House has said that the President has not been satisfied and yet he has taken this action. Nobody has suggested that the President has acted on any material other than the report of the Governor. Nor did anybody suggest that the report contained statements which are false or untrue or baseless. So what is to happen in these circumstances? Here is a report which the President has received. He has considered that report. On that report the President is satisfied—it is his subjective satisfaction, not the opinion of any hon. Member of this House nor of the House taken as a whole—and then he is entitled to take that action. We may agree or disagree with it. It is his privilege and authority to take that action. Nobody else has the right to substitute his own subjective judgment. The only remedy under the Constitution would be to impeach the President and to make out a case that the President's judgment is improper or dishonest or that there was no report before him or that the report did not contain any material on which action could be taken. None of these arguments could be put forward.

15 hrs.

Now, going a little backwards, I understand that the Rajasthan Assembly has got 184 members, out of which, on the elections being held, one member was elected in two constituencies, and therefore there were 182 members elected. The composition of the parties, as I have been able to gather, is that 89 members were elected on the Congress ticket,

[Shri Shantilal Shah]

23 members were elected on the Jan-Sangh ticket, 49 on the Sawatantra ticket, eight SSP, one Communist and 15 Independents. It is now claimed that some members who were elected as independents have joined the Congress party. It is also claimed that some members who were elected on the Congress ticket have deserted the Congress party. It is further claimed that several members of different parties have combmed themselves into a single party and they claim to be a majority

Now, there are many things which in a democracy we should consider Firstly, is it proper that a person elected on one ticket should desert his party and joins another party, because when he sought election he had had represented to the public that he has based his candidature on a certain manifesto and on a policy which was laid dow by his party, it may be, in addition, his personal qualifications too, but a person who stands on the manifesto of a political party, and then changes his allegience

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली मदर): आप ऐसे लोगों को क्यों अपनी पार्टी में मिलाते हैं।

श्री मोरारजी देसाई: आपकी नकल करते हैं।

Shri Shatilal Shah: Thank you, my friend But whoever does it, if it is done by this side or that side, be is acting in a manner which is unfair to the electorate The honest thing for him, if he then feels that the Congress party is wrong, or that the Swatantra is wrong or the Jan Sangh is wrong and he wants to change his party, would he to resign his seat, put himself forward again as a candidate based on the ticket and then he could do what he likes What is happening now in this country is rather unfortunate. Members seem to change the parties without any regard to the promises or the manifastos on which they put forward their candidature. After wining a seat, a member feels that he is master of himself. He owes no party allegiance and the promise or whatever he has said to his electorate during that time is not worth anything and all that he has got to do is to say. "I shall be with this party or that party." That is very unfortunate; that does not build up democracy or faith in the honesty of the persons who are elected to the legislatures. Therefore, all parties ought to discourage the change of parties, the transfer of members from one party to another especially in the case of those who have been elected on a party ticket

Then we come to a case where a person has been elected on independent ticket It would be open to them to support the Government or not to support the Government If they agree to support either the congress party or any other party, they are still deviating from what they held out to the electorate If at that time, they were in favour of the Congress or the Jan Sangh or the Swatantra, why did the hon Member stand as an Independent? The member ought to have made his choice then, but if he wants to make his choice later let him make it publicly, face the electorate with his choice and get a fresh mandate

What is happening in Rajasthan is a consequence of what we see in many places not only after this election but even earlier: members changing their allegiance from one party to another without regard to their own honesty or loyalty, without regard to the promises they made to the electorate, without regard to the democratic forces of government But something more wonderful has happened in Rajasthan In Rajasthan, all the other parties, except the Congress now claim that they have formed themselves into a single united party. Why did they not do so before the elections, Is there anything in com-

mon between themselves, the Jan Sangh and the Swatantra? As I have read their manifestos, there are many things contradictory between the manifesto of the Jan Sangh and the Swatantra; and there are so many other things contradictory between the communists and the Swatantra, for example, or the SSP and others. These parties have come together. Having made some sort of promise to their electorates now they say, "Never mind the promises we make; we want to be in the Government and therefore we statnd together." The promises which they made yesterday to the electorate are thrown to the winds; they want to make up the differences between themselves; what for do they want to make them up? Have they found some new truth? Have they found some new principle of democracy? Have they found that they have made mistakes? If they had made mistakes, they ought to correct their own mistakes, by again going to the electorate. But it seems that the only thing that they now find is the desire to be in power. The Congress has been blamed very often for the desire to be in power and for sticking to power. A person who has no authority seeks power and tries to maintain the power. But at least those persons are of one view, of one policy. But what shall we say of those half a dozen parties who are not of one view, who have made different promises to the electorate and who now still want to say, "We shall behave in a particular way, just because we want to form the Government"? Have they told the electorate that so much of their programme, they have dropped, or that so much of the programme, they have taken up with each other? Have they got the mandate from the electorate to say that the common programme which they now have or which they will frame hereafter has the sanction of the electorate behind them? If it is not so, and in the midway, if they have changed their programmes and policies, what right have they to say now that they have the electoral backing? The backing of the electorate was given to them on certain representations made by them to the electorate. That representation they are throwing to the winds, and now they say, "Never mind the electorate. The elections are over. We do bargaining between ourselves". What is described as horse-trading, and the horse-trading may be in terms of power; maybe in terms of many other allurements. But the horse-trading is not the end of it all. If the Congress wants to remain in power, is it not true that the Opposition parties who have nothing in common among themselves want to come into power? And why do they want to come into power?

An hon. Member: To serve the people.

Shri Shantilal Shah: If they want to come into power to serve the people, the best thing for them is to ask the people and the demand here then should have been not that the proclamation should be revoked but the demand should have been that the Assembly should be dissolved, and they should take a fresh mandate; one single party should face the electorate and get their mandate. In that case, the hon. Member will be justified in saying that "we are for the people."

Shri Umanath (Pudukkotai): You could have done it in Uttar Pradesh.

Shri Shantilal Shah: The hon. Member is getting excited. Excitement is not a part of this House. (*Interruption*). Therefore, to say that it is for the people is against the facts. These gentlemen who have now formed a single party have made an alliance which cannot be described in any other terms than being opportunistic and that alliance is made only for the sake of getting power. Why should it be intended to be done? It seems that in Rajasthan, there are 15 Independents and it also seems that every party, perhaps also the Congress party—some Independents here and there will be supporting it. I am told that some members of the Congress party have deserted the Congress party and have gone to the Opposition. These are poli-

[Shri Shantilal Shah]

tically dishonest persons; they are traitors to the principles on which they stood, but I will take those others also. If the Independents were there, the Independents also ought to resign and seek a fresh mandate, or, if they had stayed, we shall have Independents in the House and wherever they feel that the Government is bringing forth a measure or laying down a policy which is correct, they as Independents should support them. If they say it is incorrect, they should oppose them, but if the man who came as Independents had bartered away his independence, because he wants to be with the party in power, then he ceases to be an Independent.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi): If you bribe those Independents to purchase them for the Congress party. (*Interruption*).

Shri Shantilal Shah: I was not suggesting that anybody was bribing anybody in terms of money or in any other way, but if the hon. Member feels that he or somebody has bribed, I accept his statement. I was only saying that whoever does this is not true to himself, and is not true to the electorate. Bribery is something which is an enemy of the electorate and democracy. Therefore, I am acting on the assumption that every member who has been elected has been acting in a manner which is apart from these mean considerations.

In these circumstances, what should the Governor do? Under article 164(1), the Chief Minister shall be appointed by the Governor. If there is a party having a clear majority, it is an easy task for the Governor. He calls on that party, barring, of course, the bribery which was referred to by the hon. member, to form a Government. In this case, one party has a strength of 89 and none of the other parties has a strength near majority. So the best thing for him would be to give a chance to that party which is nearest to the majority, so that that party may be able to carry on the Government with the Independents voting for them or against them, as the case may be.

Shri P. Ramamurti: Why was it not done in Kerala in 1965?

Shri Shantilal Shah: These questions may not be put to me. I have not done anything. It is the President who acts. I am expressing my view and I am supporting the attitude which the Government has adopted and which the President has been advised to adopt.

In this case, what is the Governor expected to do? In fact, he called upon one of the elected members to be the Chief Minister and he was to be sworn in on a certain date. Before that, the law and order situation became difficult. There was no peace in the capital city of Jaipur. There was rioting as a result of which the gentleman who was called upon to form the Government stated that he would not be able to take the oath of office along with his colleagues. The Governor again has to act and decide not merely whether there is any other party which can form the Government, but also to see whether a situation has arisen where the Government cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution". If the Governor finds that the party which has the largest number in the Assembly is not willing to form the Government and the situation is such that the Government could not be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, he makes a report to the President. The President peruses the report and if he is satisfied, then he issues the Proclamation. Nobody has attributed any motive or that the Governor's report was false in any respect or was not based on facts. We have not seen the report. So, one must presume that the Governor who enjoys the office during the pleasure

of the President also has the confidence of the President. Therefore, the Governor's report is a document on which full faith should be placed. On the basis of that report, the President comes to the conclusion that a Proclamation should be issued.

Now what has been done is that there is suspension of the legislature. If peaceful conditions return and if it becomes possible to carry on the Government in the manner envisaged by the Constitution, the Proclamation can be revoked, the Assembly can be called again and whoever can command a majority and run the Government can do so. I do not think the Heavens have fallen. The Assembly has not been dissolved, as the hon member would like it to be done The Assembly has only been suspended till normalcy is restored and firing is not necessary and if the President is satisfied on the Governor's report that the Government can be run according to the Constitution. It is a temporary measure. If the hon. members desire that the Proclamation should be revoked soon, let us all bend our energies to the restoration of normalcy in the State. That is the only basis on which the President can revoke his Proclamation and Government belonging to the Congress or any other party can be formed As long as the President is not satisfied that normalcy has returned, the only remedy is not to censure A or B but to try to restore normalcy in the State so that normal conditions can be there the Government can be run in accordance with the provisions of the Constitution.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अधिष्ठाता महोदय, मैं ने जनसंघ के नेता द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव को बहुत गौर से सुना । उनका पूरा भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की महत्ता को , उसके गौरव को और उसकी आवश्यकता को ठीक से आंके बगैर आज उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया । उन्होंने स्वयं इस बात को तसलीम किया कि इस केन्द्रीय सरकार की नीतियों के घोषित होने से पहले उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आप के कार्यालय को भज दी थी । अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी सरकार के प्रति जब लाया जाता है तो इस बात को ध्यान में रख कर कि उस सरकार की नीतियां असफल हो गयी, वह सरकार जनता के विश्वास को खो चुकी है । वह सरकार इस योग्य अब नही है कि जो कार्यभार उसे जनता ने सौंपा था उसे आगे ठीक से सम्हाल सके ।

अभी चन्द दिन पहले इस सरकार के कन्धो के ऊपर जनता ने इतना बड़ा दायित्व सौंपा है । इस देश की जनता ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाहे कुछ राज्यों के अन्दर मुख्तलिफ विरोधी दलों को उन्होंने कार्य चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी है लेकिन देश की जनता का विश्वास था कि पूरे देश के अन्दर आज की जनतात्रिक परम्परा के अन्दर आज अपनी कमजोरियो के बावजूद बहुत से उन दोषों के होते हुए भी जिनको कि हमारे विरोधी दल के भाई हमारे ऊपर लगाते है, देश की जनता ने अपना विश्वास, अपनी आस्था कांग्रेस सरकार और काग्रेस पार्टी के अन्दर दिया और इसीलिए आज केन्द्रीय सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है । मुझे दुःख है कि बगैर इस बात का ध्यान रखते हुए एक छोटे से मसले को लेकर राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया और विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अगर इस के ऊपर इस सदन को विचार करना था तो अविश्वास के प्रस्ताव के अलावा दूसरे भी प्राविधान हमारी कार्य-संचालन नियमावली के अन्दर है जिसके कि ऊपर गौर करते हुए हम इस सदन में इस के ऊपर विचार कर सकते के लेकिन जनसघ के नेता ने इस बात को ध्यान में नही रखा । उन का

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आरोप है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है वह अनुचित है । सविधान की अवहेलना की गई है। जनतात्रिक भावनाओ का उल्लघन किया गया है। उन का यह भी कहना है कि वहा जो निर्दलीय चुन कर आये थे वहा के राज्यपाल ने उन को राजनीतिक अधिकारो से वचित रखा और बगैर उन को ध्यान मे रखते हुए उन्होने कहा कि काग्रेस पार्टी जो सब से बडा दल है केवल उसे सरकार बनाने का अधिकार है। एक तरफ आप मापदड यह लगाते हैं कि राजस्थान मे निर्दलीय सद यो की अवहेलना की गयी, उन के राजनीतिक अधिकारो पर प्रहार किया गया दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप प्रस्तुत करते हैं और वहा के लिए आप यह कहते हैं कि वहा की काग्रेस पार्टी ने निर्दलीय सदस्यो की सहायता से क्यो सरकार बनाई । एक जगह आप निर्दलीय सदस्यो को उन के राजनीतिक अधिकारो से वचित रखना चाहते हैं दूसरी तरफ अगर वही निर्दलीय सदस्य अपने अधिकारो का उपयोग करते हैं तो आप वहां की काग्रेस पार्टी के ऊपर वहां के गवर्नर के ऊपर इस बात का आरोप लगाना चाहते हैं कि उन के द्वारा वहा कोई सविधान का उल्लघन हुआ है, या हत्या हुई है। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आप से कहना चाहता हू कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करने के पीछे हमारे जनसघ के नेता की केवल एक भावना है कि आज उन की आतुरता, आज शासन मे पहुचने की उन की लिप्सा आज राजनैतिक सत्ता को हथियाने की उन की होड केवल एक मात्र कारण है जिससे उन के दिल मे आज दर्द पैदा होता है जो वह इस बात का आरोप लगाते थे, काग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप सिद्धान्त के विपरीत काम करते हैं, आप सिद्धान्तो की अवहेलना करते है और दूसरी तरफ मैं आप से पूछना चाहता हू कि आप ने आज किन सिद्धान्तो की मान्यता प्रदान की है ? आप राजस्थान के अन्दर किस के साथ सरकार बनाने के इच्छुक हो रहे हैं ? आप स्वतत्र पार्टी के साथ, आप कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ और आप सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ सरकार बनाने को इच्छुक हो रहे हैं। आप ने बिहार के अन्दर क्या किया ? जिस कम्यूनिस्ट पार्टी को आप कल तक देशद्रोही समझते थे, जिस कम्यूनिस्ट पार्टी को आप चीन और रूस का दलाल समझते थे, आज उसी कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ आप हाथ मिलाते हैं, तब सिद्धान्तहीनता कौन कर रहा है ?

एक माननीय सदस्य क्या इसी लिए राष्ट्रपति का शासन कायम कर दिया ?

श्री चन्द्रजीत यादव आज जनतन्त्र के सिद्धान्त की अवहेलना कौन कर रहा है, जनता को इस बात को देखने का अधिकार है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस का फैसला जनता करेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव आज केवल शासन मे पहुचने की जो आप की होड है वही राजस्थान मे आप के अन्दर दर्द पैदा कर रही है। हो सकता हैं कि

श्री अटल बिहारी वाजपेयी सभापति महोदय, माननीय सदस्य इसका जवाब दें कि क्या यह सच है कि वह स्वयम् पहले कम्यूनिस्ट पार्टी मे थे।

श्री चन्द्रजीत यादव श्री वाजपेयी यह प्रश्न उन सदस्यो से पूछें जो चुनाव से जीत कर आये हैं जिन्होने काग्रेस

Shri Nambiar: The hon Member is not required to give a judgment over the Communist Party The people

have given their judgment over the Communist Party. We are here elected by the people. The people know who we are. The hon. Member is not here called upon to sit in judgment over the Communist Party. Let him better talk less of that. Let him know what he is talking here. (*Interruption*).

Shri Randhir Singh (Rohtak): We have won by a greater majority than what you have got.

Shri Nambiar: He is saying that the the Communist Party is an agent of Russia and China. Please put an end to this rot.

Shri Chandra Jeet Yadav: I am not saying anything like that. It is the Jan Sangh that has made that allegation. I am not saying that the Communist Party is an agent of Russia or China. It is these friends who have always alleged like that.

सभापति महोदय, मैं अभी आप से कह रहा था कि जो स्थिति आज राजस्थान के अन्दर पैदा हुई है आप यह कह सकते हैं कि मैं उन लोगों में से हूं जो कि इस बात को मानते हैं कि जब वहां के राज्यपाल ने कांग्रेस दल के नेता को इस बात के लिये निमंत्रित किया कि वह आ कर सरकार बनायें और कांग्रेस दल के नेता ने वहां की विशेष उत्पन्न परिस्थितियों के अन्दर, जब कि सामान्य स्थिति नही रह गई और वहां ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन खराब होने लगी, यह उचित नहीं समझा और अपने को समर्थ नहीं पाया कि वह सरकार बना सके, तो ज्यादा अच्छा होता अगर राजस्थान के राज्यपाल उसके बाद संयुक्त विधायक दल के नेता को निमन्त्रित करते और उन से कहते कि हालांकि कांग्रेस पार्टी सब से बड़ी पार्टी है लेकिन उस के नेता अपने को समर्थ नही पाते कि वह सरकार बनाये, इस लिये आप अपनी सरकार बनाये। यह ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं इन बातो मे नही जाना चाहता।

मैं आप से कहना यह चाहता हूं कि आज केन्द्रीय सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उस ने संविधान की अवहेलना की तथा जनतन्त्र की परम्पराओं की अवहेलना कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम आंख बन्द कर के बैठे रहेंगे और इन बातों पर गौर नही करेंगे ? हमारे कुछ नियम बने हुए हैं, विधान बना हुआ है, और हमें उन के अनुसार काम करना होता है।

जब हमारे विरोधी पक्ष के नेताओं ने इस बात की माग की कि नया ससद् बुलाया जाना चाहिये, पुराने ससद् को नही बुलाना चाहिये, तो हालांकि हम पुरानी संसद् को समन कर चुके थे, लेकिन उन की भावनाओं का आदर करते हुए जनतन्त्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए, ज्यादा अच्छी परम्पराओं की स्थापना करने के हेतु हम ने उन के सुझाव को माना उस का आदर किया। क्या यह जनतन्त्र की हत्या है ? यह मैं आप से जानना चाहता हूं। यहां पर मांग की गई कि हमारे इस सदन का अध्यक्ष चुना जाये और चुने जाने के बाद उसे अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिये। कांग्रेस पार्टी ने जनतांत्रिक भावनाओं में आस्था होने का कारण उसका आदर किया। उस के सदस्य ने जिस को इस सदन ने बहुमत से अध्यक्ष पद पर बिठलाया है और जिस का 35 वर्षों से इस महान् पार्टी से सम्बन्ध था केवल जनतंत्र की भावनाओं का आदर करने के लिये इस बात को स्वीकार कर लिया ताकि इस देश में जनतंत्र की जड़ें मजबूत हों और उसने पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। क्या यह जनतंत्र की हत्या है ? क्या यह जननंत्र मे हमारी आस्था और विश्वास का द्योतक नहीं है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राजस्थान की बात कीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव कृपया आप सुने। आप के अन्दर यह सहनशीलता भी होनी चाहिये कि जनतंत्र के अन्दर आप दूसरो की बात सुनें।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हम ने इस बात का आदर किया। राजस्थान के अन्दर जो स्थिति पैदा हुई, उस के सम्बन्ध में राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश की। उन की सिफारिश थी कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति को इस बात के लिये परामर्श दे कि राजस्थान के अन्दर विधान सभा भंग कर दी जाये। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रपति को यह सलाह नहीं दी कि विधान सभा भंग कर दी जाये। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुमकिन है कि सामान्य स्थिति पैदा हो जाये, मुमकिन है कि इस बीच में फिर हमारी चुनी हुई पार्टियां इस योग्य हो जायें कि वहां लोकप्रिय सरकार की स्थापना कर सकें, विधान सभा भंग नहीं की गयी। यह कहा कि विधान सभा केवल कुछ समय के लिये स्थगित रहेगी, इस के लिये अवसर देने के लिये।

मैं विरोधी दलों से कहना चाहता हूं कि अगर वह वहां सरकार बनाने के इच्छुक हैं, अगर वे चाहते हैं कि दुबारा सामान्य स्थिति पैदा हो, तो उन का कर्तव्य है कि वे उत्तरदायी विरोधी दलों की तरह से काम करना सीखें। राजस्थान में सामान्य स्थिति पैदा करने में सहयोग करें। अगर वहां सामान्य स्थिति पैदा होती है तो हमारे राष्ट्रपति को फिर इस बात का अवसर मिलेगा कि वह इस पर पुनर्विचार करें और अगर वहां लोकप्रिय सरकार बनने की स्थिति आये तो उस के लिये अवसर दें क्योंकि वहां की विधान सभा भंग नहीं की गई है।

इसलिये आज की स्थिति बहुत गम्भीर है जहां आप शासक दल पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में जनतंत्र की जड़ों को मजबूत होना है अगर इस देश के अन्दर संविधान की रक्षा करनी है मर्यादाओं की रक्षा करनी है अगर इस देश के अन्दर हम जनतांत्रिक मर्यादाओं को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम को केवल आरोप प्रत्यारोप की भावना से नहीं; हम को ठंडे दिल से और देश के अन्दर उत्पन्न आज के राजनैतिक और आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ेगा।

आप को इस बात की सराहना करनी चाहिये थी कि आज जब हमारे मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग कर के हमारे देश के कई राज्यों में ऐसी स्थिति पैदा की कि विरोधी दलों की सरकारें बन सकें, हमारे प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री होने के बाद पहला वक्तव्य इस बात के लिये दिया। उन्होंने इस बात का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनतंत्र की जड़ें हमारे देश में मजबूत होती दिखाई पड़ती हैं, हमें इस बात की परीक्षा करने का अवसर मिलेगा कि हम किस तरह से शासन सत्ता को सम्भाल कर के, विरोधी पक्ष में बैठ कर एक दूसरे से सहयोग कर के इस देश में अपने को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आप उसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। बजाय इस के कि आप उसकी सराहना करते, बजाय इस के कि इन परम्पराओं को पुष्ट करने के लिये, मजबूत करने के लिये देश के अन्दर एक वातावरण पैदा करते, एक स्थिति उत्पन्न करते, आप ने जनतंत्र का मखौल बनाया इस अविश्वास प्रस्ताव को ला कर के। इस लिये हम को इस पर गौर करना चाहिये।

यहां उत्तर प्रदेश का भी उद्धरण दिया गया। मैं इस लिये कहना चाहता हूं कि मैं उस प्रदेश से आता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बावजूद इस के कि विरोधी पार्टियों ने सारे गैरउसूली तरीकों से वहां पर गठबन्धन किया, जनसंघ के सिद्धान्त में, कम्यूनिस्ट पार्टी के सिद्धान्त में, स्वतन्त्र पार्टी के सिद्धान्त में, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्त में, कोई

मेल नहीं है लेकिन सारी बातों को ताक पर रख शासन सत्ता प्राप्त करने के लिये सिद्धान्तहीन गठबन्धन किया गया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कांग्रेस के भीतर भी खुद दस पार्टियां हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : हो सकता है, लेकिन पहले आप अपना दामन देखिये, उस के बाद उंगली उठाइये । शासन सत्ता प्राप्त करने की होड़ में वहां सारे उसूली सिद्धान्तों की हत्या करना . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम ने अपने मतभेदों को निकाला इमानदारी से . . .

श्री चन्द्रजीत यादव : पहले आप मेरी बात सुन लीजिये, मैं बोल रहा हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य मुझ से सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जो आप ने उठाये है । इसलिये मैं कह रहा हूं कि बावजूद इन सब बातों के चूंकि वहां की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सब से बड़े राजनीतिक दल के रूप में भेजा, उत्तर प्रदेश के निर्दलीय सदस्यों ने इस बात को उचित समझते हुए कि उस राज्य की जनता 8 करोड़ जनता एक स्थायी सरकार बनाना चाहती है, अपना समर्थन कांग्रेस दल को को देने का आश्वासन दिया , और इस तरह से वहां पर कांग्रेसी सरकार बनी । मैं श्री वाजपेयी से जानना चाहता हूं कि इस में संविधान की किस धारा का उल्लंघन हुआ ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आप को जवाब दूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप को जवाब देने का हक है, लेकिन अभी उस का अवसर नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति, महोदय या तो माननीय सदस्य मुझे सम्बोधित करेंया आप को क ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य पाल ने संविधान की किस धारा का उल्लंघन किया है । उत्तर प्रदेश में बहुमत किस का है, क्या अभी इस को और प्रमाण चाहिये । परसों उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ । सारे विरोधी दल के लोगों ने मिल कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया । लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 236 मत प्राप्त हुए हैं और सारे विरोधी दलों के उम्मीदवार 188 मत प्राप्त होते हैं । तब इस में शक कहां रह गया कि वहां पर किस का बहुमत है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हरियाना में क्या हो रहा है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या इस प्रकार की बहुमत प्राप्त सरकार को भी चुनौती दी जायेगी और यह कहा जायगा कि यह बहुमत नही है; जनता की भावनाओं का उल्लंघन किया गया है, या इस सदन में चुनौती दी जायेगी कि हम इस को सड़कों पर देखेंगे, माननीय सदन के बाहर देखेंगे मैं समझता हूं कि इस देश की जनता की बुद्धि में आज इतनी परिपक्वता है, इस देश में जनतंत्र आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि इस प्रकार की चुनौतियों को हस्यास्पद बना कर रद्दी की टोकरी में रख देगी हम इसका जवाब आप की भाषा में नहीं देना चाहते है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज इन बातों पर हमें ठंडे दिलसे गौर करना चाहिये ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने शुरू में कहा देश के अन्दर गम्भीर राजनैतिक और आर्थिक स्थिति है । हमारा जनतंत्र एशिया का और दुनिया का बहुत बड़ा जनतंत्र है । आज वह कसौटी पर चढा हुआ है । अगर हम देश में जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो शासक दल को और विरोधी पक्ष को भी दोनों को यह बहुत जिम्मेदारी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

के साथ देश की विकट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। अगर शासक दल जनतान्त्रिक भावनाओं का आदर करता है तो आज विरोधी दलो का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उस में सहयोग करे और अपना समर्थन प्रदान करने की कृपा करे। यदि ऐसा होगा तभी देश में आज जनतंत्र मजबूत होगा।

मैं आपके द्वारा सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान मे जो स्थिति पैदा हो गई है और जिस को ले कर यह अविश्वास का प्रस्ताव मुख्य रूप से आज यहा लाया गया है विरोधी दल की ओर से, हम और विरोधी दल वाले भी इस बात मे सहायता करे कि राजस्थान में एक सामान्य स्थिति पैदा हो और अगर वहा पर समान्य स्थिति पैदा हो जाती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज केन्द्रीय सरकार का जो रुख है उस में परिवर्तन होगा और राष्ट्रपति महोदय भी वहा समान्य स्थिति पैदा होने के बाद फिर इस बात का प्रयास करेंगे कि वहां एक पापूलर सरकार बन सके और अगर कांग्रेस पार्टी के नेता फिर ऐसा करने मे अपने आपको असमर्थ पाते हैं तो निश्चत रूप जो सयुक्त विधायक दल बना हुआ है उसके नेता को बुलाया जाना चाहिये और उनको सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिये। मै चाहता हू कि इन बातों पर आप ध्यान दे और प्रजातंत्र की जो मर्यादा है उस का पालन सब करे। हम प्रजातंत्र की मर्यादा की स्थापना करना चाहते है और वह होगी, लेकिन इन बातो की ओर आप अवश्य ध्यान दे।

अन्त में मैं वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस अविश्वास के प्रस्ताव को वापिस ले लें और देश के अन्दर, विशेषकर राजस्थान के अन्दर एक सामान्य स्थिति पैदा करने में सहायता करे।

Mr. Chairman: I have very few names from the opposition side. Would Shri S. M. Banerji like to speak now?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि श्री चन्द्रजीत यादव के फौरन बाद मुझे बोलने का आपने मौका दिया है। मैं भी उत्तर प्रदेश से तीसरी मर्तबा चुन कर आया हू। मैं समझता हू कि राजस्थान की परिस्थिति जो वहा के गवर्नर साहब ने बिगाडी है आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हो सकती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने और उत्तर प्रदेश के विरोधी दलो ने, उनके नेताओ ने, काफी संयम और धैर्य से काम लिया है। अगर खून की होली के बाद सरकार अपना फैसला बदल सकती है तो वह खून की होली उत्तर प्रदेश में भी खेली जा सकती थी, लेकिन खेली नही गई।

राजस्थान से 93 सदस्य जो यहां पर आए थे उनको मैंने भी देखा था और राष्ट्रपति जी ने भी उनका निरीक्षण किया था, उनसे बातचीत की थी। हमारे गृह मन्त्री जी भी उस समय वहा पर थे। मैं समझता हू कि आज प्रजातान्त्रिक उसूलो के आधार पर जो सरकार बनी है वह अपने आपको उन उसूलो के आधार पर चलायेगी। यह कह देना कि राष्ट्रपति जी के निरीक्षण के बाद भी हम अपने फैसले को नही बदलेगे किसी भी दृष्टि से सही नही है। जो कुछ राजस्थान मे हुआ है उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई करना ठीक नही है। आखिर राजस्थान में हुआ क्या है ?

आज सुबह जब यह सवाल इस सदन में रखा गया था तो उस वक्त मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं उसका प्रयोग न करू। मैंने "रेप आफ डेमोक्रेसी" शब्दो का प्रयोग किया था। हम रेप आफ डेमोक्रेसी की बात को सुना करते थे लेकिन मुझे मालूम नही था कि विरोधियों की तादाद रूलिंग पार्टी के सदस्यो की तादाद से ज्यादा होगी लेकिन फिर भी वहा पर चुने हुए नुमाइन्दो को मौका नही दिया जाएगा कि वे सरकार बनाये बल्कि वहा पर एक ऐसे व्यक्ति को बुला कर कहा जाएगा कि वह सरकार बनाये जिस का वहां पर बहुमत नही है और

जब वह सरकार बनाने में समर्थ न हों तो एक ऐसी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न कर दी जाए कि केन्द्रीय हुकुमत अपने बाहुबल या बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति जी को यह सलाह दे कि वह हस्तक्षेप करे। लेकिन ऐसा किया गया है। मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा रेप आफ डेमोक्रेसी और कोई नही हो सकती है। 30 या 31 व्यक्तियों को मारा गया। मेरे मित्र महाराजा कर्णी सिंहजी ने कहा कि छोटे छोटे बच्चो के ऊपर गोली चलाई गई। छोटे छोटे बच्चो को, स्कूलो के विद्यार्थियों को जेल के सीखचो मे रखा गया। मैं नही समझता हूं कि यह इस सरकार के लिए कोई नई बात है। मै आपको बतलाना चाहता हू कि आज भी उत्तर प्रदेश में 13-13 14-14 साल के बच्चो के ऊपर भी दस दस मुकदमे चलाये जा रहे है। जिस भ्रष्टाचार के आधार पर, राजनीतिक रिश्वतखोरी के आधार पर उत्तर प्रदेश मे सरकार बनी है वह सरकार उन मुकदमो को वापिस लेगी, ऐसा मैं नही समझता हू। सरकार उनको सजा देने वाली है।

राष्ट्रपति जी ने राजस्थान के मामले मे जो हस्तक्षेप किया है, उसको लेकर यह कहा गया है कि सस्पेंड किया गया है, असेम्बली को भग नही किया गया है, उसे तो सस्पेंड किया गया है और सस्पेंशन तो अच्छी बात है। मैं समझता हू कि सभा के जिन सदस्यो ने कहा कि सस्पेंशन अच्छी चीज है अगर उनको दो दो महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए तो उनको मालूम होगा कि सस्पैंडिड मैम्बर की क्या हालत होती है। हिन्दुस्तान के दो तिहाई प्रान्तो में आज कांग्रेसी शासन खत्म हो चुका है। मैं समझता हूं कि बिहार मे, केरल मे, बंगाल मे, मद्रास में, उड़ीसा आदि मे शायद कांग्रेसी सुबह उठ कर अपने बदन को नोच कर देखते होंगे कि वाकई में वे जिन्दा हैं या नही हैं। ऐसी हालत उनकी हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से रेप आफ डेमोक्रेसी अगर चलता रहा हिन्दुस्तान में तो हमारे कांग्रेसी भाई सुन लें कि हो सकता है कि सन 1972 के चुनाव तो दूर है लेकिन उससे पहले ही शायद कांग्रेस का आखिरी जनाजा बिना कफन के मरघट मे चला जाए। और वह जाने वाला है। जो कुछ राजस्थान में हुआ है उसके सामने आपका सिर शर्म मे झुक जाना चाहिये। हमारी प्रधान मन्त्री जी ने आज कहा था कि यह सही फैसला है। मै उनकी इस बात को चुनौती देता हू। आप देखे कि उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया है? वहा पर 198 कांग्रेसी सदस्य चुन कर आए। विरोध दल वालों की तरफ से 215 की लिस्ट गवर्नर साहब को दी गई लेकिन उनको वहा सरकार बनाने का मौका नही दिया गया। कांग्रेस को दे दिया गया। इसी वजह से बार बार हम कहते हैं कि गवर्नर कम से कम ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो किसी दल से सम्बद्ध न हो। उसके बाद नेक राम शर्मा की बात आई। नेक राम शर्मा जी को हम नेक समझते थे। लेकिन बदकिस्मती देश की और उत्तर प्रदेश की कि वह नेक चाल चलनी में नही रहे और श्री सी० बी० गुप्त के अमर में आ गए, पुलिस की मदद से। पुलिस खडी हुई थी, पी० एम० सी० की लारियां खडी हुई थी और जब लोग पूछते थे कि क्या बात है तो कहा जाता था कि यह कांग्रेस में चले गये हैं। उस वक्त लखनऊ का नजारा देखने लायक था। नेक राम जी की हिफाजत कौन कर रहे थे? उनके वोटर नही, पुलिस की तरफ से—हो रही थी और पी० ए० सी० की लारिया वहां खड़ी हुई थी। जब लोग पूछते थे कि ये पुलिस को लेकर क्यो आए तो कहते थे कि नेक राम कांग्रेस मे चले गये है। ये तरीके मैम्बरों को खरीदने के वहा पर अपनाये गये हैं। मैं चाहता हू कि पूरी जाच हो, निष्पक्ष जाच हो, अदालती जाच हो कि जो 60 या 65 लाख रुपया, चोर बाजारी का पैसा चन्द्र

[श्री स० मो० बनर्जी]

भान गुप्त जी को उनकी वर्ष गांठ के अवसर पर दिया गया है, वह कहां और कैसे खर्च हुआ है। उसका आधा पैसा मैम्बरों को खरीदने के लिए खर्च किया गया है, पचास पचास और साठ साठ हजार रुपया दे कर मैम्बर खरीदे गए हैं। मैं एक आजाद उम्मीदवार हूं। लेकिन लानत है ऐसे आजाद उम्मीदवारों को जो वामपंथी मोर्चे की मदद से चुनाव जीत कर आए और कांग्रेस की गोद में चले गए। कुछ कांग्रेस की गोद में इसलिए चले गए कि उनको टिकट मिल जाएगा। कोई चुनाव के पहले और कोई चुनाव से साल भर पहले चले गए। हमारे चंद्र जीत यादव जी साल भर पहले चले गए। वह अक्लमन्द आदमी थे। कुछ लोग अभी चले गए।

श्री प्रेम चन्द्र वर्मा (हमीरपुर): वह बात वहां असैम्ली में कहिये।

श्री स० मो० बनर्जी: इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करना चाहिये था। उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरीके से क्यों बनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में इन्टरवैंशन करने में नाकामयाब रही, उस ने हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि वह इमर्जेन्सी के आधार पर कांस्टीट्यूशन की धारा के अनुसार गवर्नर को डायरेक्शन इस्यू कर सकती थी कि वहां पर किस तरीके से सरकार बने। उस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह समझती थी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मरकज रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत को, कांग्रेस की इमारत को विरोधी दल के लोग तोड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस की 65 साला पुरानी पवित्र इमारत को, गांधी जी की इमारत को कौन तोड़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि श्री बीजू पटनायक उस इमारत की छत को तोड़ रहे हैं और श्री सी० बी० गुप्त उस के लेहन को तोड़ रहे हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी सीमेंट की बोरी ले कर सारे हिन्दुस्तान में घूम रही हैं कि उस इमारत की मरम्मत की जाये। लेकिन अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब तो उस का फ़ातिहा पढ़ने की जरूरत है, मर्सिया पढ़ने की जरूरत है।

एक माननीय सदस्य: आप को इस की क्या फिक्र है?

श्री स० मो० बनर्जी: मुझे इस लिए फ़िक्र है कि कि मैं हिन्दुस्तान का नागरिक हूं। अगर आप मुसीबत में हैं, तो आप की मदद करना मेरा फर्ज है।

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस में आ जाइये।

श्री स० मो० बनर्जी: मुझे कांग्रेस में आने की जरूरत नहीं है। मैं तो इन लोगों पर तरस खाता हूं।

श्री रामसेवक यादव: कांग्रेस में महाराजा कश्मीर आयेंगे, महाराजा बड़ोदा आयेंगे। उस में गरीब आदमियों के लिए जगह कहां है?

श्री क० मा० तिवारी (बलिया): माननीय सदस्य स्वतंत्र उमीदवार के रूप में खड़े हुए थे और वह कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन को कितना रुपया मिला था?

श्री स० मो० बनर्जी: माननीय सदस्य अखबार तो पढ़ते होंगे। अगर वह अंग्रेजी नहीं समझते, तो वह हिन्दी के अखबार पढ़ें। मैं कम्युनिस्ट ब्लाक में बैठूं या सोशलिस्ट ब्लाक में, लेकिन 1947 के बाद मैं खद्दर पहन कर बेईमानी करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं खद्दर उस वक्त पहनता था, जब खद्दर पहनने वालों पर लाठियां चलती थीं। जब से उन को परमिट मिलने लगा है मैं ने खद्दर पहनना छोड़ दिया है।

मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक करप्शन हुआ है जो राजनीतिक लाइबरी और रिश्वतखोरी हुई है सेंटर की एक टीम, पार्लियामेंट के मेम्बरों का एक कमीशन, उस की एन्क्वायरी करे। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है विधान सभा में जिन दलों के पक्ष में 93 सदस्य हैं उन को सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए। सुखाड़िया साहब को वहां पर सरकार बनाने का कोई हक़ नहीं है। मैं महाराजा बीकानेर के इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि राजस्थान में सुखाड़िया राज में हुए करप्शन की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाये।

मैं आशा करता हूं कि इस अविश्वास-प्रस्ताव पर बहस ख़त्म होने से पहले प्रधान मंत्री यहां आ कर यह एलान करेंगी कि राजस्थान में राष्ट्रपति जी ने वहां पर अपने शासन को रिवोक कर दिया है और वहां पर अब जनतांत्रिक सरकार बनेगी जो कि विरोधी दलों की सरकार होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास-प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री पहाड़िया (हिंडौन): सभापति महोदय, लोक सभा का विधिवत् कार्य प्रारम्भ होने पर ही विरोधी दलों द्वारा केन्द्रीय सरकार में अविश्वास-प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव की मूल भावना इस के प्रस्तावक श्री बाजपेयी जी के भाषण से झलकती है जो कि जनसंघ के एक बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने अपने भाषण में राजस्थान के अलावा और किसी विषय के बारे में कुछ नहीं कहा। उस से ऐसा लगता है कि श्री बाजपेयी की नज़र अब पूरी तरह से राजस्थान की ओर लगी हुई है। शायद उन को इस बात का विश्वास हो गया है कि हमारे उन साथियों के सहयोग से जो थोड़े दिन पहले ही हम से पृथक हुए हैं राजस्थान की सत्ता जनसंघ के हाथ में आ जावेगी। चुनावों से पहले माननीय श्री बाजपेयी और उन के दल के अन्य उम्मीदवारों ने राजस्थान के बारे में क्या क्या कहा था, क्या क्या आशायें प्रकट की थी मैं उन्हें उस की याद दिलाना नहीं चाहूंगा:

एक माननीय सदस्य: दिला दीजिए।

श्री पहाड़िया: उन को याद आ गया होगा।

राजस्थान की घटनाओं के सम्बन्ध में स्वयं उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसी को ले कर बोलूंगा। सब से पहली बात उन्होंने यह कही कि भारत मे केन्द्रीय सरकार के प्रथम मंत्री-मंडल ने सब से पहला फ़ैसला राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के बारे मे किया। उन का सारा भाषण इसी बात के इर्द-गिर्द घूमता रहा। उन्होंने अपने भाषण मे इस बात की कोई चर्चा नहीं की कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए जिससे राजस्थान के राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार को वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिए कहना पड़ा। उन्होंने इस बात का भी कोई जिक्र नहीं किया कि राजस्थान की जनता की क्या भावनाये थी।उन्होने हवाला दिया केवल जयपुर के एक शहर का। मैं मानता हूं कि जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है। मैं इस बात का भी जिक्र नहीं करता कि जयपुर मे हम विधान सभा की चारों सीटें हार गए।

श्री ओंकार लाल बेरवा: कोटा में क्या हुआ?

श्री पहाड़िया: जो कुछ हंगामे हुए जो कुछ हुल्लड़ हुए.....

श्री रामसेवक यादव: क्या माननीय सदस्य मन से बोल रहे हैं?

श्री पहाड़िया: यह तो माननीय सदस्य अपने मन से पूछें।

श्री रामसेवक यादव: वह जो कुछ बाहर कहा करते हैं उस को क्यों नहीं कहते?

श्री पहाड़िया : माननीय सदस्य ने उन सब बातों का हवाला देते हुए यह प्रकट करने की कोशिश की कि राजस्थान में जो कुछ हुआ वह गैर-कानूनी तरीके से और असंवैधानिक ढंग से हुआ। जो कुछ नहीं कहना चाहिए था वह भी उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के बारे में कहा। उन्होंने राज्यपाल पर पक्षपात का आरोप लगाया और यह आरोप भी लगाया कि शायद उन की इतनी काबलियत नहीं है कि वह राजस्थान के राज्यपाल रह सकें। वह इस से भी आगे बढ गए और उन्होंने राज्यपाल को उन के पद पद से हटाने की बात कह डाली। मैं उन तर्कों में नहीं जाना चाहता हूं। राजस्थान का राज्यपाल या किसी दूसरे प्रदेश का राज्यपाल किस तरह से हटाया जाना चाहिए और किस तरह से नियुक्त किया जाना चाहिए वह एक अलग सवाल है लेकिन उन्होंने यह कहा कि राज्यपाल का निर्णय पक्षपातपूर्ण था। उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि विरोधी दलो के पास बहुत बड़ा बहुमत था और इस लिए संयुक्त दल को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए था।

मैं निवेदन करना चाहता हू कि श्री बाजपेयी अखबार तो मुझ से ज्यादा पढ़ते होंगे और राजस्थान के जनसघ के लोगो की ओर से उन को सूचना भी उपलब्ध होती होगी। जो माननीय सदस्य कोटा से चुन कर आए हैं मैं उन को भी कुछ आकडे बताना चाहता हू।

श्री ओंकार लाल बेरवा : 18 सीटो मे से हम ने 16 जीती हैं और दो हारी हैं।

श्री पहाड़िया : माननीय सदस्य यह भी याद करे कि कौन जीता है।

इस समय राजस्थान की विधान सभा मे 184 सीटे है जिन मे से 89 सीटें राजस्थान की जनता ने स्पष्ट तौर पर काग्रेस को दीं। उन मे से एक सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने दो सीटो से चुनाव लड़ा था और जो दोनो पर जीत गए। वहां पर कुछ विरोधी दलों ने इस बात की कोशिश की कि पुराने सामन्ती तत्वों की सहायता से राजस्थान में सत्ता को हथिया लें। उनकी जो सबसे बड़ी नेत्री हैं उनका बहुत बड़ा ग्लैमर न केवल इस हाउस में है बल्कि बाहर भी है। उन का बहुत बड़ा प्रभाव न केवल राजस्थान मे है, न केवल हिन्दुस्तान में है बल्कि ऐसा लगता है कि शायद वह दुनिया के राजनीतिक पटल पर छा रही हैं। मैं महारानी गायत्री देवी की बात कर रहा हूं। वह जयपुर की महारानी है, राजस्थान की महारानी नही। उन्होने जयपुर से लोक सभा और विधान सभा के चुनाव लडे। वह विधान सभा के चुनाव मे नौ हजार वोटो मे हारी। यह परिणाम चुनाव आयोग ने घोषित किया है। इस पर भी माननीय सदस्य इस को कुबूल करे या न करे, यह मेरे बस की बात नही है। वोटो की गिनती गिनी गई है। उस मे जाहिर होता है। इसलिए उनका कितना असर राजस्थान के अन्दर है जयपुर शहर के बाहर, जयपुर की भतूर्व रियासत के बाहर है, इसका पता इसी बात मे लग जाता है।

तो श्रीमन, मै निवेदन कर रहा था 184 म 79 सीटे काग्रेस को मिली। 49 सीटे स्वतन्त्र पार्टी को मिली, 22 सीटें जनसघ को मिली और 8 सीटे समोपा को को मिली। वह आठ सीटे भी किस तरह से मिली? यादव साहब बहुत कह रहे है, माफ कीजिएगा, कहना नही चाहता था, जरा कुछ तो साचा करो, महाराजा भरतपुर का सहयोग आपको प्राप्त न होता तो आपको कितनी सीटे मिलती यह आप अन्दाजा लगा लो। 15 सीटे निर्दलीय को मिली। निर्दलीय सदस्यो के बारे मे एक कट्रोवर्सी पैदा हुई है। उन के बारे मे मैं कुछ निवेदन नही करना चाहता। वह 15 निर्दलीय कौन है? 22 जनसघ के कौन है? 49 स्वतन्त्र पार्टी के कौन है? अगर वहा बैठे हुए नेता अपने दिल पर हाथ

रखकर टटोलें, अपने दिमागों को राजस्थान में दौड़ायें तो पता लग जायगा ।

मैं कहना नहीं चाहता पर वह सब कांग्रेस की जूठन हैं जिन को हमने टिकट नहीं दिया, जिनको हमने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, किसी के खिलाफ रिश्वत के आरोप, रिश्वत में पकड़े जाने के आरोप, रंगे हाथ पकड़े गए, वह हमारे पास आये, हम ने उनको रिजेक्ट कर दिया तो वह इन को मिले और इन्होंने उनको खड़ा कर दिया । श्रीमन, मैं मानता हू कि राजस्थान की जनता ने जो फैसला किया है वह हमसे छिपा हुआ नहीं है । लेकिन इसके साथ साथ मैं वाजपेयी जी का याद दिलाना चाहता हू कि जितने प्रतिशत मत राजस्थान में कांग्रेस को 1962 में मिले थे, उससे दो प्रतिशत ज्यादा इस बार मिले है । पहले 40 प्रतिशत मिले थे, अब 42 प्रतिशत मिले हैं

श्री ओंकार लाल बेरवा झूठ, सफेद झूठ । (व्यवधान) 37 प्रतिशत कांग्रेस को मिले है और 42 प्रतिशत हम को मिले है ।

श्री पहाड़िया : बहुत अच्छी बात है । आप अपनी बात कहिएगा जब आपको मौका मिले ।

तो यह आकड़े इस बात का साबित करते हैं कि राजस्थान की जनता जयपुर में नहीं रहती मेरा तर्क यह था कि हंगामा जो हुआ वह जयपुर में हुआ । वाजपेयी जी ने जो हवाला दिया वह जयपुर का दिया है । मैं ने निवेदन किया कि जयपुर शहर एक शहर है राजस्थान का, राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान नहीं है। इसलिए जयपुर के अन्दर जो कुछ होता है वह राजस्थान की जनता का काम नहीं कहा जा सकता । और मैं आपको यह भी बताना चाहता हू कि जयपुर शहर जिसकी आबादी पाच लाख है उस के अन्दर जयपुर के मूल निवासी 2 लाख है । (व्यवधान) बाकी जयपुर की चहारदिवारी के बाहर जो लोग रहते हैं जो कि सर्विसेज में काम करते है, जो कि विद्यार्थी कालेजों में पढते है या जो ईंट फैक्टरी में मजदूर काम करते हैं आज तक किसी आन्दोलन में उन भाइयों की मदद न जनसघ को मिली, न स्वतत्र पार्टी को मिली । (व्यवधान) जो लोग आये वह जयपुर के भूतपूर्व राजघराने के प्रभाव में प्रभावित हो कर, उन के प्रभाव में आकर आये और मैं यह कहना चाहता हू बहुत निश्चित रूप से, आप को बुरा लगे तो लगे, आप कहिए तो मैं सबूत दे सकता हू, एक नहीं हजार आदमी पेश कर सकता हू, हजार मैं जानबूझ कर कह रहा हू, मैं सौ नहीं कह रहा हू, हजार आदमी मैं पेश कर सकता हू जिन को पाच पाच रुपये दिए गये इस बात के कि वह उनके जलूस में शामिल हों । (व्यवधान)

श्री ओंकारलाल बेरवा : झूठ, सफेद झूठ ।

श्री पहाड़िया : जिन से आपका कोई ताल्लुक नहीं (व्यवधान)
आप को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह तरह से आपने कार्यवाही की

Shri Tenneti Viswanatham (Visakhapatnam) On a point of order, Sir, the hon Member is speaking something and I hear the translation. But the interruptions are not translated and I am not able to follow the trend of the discussion

श्री पहाड़िया : मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में जो कुछ हुआ वह राजस्थान में नहीं हुआ वह केवल जयपुर शहर के अन्दर हुआ ।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हू कि वह ऊधमगर्दी जो जयपुर शहर के अन्दर हुई वह सारे राजस्थान में भड़कने

[श्री पहाड़िया]

वाली थी। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस स्थिति को यहां पर साफ करें कि 7 तारीख को जो गोलीकाड हुआ उसके बाद क्या उन के पास इस बात के समाचार नही हैं कि विरोधी दल के राजस्थान के बहुत जिम्मेदार एक नेता ने जयपुर मे बैठ कर के उन की पार्टी के हेडक्वार्टर से राजस्थान की सब ब्राचो को इस बात के तार दिये कि 14 तारीख को या तो वैधानिक तरीके से सत्ता हमारे पास आती है अन्यथा राजस्थान की विधान सभा के अन्दर खून खराबी की जाय, कांग्रेस के लोगो को मारा जाय और जैसे भी हो सत्ता को हथियाया जाय । श्रीमन, मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हू कि आपके मार्फत कि वह इस स्थिति को साफ करे। एक बात और कहना चाहूगा ।

उसमे उन्होने कहा है कि विरोधी दल के सदस्यों को मिलाकर के हमने इस बात की कोशिश की थी । हमने तो कोशिश की थी, हमारे ही सदस्य थे, किसी वजह से आपके पास चले गये, उस की वजह से। लेकिन मैं जानना चाहता हू कि राजस्थान मे जनतन्त्र की हत्या कौन कर रहा है ? महाराजा साहब करनी सिह जी जिन की मैं बहुत इज्जत करता हू उन्होने भी इस बात का बहुत खुलासा करने की कोशिश की लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हू कि क्या वह जनतंत्र है कि जब कि जयपुर के पास कानोता के फोर्ट मे राजस्थान विधान सभा के चुने हुए सदस्यो को कैदी की तरह से बन्द रखा जाय ? ..... (व्यवधान) ... .जबकि कोई विधान सभा का चुना हुआ सदस्य अपने घर वालों से मिलने के लिए भी जाय या कोई अपने चुनाव का हिसाब किताब पेश करने भी जाय तो उस राजस्थान विधान सभा के चुने हुए सदस्य के साथ चार चार गोली वाले, बन्दूक वाले, आगे पीछे बैठे हैं ? उन को इस बात की धमकी दी गई कि अगर आपने कांग्रेस का साथ दिया तो हम न केवल आपकी जान ले लेंगे बल्कि आपके बच्चों को कत्ल कर देंगे, आपके रिश्तेदारों को कत्ल कर देंगे। अगर यह बात गलत है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कानोता के फोर्ट के अन्दर दो हफ्ते से भी अधिक राजस्थान विधान सभा के उन सदस्यो को क्यो बन्द रखा गया। अगर बन्द नही रखा गया था तो आप इस बात मे इनकार कर दीजिए। क्या यह बात गलत है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार, भाई या लडका या उन की औरत भी उनसे मिलना चाहती थी तो उनको भी आख पर पट्टी बाध कर जयपुर शहर से ले जाया जाता था। पट्टी जयपुर शहर मे बाधी जाती थी और पट्टी बाध कर के कार मे बिठाकर जयपुर से आठ दस मील की दूरी पर कानोता के फोर्ट मे ले जाया जाता था। और फिर मिलने के बाद वही पट्टी बाध दी जाती थी फिर कार मे बिठाकर जयपुर लाया जाता था। श्रीमन्, यह कौन सा प्रजातंत्र है? (व्यवधान) .. मेरे दो तीन नजदीकी रिश्तेदार राजस्थान विधान सभा के सदस्य चुने गये है। मै उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हू लेकिन आज तक उनसे मिलने नही दिया जा रहा है। (व्यवधान) . . अगर वह यह कहते है कि राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि कांग्रेस की सरकार नही बनाना चाहते, उनको पहले छोडो, जरा छुट्टी दे दो, उन को जरा घर जाने दो . (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : (दक्षिण बम्बई) : 93 मेम्बर राष्ट्रपति के यहा हाजिर थे.

श्री पहाड़िया : 93 मेम्बर राजस्थान विधान सभा के राष्ट्रपति के यहा जो हाजिर थे, उनके बारे मे गृह मत्री महोदय ने बहुत कुछ कह दिया कि उन्होंने कोई गिनती नही गिनी थी कि कितने लोग थे, उनसे पूछा भी नही गया था कि वह राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं या नही ? किसी भी व्यक्ति को इस तरह हाकर खड़ा कर दिया जाय,

उन से कुछ सवाल पूछ लिया जाय, उन की राष्ट्रपति के साथ फोटो खिचवा दी जाय, इस बात को हम कबूल नही कर सकते। इसका भी कोई वैधानिक तरीका है। राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति का शासन राजस्थान के अन्दर है। अगर इसको चुनौती देना चाहते थे तो हमने सरकार बनाना मजूर किया था। हमारे नेता ने कहा था कि हम सरकार बनायेंगे और उस को फेस करेंगे। उन को इसका मौका क्यो नही दिया ? क्योकि इस बात का खतरा था कि अगर हमने उन सदस्यों को छोड़ दिया तो निश्चित रूप से वह कांग्रेस के साथ जायेंगे और विरोधी दलो का वह सपना जिसको वह खून खराबी से पूरा करना चाहते है वह पूरा नही हो सकेगा। इसलिए उन्होंने उन को छूट नही दी। मै निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री कंवर लाल गुप्ता . मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि सदस्य महोदय को वाइल्ड एलीगेशन लगा रहे है, मै यह चाहता हू उन्होने होम मिनिस्टर को रेफर किया है, या तो होम मिनिस्टर साहब कहे कि उन्होंने आदमी नही गिने जैसा कि उन्होने कहा है और उन्होने यह भी कहा है कि उनको कत्ल करने की धमकी दी गई, अगर कत्ल करने की धमकी दी गई तो क्या यह उनसे कहलवाने को तैयार है ? अगर इसको साबित करने के लिए तैयार हैं तो होम मिनिस्टर साहब कहे।

16 hrs.

श्री पहाड़िया : मैं एक बात और निवेदन करना चाहूगा कि राजस्थान की जो स्थिति है उस से शायद इस सदन के सारे लोग परिचित नही है। आज विरोधी दलों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि राजस्थान की स्थिति सामान्य है, मैं भी कहता हूं कि आज के दिन राजस्थान की स्थिति सामान्य है, लेकिन क्या वह स्थिति सामान्य रहेगी ? जब कि हम इस बात की फिर कोशिश करेंगे कि किसी भी दल को चाहे वह कांग्रेस दल हो, चाहे संयुक्त विरोधी दल हो, उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाय, इस बात का सबूत उनकी इस भावना में ही लगता है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय 4 मार्च को जब कांग्रेस दल के नेता श्री सुखाडिया को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया तो उनकी भावना भड़क उठी, जनता नही भड़की थी, संयुक्त दल भड़का था, उन मे कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आपके साथ बैठी थी, जनसघ के साथ और दूसरी पार्टी जिसका नाम मैं लेना नही चाहता, वह कोई पार्टी नही है, अगर आपको कोई तसल्ली होती, अगर आप कुछ तसल्ली रख लेते, राजस्थान की विधान सभा चल जाती, अध्यक्ष का चुनाव वहा पर हो जाता तो उससे साफ हो जाता कि किसका वहा पर बहुमत है और किसका अल्पमत है. लेकिन आपने इन्तजार नही किया। इस बात का सबूत हम आपको देना चाहेगे और हम इस बात की मांग करते हैं कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये, चाहे हाई कोर्ट के जज द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा, कि क्या इस बात का खण्डन किया जा सकता है कि उनकी इस बात की योजना थी कि वहा की सत्ता को इस प्रकार से हथिया लिया जाय तथा वहा की जनता को भड़का दिया जाय, किस तरह से वहा पर गोली चली, किस तरह से वहा पर पुलिस वालो को तग किया गया। वहा पर धारा 144 क्यो हटाई गई, श्रीमन, धारा 144 वहा की विरोधी दल की नेत्री महारानी गायत्री देवी के आश्वासन पर हटाई गई, उन्होने यह आश्वासन दिया कि वह जयपुर जायेंगी, जयपुर की जनता से अपील करेगी कि शान्ति रखी जाये, लेकिन जैसे ही धारा 144 हटाई गई, नतीजा यह निकला कि पुलिसवालों पर पत्थर फेंके गये, पुलिस वालो पर गोलिया चलाई गई और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पुलिस ने गोली चलाई, जिनकी वे बात करते है, वह पुलिस राजस्थान की पुलिस नही थी, वह यू० पी० की पुलिस थी। यू० पी० की पुलिस के चारो तरफ घेरा डाल दिया गया, वे सिपाही जो

[श्री पहाड़िया]

जयपुर शहर से परिचित नहीं थे, उन के ऊपर किसी व्यक्ति ने, पुलिस के सिपाही पर किसी व्यक्ति ने, मुझे शक है कि राजनीतिक दल के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने, पुलिस के सिपाही पर गोली चलाई और तब उनको अपनी आत्मरक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी । ऐसी स्थिति में जब भीड़ की तरफ से पथराव हो रहा हो, जब भीड़ की तरफ से गोली चलाई जा रही हो, जब इस बात का पूरा खतरा हो कि किसी भी समय न केवल जयपुर शहर बल्कि राजस्थान की स्थिति बिगड़ सकती है, उस समय पुलिस के पास क्या चारा था कि गोली न चलाती, ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी किसी भी दल के नेता ने शान्ति की अपील नहीं की । सब दलों के नेता वहां पर मौजूद थे, सब ने इस बात की कोशिश की कि शान्ति भंग होनी चाहिये, बराबर खतरा बना रहना चाहिये, क्योंकि वे राजस्थान की जनता को इस बात के लिये उकसाना चाहते थे कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम दोबारा नहीं आ सकेंगे, 10 साल के लिये धुल जायेंगे । और प्रान्तों में जब गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं तो दीपक जलाये गये, लेकिन दीपक तो उसी समय बुझ गया जब आपकी कोशिशें नाकामयाब हो गईं । जब नाकामयाब हो गये, तब इस बात की कोशिश की कि प्रजातन्त्र का तरीका नहीं चलता तो हुममामे से सरकार बननी चाहिये, लेकिन इस तरह से सरकार नहीं बनेगी । हमने आपको कई प्रान्तों में मौका दिया है, अगर हमारी नीयत खराब होती तो बिहार में क्यों देते, बंगाल में मौका दिया, केरल और मद्रास में मौका दिया गया . . .

श्री रामसेवक यादव : नहीं दिया गया ।

श्री पहाड़िया : ऐसी स्थिति में इस खून-खराबी से डर कर, इस खतरे से डर कर कि अगर विरोधी पार्टियों को इस बात का मौका दिया गया कि वे सरकार को हथिया लें, तो हमारे लिये बड़ी मुश्किल हो जायेगी, हिन्दुस्तान की जनता बड़ी परेशानी में पड़ जायेगी, वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया ।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति सामान्य नहीं है, वहां पर राष्ट्रपति का जो शासन लागू किया गया है, वह कुछ समय तक जारी रहना चाहिये और उसे जारी रखना चाहिये जब तक वहां पर पूरी शान्ति न हो जाय ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) सभापति जी राजस्थान में जो राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है यह भारतीय जनतन्त्र के लिये बहुत घातक है । पहली बात तो यह है कि राजस्थान में जो फिजा पैदा हुई है हमें इस पर गौर करना है । वह फिजा कांग्रेस की जो हुकूमत सारे हिन्दुस्तान में अब तक रही है उसकी वजह से है । वह फिजा वहां पैदा हुई और वहां की जनता ने कांग्रेस को वहां से हटाया और उसमें उनकी उतनी ताकत न हो पाई कि वह बहुमत में आ सके । जब दूसरे लोग जीते और उनका बहुमत हुआ, न केवल राजस्थान में बल्कि मोटे तौर पर सारे हिन्दुस्तान में जब विरोधी दल मजबूत हो रहा था, तो राजस्थान के राज्यपाल का यह फर्ज था कि वे विरोधी दल को मौका देते और हुकूमत बनाने के लिये उनको आमन्त्रित करते । लेकिन ऐसा न करके उन्होंने कांग्रेस को बुलाया और फिर जब कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने में असमर्थ रही तो राष्ट्रपति का शासन वहां पर लागू कर दिया गया ।

यह राष्ट्रपति के शासन को लागू करने का जो यह लालच है यह एक खराब लालच है जिस जल्दबाजी में आप इसको लागू करते हैं, एक इलाके में, दूसरे इलाके में, तीसरे इलाके में, तो हो सकता है कि सारे हिन्दुस्तान में जनतन्त्र को खत्म करने के लिये भी एक दिन आप सख्त कदम उठा लेंगे ।

इसलिये, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो राष्ट्रपति का शासन लाग किया गया है यह भारत के विकास के खिलाफ है भारत के जनतन्त्र के खिलाफ है और अभी भी कोई देरी नही हुई है यदि इसको हटा दिया जाय और विरोधी दल को वहा पर हुकूमत बनाने के लिये मौका दिया जाय तो वह देश के हित मे होगा ।

इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू ।

श्री भोला नाथ मास्टर (अलवर) सभापति महोदय मैं राजस्थान से आया हू और कुछ समय के लिये अस्पताल मे भी था । मैंने देखा कि जो सख्या यहा पर बताई गई है जिसमे करीब 35 मृत सख्या का इन्होने जिक्र किया है यह बिल्कुल गलत बात है । इतनी मृत सख्या नही थी बल्कि जो सख्या पत्रो मे छपी है वह बिल्कुल सही सख्या है ।

अब हाउस के सामने जो मैं अर्ज करना चाहता हू—वह केवल यह विषय नही है कि यह जो कार्यवाही हुई या गोली चली वह सवैधानिक है या नही है, बल्कि सवाल यह है कि हिन्दुस्तान मे इस 1967 के चुनाव के बाद जो नया ट्रेन्ड शुरू हुआ है उस पर हमको विचार करना होगा । मैं प्रधान मत्री महोदया से, लीडर आफ दी हाउस से, भी यह निवेदन करना चाहता हू कि 1967 के चुनाव मामूली हालात मे नही हुए है । जो भी चुनाव कराये गये और चुनाव के सम्बन्ध मे जो भी सभायें की गई, उन मे पहले से ही हिसा शुरू हो गई थी । प्रधान मत्री पर पत्थर फेका गया, और लोगो पर भी पत्थर फेके गये, हमारे राजस्थान मे यह दृश्य सन् 1952 से देखने को मिला था । सन 1952 मे ज्योही हिन्दुस्तान मे हमारी सरकार बनी, आपको मालूम है कि राजस्थान एक विशेष प्रकार की रियासत (स्टेट) है वह पहले ही बी क्लास स्टेट थी, इसी तरह उडीसा भी बी क्लास स्टेट थी आप देख कि यह ट्रेन्ड उड़ीसा से चलना है पूरब से पश्चिम तक यह ट्रेन्ड चलता है कि किस प्रकार से हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाय और उस हिंसा को प्रोत्साहन देने की गर्ज से यह सब कार्यवाहिया हिन्दुस्तान मे हुई । उधर प्रधान मत्री पर पत्थर फेका जाता है इधर जोधपुर मे जो हमारे बार्डर पर है आप जानते है कि पाकिस्तान के बार्डर पर वह सब से बडा शहर है वहा पर हमारे गृह मत्री गये थ, उन पर भी वहा पत्थर फेके गये, जिसमे आठ आदमी घायल हुए । यह ट्रेन्ड हिन्दुस्तान मे जैनरल इलेक्शन के बाद चला, शुरू से चला और अब भी चलने की बात हो रही है । जहा-जहा सरकारे बनी है, वहा ये चाहते हैं कि हम दबा कर कोई पब्लिक मीटिग न होने दे, किसी को बोलने न दे, सभाये न चलन दे, बल्कि एसेम्बली तक न चलने दे ।

16.08 hrs

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

आज राजस्थान मे जो हो रहा है, उसको इसी मद्देनजर से देखना चाहिये, राजस्थान की बैकग्राऊड को इसी नजर से देखने की कोशिश करनी चाहिये । राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसको 22 रजवाडो को मिलाकर बनाया गया है, उन 22 रजवाडा मे तरह-तरह के सम्बन्ध है । एक बडा नेतृत्व पनपाने के लिये कितना परिश्रम काग्रेस ने किया है, काग्रेस के नेताओ ने किया है, वह काग्रेस के काम करने वाले जानते है । हम सन् 1947 से पहले इसी रियासत मे और एक दूसरी मे नही जा सकते थे । मेरा जैसा छोटा आदमी भी दो, चार रियासतो से निकाला गया था । मेरे दो नेता तो 5—5 और 7—7 रियासतों से निकाले हुए थे । अब उन रियासतो मे मत्रिमडल बने हैं । वहा पर काग्रेस चुन कर आती है । वह जयपुर शहर मे आना चाहती है । लेकिन जयपुर शहर के बारे मे मैं आप से निवेदन करता हू कि आप इस की बैकग्राउण्ड मे आज जयपुर के हालात को जयपुर शहर

[श्री भोला नाथ मास्टर]

की परम्परा को देखने की कोशिश करे। जयपुर शहर की असेम्बली कोई राजस्थान में जो गये होंगे वही जानते होंगे कि जिस तरीक़े में अपनी पार्लियामेंट है वह शहर से कोई दूर नहीं है। वह बिलकुल शहर में होकर उन को असेम्बली में होकर जाना पड़ता है। अभी खांडिलकर साहब ने कहा कि हमारे वाजपेयी साहब से जो जलूस निकालने के लिए आप ने कोई शर्तें रक्खी थी, आप ने कहा कि आप आरडरली जलूस निकालेंगे लेकिन आप को 4—6 मील आना पड़ता था। लेकिन राजस्थान असेम्बली मे कोई जलूस निकाला जाय तो वहां पर आइये तो सारा शहर पार करना पड़ता है। मिनिस्टर्स के जो बंगले है वे शहर से कही दूर हैं। इस के अलावा जो हमारे एम०एल०एज० के क्वार्टर्स है वह भी शहर मे दूर और एम० एल०एज० को पूरे शहर मे से होकर गुजरना पडता है और बसों पर और कारो पर पत्थर फेंक देना यह मामूली काम जयपुर का हो गया है। मैं वाजपेयी जी से पूछना चाहता हू कि क्या जब यह कर्फ्यू लगाया गया उस मे पहले जो ख़ास सैंटर है जगह है वहा पर क्या पत्थर नही फेंके गये थे? क्या वहां पर खादी भंडार नही जलाया गया था? यहां पाच बत्ती का रास्ता गवर्नमैंट होस्टल जहां से कि होकर मैम्बर्स पास होते है, मिनिस्टर्स और असेम्बली के मेम्बर्स पास होते हैं उस पांच बत्ती के सैंटर पर आग नही लगाई गई। वहां पर जयपुर शहर में एक मशहूर जगह है उस का एक बड़ा बाजार है। उस सारे बाजार में होकर एम०एल०एज० को जाना पड़ता है। उस मशहूर बाजार मे से होकर मिनिस्टर्स की कारें जाती हैं और चूंकि उन पर खाल पट्टी होती है जोकि आसानी से पहचानी जा सकती है। उन पर पत्थर फेंकने की कार्यवाहियां की जाती हैं और लाचार होकर यह कर्फ्यू लगाने की कार्यवाही करनी पड़ी। इस के लिए मैं राजस्थान के राज्यपाल महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी मजबूती के साथ स्थिति को सम्हाला और वहां की परिस्थिति के बारे में एक सही राय गृह मंत्री महोदय की सेवा में पेश की। राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने के बाद हमारी केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक और उपयुक्त क़दम उठाया। कदम यह उठाया कि राजस्थान के अन्दर आम दिनों जैसे हालात पैदा होने देने चाहिएं। क्या यह ग़लत बात है? वहां के जैसे हालात मे उस में यह वाजिब बात की गई।

अभी हमारे बीकानेर के महाराजा कर्णी सिंह जी बोल रहे थे और वह कह रहे थे कि वह पुराना फ्यूडैलिस्टिक कैरैक्टर नही रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि फ्यूडैलिस्टिक कैरैक्टर भले ही न रहा हो लेकिन फ्यूडैलिस्टक बिल्डिंग और फ्यूडैलिस्टिक किले मौजूद हैं। कानौता का वह किला अभी भी मौजूद है जिसकी कि बाबत हमारे भाई श्री पहाड़िया जिक्र कर रहे थे कि जहा हमारे एम०एल०एज० को बन्द किया गया। वह किला आज भी मौजूद है। राजस्थान की असेम्बली की बैठक जयपुर की महारानी गायत्री देवी के महल मे होती है यह आश्चर्यजनक बात मैं कहना चाहता हूं। आज वह असेम्बली कहा हो रही है? असेम्बली का कोई उनका स्वतन्त्र भवन राजस्थान के अन्दर नही है। वह महारानी गायत्री देवी के महल में है और महल के उस दरवाजे से से होकर हमको असेम्बली के लिए जाना पड़ता है। एक कमरा बना हुआ है। राजस्थान के फाइनैंसेज लिमिटेड है और उसी में हम अपना काम कर रहे हैं। वहा जनता के हित के काम करने में हमें बड़ी कठिनाई पेश आती है। हमने लैंड रिफार्म्स किये उस से आज राजे महाराजे हम से नाराज हैं, जमींदार हम से नाराज हैं। हम वहां पर बड़ी मजबूती से लड़े और 89 अपने सदस्य लाये और उन 89 सदस्यों की तरफ़ से 25 तारीख़ को हमारे सुखाड़िया जी लीडर

चुने गये। उसी रोज उस सभा मे चार निर्दलीय सदस्य भी मौजूद थे और उन्होने खडे होकर अपने नेता के सामने नही बल्कि सारे जो 89 मैम्बर्स थे उन के सामने कहा कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? इसके लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नही है। उनमे एक पहले के हमारे कांग्रेसी है श्री अब्दुल हाजी जो पाकिस्तान बौरडर के आदमी है वह हमारे कांग्रेसी आदमी सन् 52 मे भी एम०एल०ए० रहे हैं। दूसरे जो साथी और जो एक वकील थे वह भी कांग्रेस को मानने वाले थे, हमारे पुराने साथी थे और एक राजपूत भी थे, उन्होने भी बराबर कांग्रेस का कार्य किया था। यह सब पहले कांग्रेसमैन थे। इसलिए अगर उन चार लोगो ने हमारा समर्थन किया था तो कोई गैर आदमियो ने हमारा समर्थन नही किया बल्कि वह सब कांग्रेसमैन थे। ऐसी हालत मे राज्यपाल महोदय ने जो कांग्रेस दल के नेता को मन्त्रिमडल के निर्माण के लिए बुलावा भेजा वह एक उपयुक्त बात ही थी। ऐसा करके उन्होने कोई गैर वाजिब बात नही की। 93 मैम्बर्स हमारे साथ थे। लेकिन चूकि प्रैस मे इसको लकर काफी होहल्ला किया गया, अखबारो मे आपोजीशन वालो ने इसके खिलाफ पबलिसिटी की, प्रचार किया और इसके विरुद्ध उनके द्वारा मिल कर कोई एक स्टेटमेट देने की कोशिश होती है तो आखिरकार यह जो गवर्नमेट है यह भी आजकल प्रचार से प्रभावित होती ही है और उन्होने समझा कि शायद बहुमत सुखाडिया जी के पास नही है जोकि ठीक नही था।

एक मजेदार चीज मैं यह भी बतला दू कि महारानी गायत्री देवी के बारे मे जरा गलत इत्तिला दी गई है। तथ्य यह है कि महारानी गायत्री देवी अपनी रियासत मे हारी थीं। महारानी जी खुद अपनी रियासत मे हारी। इसलिए जो मौजूदा साइन्स है उनको पढ़ना चाहिए। जहा से महारानी के लडके श्री जयसिंह जी जीते थे वही से महारानी हारी हैं। इसलिए उन्हे आज के बदले हुए साइन्स को समझना चाहिए और उनको समझ कर उसके अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना चाहिए। मैं सारे सदन से और इस की मार्फत देश से अपील करूगा कि अगर सचमुच देश मे डेमोक्रेसी को चलाना है तो हमे बदले हुए हालात को दरगुजर नही करना है क्योंकि इन रियासतो का जो इटेग्रेशन हुआ है तो फिर से यह सोचने लगे हैं कि किस तरह वही पुराना शासन तन्त्र आ जाय, यह फ्यूडेलिस्टिक स्ट्रक्चर आ जाय। हमारे महाराज कर्णी सिह जी अभी बोल रहे थे। कहने को तो वह इडिपेंडेंट हैं लेकिन मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हू और यह फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हू कि महारावल लक्ष्मण सिह जो कि अपोजीशन के लीडर चुने गये हैं वह उनके फादर इन ला है, उनका उनसे खास रिश्ता है। उसी तरह उडीसा के देव साहब जो कि बोले उनका भी उसी तरह से रिलेशन है। उनके द्वारा इस तरह की बात हाउस के सामने कह कर देश मे एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि मानो हमारे द्वारा प्रजातन्त्र का खून हो रहा है जब कि हकीकत इसके बरअक्स है। उनकी तरफ से ऐसा प्रचार किया जाता है कि अपोजीशन को गवर्नमेट बनाने का मौका नही दिया जाता है जब कि फैक्ट अदरवाइज है। यह भी अजीब बात है कि हम लोगो ने जिस परिश्रम से इन 17 सालो के अन्दर देश मे और उसके अन्दर कायम देशी रियासतो मे से फ्यूडेलिस्टिक स्ट्रक्चर को खत्म करने का प्रयत्न किया और आन्दोलन किया, जहा पर असेम्बली नाम की कोई चीज नही थी उन जगहो पर असेम्बली लाये, प्रजातात्रिक ढाचा वहा पर कायम किया उनके ऊपर इस तरह का झूठा आरोप प्रजातन्त्र का गला घोटने का लगाया जाय। हमने उन जगहो पर असेम्बली बना कर दिखाई। उस को चला कर दिखाया। सन् 52 मे भी हमारे ऊपर पत्थर फैंके गये। उसके बाद गोलियां

[श्री भोला नाथ मास्टर]

चलीं लेकिन हम अपने सही रास्ते से डगमगाये नहीं। उस वक्त भी हम लोगो ने इन सामन्तवादी लोगो के मुकाबले मे चुनाव जीते थे और आज भी 89 की तादाद मे उनके विरुद्ध चुनाव जीत कर दिखाया है भले ही आज विरोधी दल वालो की तरफ से गोहत्या बन्दी को लेकर कैसा ही जहरीला प्रचार क्यो न किया गया और सब को मालूम है कि किस तरीक से जनता की भावनाओ को भडकाने की कोशिश राजनैतिक स्वार्थ की सिद्धी के लिए की गई। दरअसल तथ्य यह है कि जिन्होने गोहत्या बदी की आवाज उठाई वही जनसघ वाले कुल राजस्थान मे सबसे ज्यादा फियुडैलिस्टिक स्ट्रैक्चर का कायम करने की कोशिश मे लगे है। वह राजा, जागीरदारी आदि के पीछे चलना चाहते है। वह हिन्दू मस्कृति आदि की बाते करते है। वे लाग यहा पर केवल 22 आदमी लाये है और वह इम तरीके म यहा पर बताना चाहते है कि काग्रेम हुकूमत काम नही कर मकती है, काग्रेस कामकाज नही चला सकती है।

मैं आप मब लोगो मे यही निवेदन करना चाहता हू कि यह जो प्रस्ताव सामने आया है यह बिलकुल फेंकने के लायक है। यही नहीं बल्कि मैं समझता हू कि जब प्रेसीडेन्ट एड्रैस आयेगा और उम वक्त भी आप के सामने फैक्टम् रक्खे जायेगें तो उन पर आप को गम्भीरता मे विचार करना होगा कि जैसे बी क्लास स्टेटम उडीसा मे गडबड चली, जैमे राजस्थान मे गडबड चली, वहा पर ईंट, पत्थर आदि फेंकने की कार्यवाहिया होती हैं तो क्या वहा पर इस तरह के हिसात्मक प्रदर्शन होने चाहिए। इन सब बातो पर हाउस गम्भीरता से विचार करे यही मेरा निवेदन है। इम प्रस्ताव का श्री वाजपेयी ने रक्खा है मैं उसका जोरदार विरोध करता हूं।

Shri Deokinandan Patodia (Jalore). Mr Speaker, Sir, I am a new Member I had expected that the level and the standard of debate in this House would be of a much higher order But I find that the Members of the Congress Party are adopting some indecent manners and are not even good enough to reciprocate the manner in which the Members of the Opposition are dealing with the matter

13th March, 1967 will go down as a black day not only in the history of India but in the history of democracy in the world It was a shock On the 13th March, the manner in which President's rule was imposed in Rajasthan came to be known through the newspapers

One thing that has been missed is that after adopting all sorts of unconstitutional methods, the Governor had decided to invite Shri Sukhadia to form the Government although he did not have the majority First of all, the Assembly was expected to be convened round about 22 March But on persistent demand from the Opposition with great difficulty he agreed that the Assembly would be convened on 14 March Then all of a sudden after having had so much time at his disposal Shri Sukhadia came to know that he did not have the majority that he was not in a position to form the Government On 13 March he refused to form the Government The only other constitutional alternative the Governor had under those circumstances was to invite the Leader of the Opposition to constitute the Government, and then, had the Opposition failed to produce a majority, had they refused to form the Government, any other alternative step could have been contemplated and taken Instead of doing that, the Governor chose, possibly in consultation with the Chief Minister, to

take the advice of the Home Ministry only to find out by what method and in what manner, somehow or other, an Opposition Government may be avoided and may not be formed and some more time might be given to Shri Sukhadia to manoeuvre and try to bring some members into his camp. In these circumstances, President's rule was imposed in Rajasthan. This is an important point which all of you will take into account.

Look at the background of the elections in Rajasthan. First of all, before the elections, all types of pressures, administrative pressures and misuse of authority, were brought to bear to obtain a majority for the Congress. When even after that, the Congress did not get a majority, efforts were made to purchase members. All sorts of pressures were used for the purpose. There also they were not successful. Then at one stage the Governor said that the Independents would not be recognised, a most unconstitutional thing ever heard of. In spite of that, Shri Sukhadia failed to form the Government. But somehow or other, he must stick to his power; somehow or the other, the Congress must form the Ministry; somehow or the other, the Opposition must not be given a chance even when the people's verdict is in their favour. So President's rule was imposed.

On the other hand, can anybody deny that out of 184 Assembly seats, the Congress got only 89 and it was definitely in a minority? Can anyone dispute the fact that 93 members of the Opposition were presented to the President, brought on the platform? Can anybody deny that signatures were given? The President in my presence asked all of them who were present, 'Are they all with the Opposition? Are they wholeheartedly, honestly with the Opposition?' The reply was a unanimous 'Yes'. This was in the presence of Shri Chavan, our Home Minister. Can anybody challenge these facts?

In these circumstances, why then resort to these undemocratic methods? What is the meaning of democracy? What do we stand for here? We declare in loud terms that we in India live for democracy? After all, in a democracy, power is nobody's perpetual preserve. Nobody can say that because his father enjoyed power, he should also be in power. Times have changed. If the Congress party is under the impression that they will hold power because they have been holding it in the past it is high time they disabused themselves of it.

The people's verdict is written on the wall. This verdict must be understood and accepted. It was only proper for them when they knew that they are not holding the majority, to say 'Since we are not in a clear majority, let the Opposition form the Government'. But no, that was never done. They want to stick on to power, adopting all unfair means in the process. The Governor in collusion with the Home Ministry created all sorts of pretexts and manoeuvred all sorts of circumstances only to show that there was a break down of law and order. I want to ask: in the course of twenty years of independence, how many times has President's rule been imposed in the country? How many times has law and order broken down in the country? How many times has firing been resorted to? What reply have they to all these questions?

After the 7th March, what was the situation, what were the incidents which go to show that there was breakdown of law and order? President's rule was imposed on 13th March. Between the 7th and 13th March, what happened in that State which prompted the Governor to declare that law and order had broken down? Let anyone reply to this question.

[Shri Deokinandan Patodia]

Apart from that, the whole State of Rajasthan is not one city. One particular mohalla of one or two square miles is not one town. If some disturbances had occurred in a particular locality in the city of Jaipur, is that enough ground to say that the situation had gone out of control, law and order had broken down in the State and imposition of President's rule is necessary and the Opposition should not be given a fair chance to form the Government?

Shri Pahadia: On point of clarification. I said that it was only in Jaipur that law and order had broken down.

Some hon. Members: Sit down. (*Interruptions*).

Shri Deokinandan Patodia: If this state of affairs is to continue, I want to ask: what difference is there between Congress rule and British rule? If they stick to power in the same manner as the British were sticking to power in this country, what is the difference between the two? If they are not good enough to accept the verdict of the people and stick to democratic practices, but refuses to vacate the chair, what is to become of our democracy?

I therefore feel that the Governor has violated all cannons of Constitution and fairplay and he should be dismissed and the Opposition given a chance to form the Ministry of Rajasthan .....

An hon. Member: By 5 O'clock today.

Shri Deokinandan Patodia. My friend interjects, 'By 5 O'clock today'. It will be good if that happens.

The other point I want to make is this. If Governors, Speakers and the President who hold such high offices of State also behave in a partisan manner, if they do not uphold the democratic right of every citizen, there is no future for this democracy. Looking at the things that have happened in Rajasthan, I feel that there should be some change, there should be an overhaul of the rules and the Constitution so that party men are not permitted to be chosen as Governor or elected as Speaker or President. With these few words, I support the Motion and hope that it will be carried.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने यह तो सुना है कि वोट देने के लिए बीमार आदमियों को, थके आदमियों को किसी तरह से उठाकर सदन में लाया जाता है । लेकिन आज कुछ ऐसा मौका आया कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए एक मेरे जैसे कुछ बीमार और काफी थके हुए आदमी को बुलाया गया और मैं आया भी । थका हुआ हू । बहुत थका हुआ हूं । इसलिए कि कांग्रेस तो खत्म हो रही ह और सिर्फ दो वर्ष रह गए हैं इस को सारे हिन्दुस्तान से साफ होने मे । लेकिन थकावट इस बात की है कि एक गढ़ ढह रहा है, इसकी जगह पर एक बढ़िया मकान बन नही पा रहा है ।

इन 20 वर्षों में लगातार जनता को कांग्रेस और सरकार पर्यायवाची शब्द के रूप में मिले थे । "कांग्रेस" माने जनता समझती थी "सरकार" और "सरकार" को "कांग्रेस" । लेकिन अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि हिन्दुस्तान की जनता के सामने अब कांग्रेस सरकार नही रही है और सरकार का अर्थ कांग्रेस नही रहा है । यह एक बहुत बड़ी बात हुई है और जो प्रस्ताव आपके सामने है वह विशेष तौर पर इसी बड़ी बात को खत्म करने की निन्दा में रखा गया है, क्योंकि जहां जनता ने कांग्रेस और सरकार के समान अर्थ को खत्म किया है वहां यह सरकार जिस किसी भी हथकण्डे से, प्रलोभन से, लालच से, जोर-जुल्म से, अत्याचार से कोशिश करना चाहती है कि फिर से जनता के मन में कांग्रेस

का अर्थ सरकार बन जाय, इस लिये यह यह प्रस्ताव आया है।

आखिर राजस्थान में हुआ क्या ? मैं घटनाओं की तफसील मे नही बतलाऊंगा 93 आदमी आये, सशरीर आये, आत्मा से आये, कैसे आये, लेकिन बात बिलकुल साफ थी, लेकिन यह काग्रेस हथकण्डे इस्तेमाल कर के, जोर जुल्म, जबरदस्ती इस्तेमाल कर के फिर मे राजस्थान मे सरकार बनाने चली, क्योंकि केवल अपने देश में ही नही, सारी दुनिया मे कही किसी चीज को करना होता है तो किसी एक छोटी जगह मे आरम्भ करते हैं। यूरोप वाले, मैंने सुना है, जब कोई छुटपुटी, बेडगी, अनोखी, बदमाश चीज किया करते हैं, तो उसको लक्जमबर्ग मे शुरू करते हैं, जब प्रयोग कर लेते हैं, नतीजा निकल आता है, तब उस को सारे यूरोप मे लाने की कोशिश करते है। उसी तरह मे ऐसा लगता है कि राजस्थान से इन लोगो ने, इन हजरतो ने, इस को शरू किया है और शरू कर के फिर बहाव उत्तर प्रदेश और इनका बस चला तो न जाने कहा कहा इस को इस्तेमाल करेगे।

उत्तर प्रदेश मे देखिये, क्या हुआ, जितने वोट देनेवाले हैं, जिनको वोट देने का हक है, उन सात मे से केवल एक ने इस सरकार को सरकारी पार्टी को अपना वोट दिया है सात मे से एक ने। अब चाहे हजार सविधान मुझको पढ़ कर सुनाइये, नियमावली, प्रतिनिधित्व के कानून, अगर कोई मुझ से कहे कि 117 किसी पार्टी को वोट दिया गया है और उस पार्टी की सरकार बनजाय, तो मैं खाली यह कहूंगा कि यह उल्टी खोपड़ी की दुनिया है और भारत मे कहीं कोई किसी तरह का नियम चल नही पा रहा है। सात में से साढ़े तीन घर बैठे रह गये, वोट देने नहीं आये, साढ़े तीन जो वोट देने गये, उन में से ढाई ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट डाला, एक ने केवल पक्ष में वोट डाला और उस एक की सरकार बन रही है—अजीब दुनिया है, इसको जनतन्त्र कहते हैं, इस के ऊपर बडा भारी घमण्ड करते हैं कि हम ने देश मे जनतन्त्र कायम कर रखा है और जब यह तर्क इस्तेमाल करते हैं कि उन में से बहुत से स्वतन्त्र थे, जो किसी पार्टी मे नही थे, तो मैं एक तर्क देना चाहता हू कि जो भी कोई स्वतन्त्र, जहा कही भी जीता है, स्वतन्त्र से मेरा मतलब ममानी साहब की पार्टी मे नही है, वे स्वतन्त्र जो किसी पार्टी मे नही है, उन हर एक स्वतन्त्र के खिलाफ इस काग्रेस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुआ था और वह हारा था, काग्रेस की शक्ति वहा हारी थी, तो किसी भी तर्क के अनुसार स्वतन्त्र उम्मीदवारो को और स्वतत्र वोटो को काग्रेस के खिलाफ ही गिनना चाहिये, वैसे इन को सात मे से केवल एक ही वोट मिला और इनकी सरकार कायम है—वाह, क्या गजब की यह सरकार है।

फिर वहा के लोग कहते है कि हम मतैक्य है, एक मत के हैं, हम लोग तो अनेक मतवाले है, मुझे इस मे रत्ती भर भी उज्र नही होना है— यह मानते हुए कि जितने लोग यहा बैठे हुए है, वे अनेक मतवाले है। यही तो मुझे एक अफसोस है कि हम अनेक मतवाले है, एक मतवाले हो जाते तो मजा ही आ जाता। लेकिन कैसा एक मत है, इसी राजस्थान के मामले को ले लीजिए। पुराने राजाओं और रानियों के खान-पान पर लाखो, करोडो रुपया दिया जाता है, जिसको ये लोग प्रीवीपर्स कहते है, इनकी भाषा आप जानते हैं जो है। जब चुनाव आता है तो यदि कही कोई छुटभैया राजा या छुटभैया रानी विरोध पक्ष मे पहुंच जाता है तो बहुत ज्यादा राजा-रानियो के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, उसी राजस्थान में खिचवाभर राजा-रानी इनके यहा बैठे हुए हैं—नये राजा, पुराने राजा, पुरानी रानी, नई रानी, अगर जयपुर की रानी इस तरफ है तो इलाहाबाद की रानी उस तरफ है, इस बात को क्यों भूल जाया करते हैं। यह सब क्या हो रहा है, मैं इतना ज्यादा दुखी हूं

[डा० राम मनोहर लोहिया]

कि जिस अपराध के लिये एक साधारण नागरिक राजस्थान की जेल मे बन्द रहा और तरह तरह की यातनायें सही, उसी अपराध के लिये वहा का एक स्वतन्त्र पार्टी का नेता, कोई राजा है, रावल है, पकडा गया और छोड दिया गया, यह है इन लोगो का मतैक्य, यह है गृह मंत्री और यही है प्रधान मंत्री। एक ही तरह का अपराध करने वाले एक नागरिक को जेल मे रखते है और दूसरे नागरिक को, क्योंकि वह राजा-रानी है, उसको पकडते भी नही, यदि पकडते है तो पकड कर छोड देते है। जाइये, भाई, जाइये—यह मतैक्य हम को बताते हैं। अगर मतैक्य करना है तो अपने अन्दर मे वे सारे के सारे लोग जो वंश, कुल, परम्परा को संविधान से ऊंची जगह देते है, संविधान मे लिखा हुआ है कि हर नागरिक के समान अधिकार है, कानून के सामने हर नागरिक बराबर है, संविधान के इस कलक के होते हुए जो राजाओ और रानियों को कानून, प्रीवीपर्स—खान-पान के खर्चे के मामले मे विशेषाधिकार देना चाहते हैं, ऐसे कांग्रेसी और स्वतन्त्र पार्टी वाले है, इन को मतैक्य कर के अपनी सरकार बना लेनी चाहिये। अगर कांग्रेस मे कोई रह गया है— मैं समझता हूं कि कोई नही है, खाली चिल्लाने भर के लिये है कि हम राजा-रानियो को खत्म करना चाहते है, वे तो उन से बड़ा फायदा उठाते हैं, जगह जगह उनके सहारे जीते हैं, उनको क्या खत्म करेंगे। फिर भी यदि ऐसे लोग अगर रह गये हो जो विशेषाधिकारों को, ऐसे समाज को जिसमें ऊंच-नीच का आधिक्य हो चुका है, उस को खत्म करने वाले लोग एक तरफ हो जाय, क्यों नही ऐसा काम होने देते हैं, क्यों अपने अन्दर ईमान की कमी के बीज को वृक्ष रूप मे उगने देते हो, फिर कहते हो मतैक्य नही है, कहते हैं अनेक मत हैं। इस लिये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं अपनी तरफ से और मेरे जैसे अनेक लोग यहां पर हैं, मैं समझता हूं कि देश के अन्दर भी बहुसंख्या हमारी ही है कि अब इस देश मे आज, कल, परसों, दो-चार साल, पांच साल मे ये जितने भी विशेषाधिकार के व्यक्ति है, इन के विशेषाधिकार को भारत का जनतन्त्र खत्म कर के छोड़ेगा। भारत का जनतन्त्र इन राजाओ और रानियो को पचायेगा, नाकि ये राजा-रानिया भारत के जनतन्त्र को पचा सकेंगे। लेकिन यह कैसे हो पायेगा। ये जो नये-नये राजा रानिया निकलते है। जो कोई बडा आदमी पैदा हुआ वास्तव मे बडा था—नही था, यह बात छोड दीजिये, क्योंकि इतिहास पूरा बन रहा है कि इन मे से कौन कौन बडे थे, मै समझता हू कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद मे बड़प्पन तो भारत मे खत्म हो चुकी है, फिर कही उग रही हो, कही निकले तो बात दूसरी है, लेकिन उनके कितने लड़के, लड़किया... ..... .

(व्यवधान)

प्रो० समर गुह : आपको महात्मा गांधी का नाम नही लेना चाहिये था, अगर उनका नाम लिया तो नेताजी का नाम भी लेना चाहिये था।

डा० राम मनोहर लोहिया : यहा पर प्रो० समर गुह ने नेता जी का नाम लिया, नेताजी की बात छोड़ दो, नेताजी को तो मैं महात्मा गांधी की बगल में रखता हू। उनको ऐसे समूह में मत लाया करो, इनकी टोका-टाकी हो जाने दिया करों। टोका-टाकी से मैं मोम जैसा मुलायम नही हू जो पिघल जाऊंगा या गड़बडा जाऊंगा, मुझे यह कहना है कि चार हजार आदमी जो इस बार विभिन्न विधान सभाओं और विधायकों के लिये खड़े हुये, जो चुनाव जीते उन में से 100 के करीब पुराने कुल और वंशवाले और 100 के करीब नये कुल और वंशवाल हैं। किसी का लड़का, किसी की लड़की, चाहे जैसा अयोग्य हो, राज्य से कोई मतलब नहीं, थोड़ी बहुत चालाकी हो, गद्दी पर बैठने की क्षमता हो, कूटनीति कूट—कूट कर भरी हुई हो, देश की भलाई से कोई मतलब नहीं।

किसी तरीके से अकल लगा करके, छलांग मार करके गद्दी पर बैठ जायें बस इतनी ही चिन्ता है इस से ज्यादा कोई फिकरत नहीं है। न जाने कितने लोग खाली इसलिये कि उनके के बाप या उन के ससुर वगैरह थे वह मर गये उन की जगह पर आ गये। मैं नाम किस का इस वक्त लूं? 100,100 आदमियों का 100,100 औरतों का कहां तक नाम लूं? यह जितने लोग हैं यह भारत में जनतंत्र के सिद्धान्त और प्रणाली को कुल्हाड़ी से मार रहे हैं और जल्दी ही आप को ऐसा वक्त लाना पड़ेगा जब इस वंश और कुल के आधार को अपने जीवन में बिलकुल खत्म कर देना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि भारत में अगर जनतंत्र का उदय होगा तो वह साधारण गाड़िया लुहार राजस्थान वाला जो दर दर घूमता है, फटे मैले कपड़ वाला जिसको कि अपना सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है शायद राणा प्रताप की पलटन में था शायद उस ने प्रतिज्ञा की थी कि देश के ऊपर विजय पाने वालों के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा लेकिन यह वंश, कुल परम्परा वाले जितने कमबख्त है उन्होंने हर विजेता के सामने अपना सिर झुकाया है और उस के जरिए वह अपनी नये और पुराने गद्दी को कायम किये हुए हैं। जनतंत्र दुश्मन है वंश और कुल परम्परा का और वह बात भी राजस्थान से बिलकुल साफ साबित होती है। मतैक्य है और बहुत तरह का है यहां मालूम होता है कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। एक नया आदमी आया है, एक उपप्रधान मंत्री, और उस उपप्रधान मंत्री ने भी जबरदस्त गजब की चीज की हैं। एक वंश और कुल परम्परा जब वह पहले वित्त मंत्री थे तब वह गये थे इंगलिस्तान में और इंगलिस्तान में उन्होंने एक अंग्रेजी बैंक के एक खाते का निरीक्षण किया। वह विदेशी मुद्रा का खाता था। और कानूनी था अपने देश के कानून के हिसाब से। उस विदेशी मुद्रा के खाते के आदमी के ऊपर मुकद्दमा चला कर उस को सजा मिलनी चाहिए थी। इन्ही वित्त मंत्री महोदय ने जो अब उपप्रधान मंत्री हैं, अंग्रेजी बैंक के साथ और अंग्रेज भी बड़े पहुंचे हुए लोग, जब कभी वह शक्तिशाली आदमी के साथ आ जाते हैं तो सब तरह का न्याय, अन्याय करने के लिए राजी हो जाते हैं, उस खाते को बिलकुल साफ कर दिया। आज उस का अवशेष भी नहीं रह गया है उस अंग्रेजी बैंक में। विदेशी मुद्रा का खाता जानते हो किस का खाता था? वह था भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री का खाता.....

(व्यवधान) यह मतैक्य है इन लोगों में। इस मतैक्य को लेकर आज चल रहे हैं..

एक माननीय सदस्य : यह गलत व झूठ है।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): Sir, I rise on a point of order. According to our rules, no such allegations can be made without giving advance notice in writing; it is absolutely irregular and no such allegations can be made. I would request you to either expunge it from the proceedings or stop the hon. Member from making such wild and untrue allegations .. (*Interruptions*)

An hon. Member: The Member should be relevant

Mr. Speaker: The hon. Member should avoid such allegations.

Shri Vidya Charan Shukla: This allegation should not be allowed to stay in the proceedings.

श्री राम सेवक यादव : स्पीकर ने रूलिंग दे दी।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब वह मतैक्य हैं इन लोगों में। यह सरकार कैसी है। सुबेतलाना जैसे कोमल फूल को इस देश के अन्दर रखने की हिम्मत इन लोगों की नहीं हुई। उस को देश से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। अब वह अधर्म तेजा, घोषित अपराधी जिसको कि न जाने कितने

[डा० राम मनोहर लोहिया]

दिनों पहले यहां आ जाना चाहिए था, ले आकर जिस पर मुकद्दमा चलाना चाहिए था वह अभी भी घूम रहा है, परिव्राजक है, अमरीका में है, इंगलिस्तान में है । कहा सुबेतलाना जैसे एक निरीह व्यक्ति जिसके ऊपर स रे देश और सारे संसार या ससार के अधिकाश हिस्से की कठोरता आज छाई हुई है उस को रख नही सकते उसको निकालना पड़ता है । यह है सरकार और ऊपर से हमारे ऊपर यह रोब जमाना चाहती हैं और तेजा साहब को नही ला पाती । कैस कैसे मत्री हैं ? बाते बिल्कुल साफ हो चुकी हैं । यह कोई ऐलिगेशन, ऐलिगेशन, के मतलब क्या होते हैं, आरोप, यह आरोप नही है । यह सब साबित की हुई चीजे है । यह हजरत कौन आये कहने वाले । जरा उपप्रधान मंत्री को आकर कहने दीजिये कि यह बात गलत है । आखिर को मुझे मालूम हुआ तो उन से या उन के किसी चर से ही मालूम हुआ होगा और मुझे यह कैसे मालूम हो सकता है ? (व्यवधान)

मैं आप से यह अर्ज करूगा कि इस लोक सभा में इस तरीके की हरकतो से कभी कोई जनतत्रीय बहस हो नही पायेगी । आखिर बहस का क्या मतलब होता है ? जब कोई बात कही जाय उस को प्रतिपक्ष अच्छे तरीके से सुने और उस का ईमानदारी से जवाब दे और सच बोले । सब से बड़ी बात यह है कि आज अपने देश में और खासतौर से विधायिकाओं में सच बोलने की परम्परा रह नही गयी । यहां जनता के भीतर भी यहा भी कुछ ऐसा माना जाता है कि जो झूठ बोल कर बच जाय वह बड़ा कुशल आदमी है बड़े कुशल मंत्री हैं । झूठ क्यों बोला जाता है ? क्योंकि कोई चीज छिपानी होती है और कोई चीज गड़बड़ क्यों की जाती है क्योंकि आज अपने देश में खर्चे वगैरह को लेकर .....

Shri S. M. Banerjee: It is not proper for Mr. Shukla to come to you now. You should not allow any Member to come to you.

Shri Vidya Charan Shukla: We will see when you come there.

Mr. Speaker: Dr. Lohia should try to conclude; he has taken twenty minutes already.

डा० राम मनोहर लोहिया : अभी मेरा आखिर को ऐसा नही है कि बिलकुल वक्त खत्म हो गया । अभी मेरा अपना वक्त है । मै समझता हू कि आप आये हैं तो आपसे थोडा सा वक्त और भी मिल जायेगा लेकिन अभी तो मेरा वक्त बाकी रहता है ।

अभी आरोपो की बात करके मै नही चाहता कि वर्तमान प्रधान मत्री के बारे में मैं कुछ कहू । वह आरोप नही है बल्कि वह चीजे अध्यक्ष महोदय साबित हो चुकी है । अब प्रधान मत्री ने स्वय दूसरे सदन मे स्वीकार किया है कि इनको परदेशी बादशाह लोग हीरे दिया करते है । यह उन्होने स्वीकार किया है । इन्होने और इनके दूसरे सदस्यो ने भी यह स्वीकार किया है कि यह हीरे सात दिन तक प्रदर्शनी के लिए इनके घर मे रखे जाते है। अगर हमको पहले से पता होता कि ऐसी प्रदर्शनी भी लगा करती है तो शायद हम भी पहुच पाते यह देखने के लिए कि कैसे कैसे हीरे मिला करते है ? सात दिन के बाद वह हीरे बैंक वगैरह मे पहुचा दिये जाते हैं । यह आरोप नही है । यह प्रमाणित बात है । इनकी तरफ से कही हुई है । अब इसके ऊपर बिल्कुल साफ़ सवाल उठता है कि जो कुछ राजस्थान में हुआ, जो कुछ उत्तर प्रदेश मे हुआ उसके बाद अपनी मन की ताकत से मेरा यह सवाल उठता है 7 दिन ? 7 दिन तो बड़ा भारी समय होता है हीरों वगैरह के मामले में । हीरों का मामला तो मिनटों में इधर उधर किया जा सकता है । क्या जानें करोड़ों के हीरे हो जो सऊदी अरब और दूसरे राजाओं की तरफ से मिले हों और खाली हजारों ही देश के बैंक में पहुंच जाया करें ।

अब यह मामूली चीजें नहीं रह गई हैं.... (व्यवधान)

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): I strongly protest against these wild allegations.

Shri Khadilkar: On a point of order (*Interruptions.*)

एक माननीय सदस्य : सूदखोर का लड़का समाजवादी ढांचे में उबलता है और झूठ बोलता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रधान मंत्री जी क्या बोली है अभी वह तो सुनवा दिया जाय ?

Mr. Speaker: She is protesting against the allegations.

Shri Khadilkar: I want a ruling. (*Interruptions.*)

Mr. Speaker: She is protesting against the wild and baseless allegations.

डा० राम मनोहर लोहिया : ऐलिगेशन कहां हैं ?

Shri Khadilkar: *rose*—

Some hon. Members *rose*—

श्री राम सेवक यादव : तथ्य की बात है जिसे प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है ।

Mr. Speaker: Let him raise the point of order. There is a point of order.

Shri Khadilkar: I would like to point out to you that in the past such allegations of this nature were made; there are rulings on record and there is a certain procedure to be followed. If an hon. Member with a view to assassinating the character of another hon. Member, were to make certain vague allegations, so as to generate an atmosphere of corruption all round, unless he has substantial proof and gives in writing a sort of notice that he is going to raise the issue, he cannot make those allegations Only on giving notice that he is permitted; otherwise, all those things should be expunged, because otherwise it appears in the press; it must be expunged.

An hon. Member: What is the rule?

Shri Khadilkar: It is a tradition here.

An hon. Member: The decision will be changed.

Shri Khadilkar: He is a new man; ask the old Members.

They must be expunged.

Mr. Speaker: He has been saying that this has been accepted. I do not know where it has been accepted and by whom. He has been saying that all these things have been accepted.

श्री मधु लिमये . वह गलत बोल रहे हैं । श्री खाडिलकर की पुरानी आदत है । (व्यवधान)

Shri Khadilkar: I will give you the rule.

Some Members *rose*—

Mr. Speaker: One at a time.

श्री मधु लिमये : जब कभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, किसी नियम के अन्दर ही उठाया जाता है । किसी परम्परा पर व्यवस्था का प्रश्न आधारित नहीं किया जाता । इसलिये पहले श्री खाडिलकर को चाहिये कि वह नियम बतलाये ।

श्री खाडिलकर : मैं अभी रूल कोट करता हूं ।

श्री मधु लिमये : अभी मैं बोल रहा हूं । आप बाद में नियम बतला दीजिएगा । मैं आपका ध्यान .....

Shri Vidya Charan Shukla: His point of order has not been disposed of. (*Interruption*).

Several hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: I have not given any ruling; Shri Madhu Limaye is on his legs I would not allow others to speak now

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, श्री खाडिलकर ने परम्पराओं की बात कही, जब कि करनी चाहिये नियमों की ।

श्री खाडिलकर रूल और परम्परा दोनों ।

श्री मधु लिमये आपने केवल परम्परा कहा है, रेकार्ड देखा जाये ।

श्री खाडिलकर मैं अभी रूल देता हूं ।

श्री मधु लिमये अब देने से क्या होता है । वह बाद में बतलायेंगे । शायद उनको नियम मालूम नहीं है । उनकी जानकारी के लिये बतला देता हूं । शायद उनका ध्यान 353 की ओर है । लेकिन यदि वह इस नियम को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि वह जो सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सदन में जवाब नहीं दे सकता, उसके बारे में है । मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned, so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply"

इस नियम का मतलब साफ है । मान लीजिये कि मैं किसी अफसर के बारे में कुछ कह रहा हूं और अगर प्रधान मंत्री को उसकी कोई सूचना नहीं है या गृह मंत्री को सूचना नहीं है तो गृह मंत्री जांच करके कैसे जवाब दे सकेगा । लेकिन अभी डा० राम मनोहर लोहिया जो कह रहे थे वह किसी गैर सदस्य के बारे में नहीं, वह प्रधान मंत्री के बारे में है, और वह भी आरोप नहीं है । वह कह रहे थे कि प्रधान मंत्री ने ही इस किस्म की बातों को स्वयं कहा है । जब वह इन बातों को काटती है तो यह कहने से ही काम नहीं चलेगा, यह हम बहुत सुन चुके है, कि हम आरोपों का खंडन करते हैं । एक एक बात को लेकर कहना चाहिये कि कौन सी बात उन्होंने नहीं कही है, और कौन सी असत्य है । इस तरह से साधारण बातें कह कर अब मामला टाला नहीं जा सकता । पिछली लोक सभा में हमारे एस० के० पाटिल ने भी इसी तरह कहा था, और मैंने मांग की थी कि एस० के० पाटिल, मनुभाई शाह, शचीन्द्र चौधरी, इनके बारे में संसदीय समिति की स्थापना कर के आरोपों की जांच की जाय, लेकिन आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई । इसका क्या नतीजा हुआ ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ियों के दलाल यहां पर आकर इस तरह से बातें करते है . . (व्यवधान)

श्री मधु लिमये मैं ने उनके खिलाफ आरोप लगाये थे (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य यहां जो बैठे हुए है यह उनके दलाल है

श्री मधु लिमये अगर इसी तरह से यह लोग करेंगे तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा । यह प्रधान मंत्री अगले चुनाव के बाद इस सदन में नहीं रहेंगी . . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य यह अमरीका के रुपये पर चलते रहे और लाखों रुपये खा गये, यह बात नोट की जाये । मधु लिमये . (व्यवधान)

Several hon. Members *rose*—

Mr Speaker: One at a time. I will myself read the rule. It is very clear

(Interruption) Let all others sit down. Shri Khadilkar.

Shri Khadilkar: Now, a point has been reached where I want to show the rule. Therefore, I am quoting the rule. I only made a reference to the precedents Now, I shall quote the rule; it is rule 352 (i) which reads thus:

> "A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending."

Then, (ii)—

> "make a personal charge against a member."

That is more important Later on, in rule 353, it is said.

> "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker..." etc.

I have quoted it. (*Interruption*). Just a minute; let me finish my argument. You had your say. Mr. Speaker, Sir, my request is this. This is being indulged in, in this House quite often. In the last session, we have heard many allegations made, and they were rebutted, and still, with all the rebuttal, they find place in the press. I want a clear-cut ruling based on this procedure from you: unless the Member follows the procedure, gives notice, if vague innuendoes or allegations of this nature are made, they must stand immediately expunged

Shri Umanath: Because he is demanding a ruling, and you are also going to give it, I wish to bring to your notice that this very question on the basis of this rule was discussed in the pevious Lok Sabha in 1965 and already a ruling has been given. I wish to bring it to your notice that when the White Paper was being discussed and when Shri A. K Gopalan was not present in the House—he was in detention—Shri Vidya Charan Shukla made a wild personal allegation against Shri A. K. Gopalan, of having made earnings by unfair means, and no notice was given to Shri A. K. Gopalan. On the other hand, the hon. Member made these remarks behind his back, when Shri A. K Gopalan was in detention. He also made mention of his wife, Shrimati Suseela Gopalan, who was also in detention and who was not than a Member of this House. Strong objections were taken against Shri Shukla by other Members on the Opposition side Shri Hukam Singh was then in the Chair, and when this rule was quoted on the basis of the discussion here, he gave the ruling saying that if Shri Vidya Charan Shukla is very strong and is satisfied as far as the allegations are concerned, and if he is satisfied that they are true, then he could make it on the floor of the House On that basis, nothing was expunged, and he was allowed. Subsequently, when Shri A. K. Gopalan wrote to the Speaker that these were wrong, malicious things, and when he requested the Speaker to make a mention of it on the floor of the House, the Speaker turned it down on the basis of his ruling. Therefore, there is no question of claiming such a privilege now.

Shri Vidya Charan Shukla: Because my name has been mentioned, I may just say a few words in order to put the record straight When certain charges were levelled against Shri A K Gopalan, there was no point of order raised on this procedural matter It was only said that those charges were false Then the Speaker said that if the charges were falsified to his satisfaction he will have them expunged and he sent a letter to me and asked me to give the documents in proof of what I had said I sent the documents as proof and all those things in support of what I had said The Speaker was satisfied that there were full facts and that is why they were not expunged There is no question, therefore, of any point of order

Shri Umanath: You did not give notice to Shri A. K. Gopalan before you made the charge. And therefore you cannot claim the same privilege for you.

Shri Vidya Charan Shukla: There was no such point that notice should be given. The only thing is, the Speaker was satisfied that there was full proof for my allegation and that is why no action was taken on that.

17 hrs.

Mr. Speaker: I have heard enough. The rules are very clear. One member shall not make allegations against another member. Whatever might have happened, we should not dig out the old records. We should follow the healthy conventions. Whether it is a question of members on this side making allegations against members on that side or *vice versa*, it should not be made without complete proof or earlier notice. The rules are very clear. It is good that we follow these healthy rules, which are very good for everybody, for all the members. I would request all the members to follow the rules.

Shrimati Indira Gandhi: Sir, since my name has been taken here, I want to clarify what exactly was said in the Rajya Sabha. This allegation was made there during the last session that I had been presented with a diamond necklace and perhaps I had done something with it. Therefore, I clarified the situation that when high dignitaries visit our country, it is the custom that they give presents. Some of these presents are expensive ones. It is true that the King of Saudi Arabia did present a diamond necklace to me. But there are very strict and clear Government rules about all such presents which are given. We are not allowed to keep these presents. They are immediately handed over to the *toshakhana*. As this was such an expensive thing, it was given over to the Reserve Bank.

डा० राम मनोहर लोहिया : कितने दिन बाद ?

Shrimati Indira Gandhi: I do not know the date. It was not in my custody and therefore I do not know who handed it over and at what time.

डा० राम मनोहर लोहिया : इस देश को भ्रष्ट कर रखा है ।

Shrimati Indira Gandhi: Naturally I would not keep such an expensive article with myself. The allegation made here is that perhaps the whole of the necklace had not been handed over. This is the allegation made here and this is what I am refuting.

Mr. Speaker: The House now stands adjourned till 11 A.M. on Monday.

17.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 20, 1967/Phalguna 29, 1888 (Saka).